वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ

विषय सूची

अध्याय 01
प्रबंधन और प्रशासन 5

अध्याय 02
सहकारी शिक्षा 7

अध्याय 03
सामान्य सहकारी नीति 46

अध्याय 04
प्रकाशन और जनसंपर्क 50

अध्याय 05
राजभाषा 52

अध्याय 06
अंतरराष्ट्रीय संबंध 55

अध्याय 07
कॉप कनेक्ट 66

अध्याय 08
राष्ट्रीय सहकारी डाटा बैंक (एनसीडीबी) 68

अध्याय 09
राष्ट्रीय सहकारी संसाधन केंद्र (एनसीआरसी) 70

अध्याय 10
एनसीयूआई हाट 76

अध्याय 11
उद्यमिता विकास एवं सहयोग 79

अध्याय 12
राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संस्थानों की संक्षिप्त रिपोर्ट 83

अध्याय 13
राज्य स्तरीय सहकारी संगठनों की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ 105

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की
शासी परिषद के सदस्य
(31.03.2024 तक)

श्री दिलीप संघानी
अध्यक्ष

डॉ. बिजेन्द्र सिंह
उपाध्यक्ष

श्री के. शिवदासन नायर
उपाध्यक्ष

डॉ. चन्द्रपाल सिंहयादव

श्री जी. एच. अमीन

श्री एस.एन. शर्मा

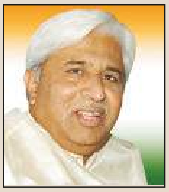

श्री एच.के. पाटिल

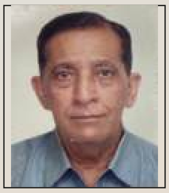

श्री सुखबीर सिंह पँवार

श्री स्वर्ण कमल साहा

डॉ. सुनील कुमार सिंह

श्री कोलियाकोड एन. कृष्णन नायर

श्री मंगल जीत राय

श्री मानवेन्द्र सिंह

श्री मुदित वर्मा

श्री संजीव राजाराम कुसलकर

श्री वी.वी. पंकजाक्षण नायर

श्री प्रदीप कुमार

श्रीमती जीना पोत्संगबाम

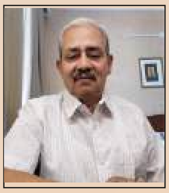

डॉ. उदय जोशी
(सरकारी नामांकित व्यक्ति)

श्रीअरुण सिंह तोमर
(सहयोजित सदस्य)

श्री विशाल सिंह
(सहयोजित सदस्य)

श्री गुरप्रताप सिंह खुशालपुर
(स्थायी विशेष आमंत्रित व्यक्ति)

डॉ. सुधीर महाजन, आईएएस (सेवानिवृत्त)
मुख्य कार्यकारी

अध्याय 01

प्रबंधन और प्रशासन

सदस्यता

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की सदस्यता राष्ट्रीय सहकारी समितियों, राज्य सहकारी संघों, राज्य स्तरीय सहकारी संघों और बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए खुली हैं। वर्ष की शुरुआत में एनसीयूआई की सदस्य संख्या 296 थी। ये सभी संस्थाएं भारतीय सहकारी आंदोलन के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं।

वर्ष 2023-2024 के दौरान निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को एनसीयूआई के सदस्यों के रूप में शामिल किया गया:

1. कृषि विपणन एवं प्रसंस्करण सहकारी संघ लिमिटेड, पंजाब
2. आधार बहु-राज्यीय सहकारी ऋण समिति लिमिटेड, महाराष्ट्र
3. श्री छत्रपति शाहू सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र
4. डॉ. अप्पासाहेब उर्फ एस. आर. पाटिल, जय सिंहपुर-उदगांव सहकारी बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र
5. फार्मट्रेड एग्रो बहु-राज्यीय विपणन सहकारी लिमिटेड, हरियाणा
6. बोरगांव शहरी सहकारी ऋण समिति लिमिटेड, कर्नाटक
7. स्वयं समृद्धि कृषि एवं विपणन बहु-राज्यीय सहकारी समिति लिमिटेड, हैदराबाद
8. देवभूमि एग्रो बहु-राज्यीय सहकारी समिति लिमिटेड, हरिद्वार, उत्तराखंड
9. कर्नाटक राज्य महिला सहकारी संघ लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक

वर्ष के अंत में यानी 31 मार्च, 2024 को एनसीयूआई के सदस्य के रूप में कुल 305 सहकारी संस्थान हैं। इन संस्थाओं का विवरण इस प्रकार है:-

1	राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियाँ	17
2	राज्य सहकारी संघ	29
3	राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ	07
4	राज्य सहकारी गृह निर्माण/आवास वित्त समितियां/संघ	07
5	राज्य शहरी सहकारी बैंक और ऋण समितियां/संघ/फेडरेशन	12
6	अन्य राज्य सहकारी संघ:	
	डेयरी/दूध विपणन	05
	हथकरघा/कताई मिलें	12
	चीनी/गन्ना	03
	मत्स्य पालन	02
	विविध	30
7	राज्य जनजातीय विकास सहकारी/निगम/समितियां/राज्य सहकारी बैंक संघ	02
8	बहु-राज्यीय सहकारी समितियां	125
	कुल	305

प्रबंधन

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के प्रबंधन संगठन

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के प्रबंधन कार्य निम्नलिखित तीन संगठनों द्वारा किए जाते हैं:

1. सामान्य निकाय, जिसमें एनसीयूआई के सदस्य संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

2. शासी परिषद, इसमें पदाधिकारी, निर्वाचित सदस्य और सहयोजित सदस्य शामिल होते हैं।

3. कार्यकारी समिति, एनसीयूआई की शासी परिषद की एक उप-समिति हैं।

सामान्य निकाय

बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 और एनसीयूआई के उप-नियमों के प्रावधानों के अनुसार, एनसीयूआई के सामान्य निकाय में प्रत्येक सदस्य संस्थान से एक प्रतिनिधि शामिल होता है। वर्ष 2022-2023 के लिए वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक दिनांक 21 सितंबर, 2023 को भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के सभागार में हुई थी। इस बैठक के दौरान सामान्य निकाय ने देश में सहकारी आंदोलन के समग्र विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

शासी परिषद (गवर्निंग काउंसिल)

इस वर्ष के दौरान गवर्निंग काउंसिल ने दिनांक 26 अप्रैल, 2023, 28 अगस्त, 2023, 6 दिसंबर, 2023 और 20 फरवरी, 2024 को कुल चार बैठकें कीं। इन बैठकों में परिषद ने सहकारी आंदोलन के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और एनसीयूआई के उपनियमों और उद्देश्यों के अनुरूप गतिविधियों पर कार्य किया। गवर्निंग काउंसिल ने एनसीयूआई के विकास को आगे बढ़ाने और इसके लक्ष्यों का समर्थन करने वाली पहलों के माध्यम से सहकारी आंदोलन के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई निर्णय लिए गए और विस्तृत चर्चा की।

कार्यकारी समिति

इस वर्ष के दौरान एनसीयूआई की कार्यकारी समिति ने 30 जून, 2023 और 21 सितंबर, 2023 को दो बैठकें कीं। समिति ने एनसीयूआई के प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंधन से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श किया।

प्रशासन

इस वर्ष के दौरान डॉ. सुधीर महाजन, आईएएस (सेवानिवृत्त), एनसीयूआई के मुख्य कार्यकारी के पद पर सेवावृत हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों के प्रभारी अधिकारियों की सूची निम्नलिखित हैं:

1	श्रीमती सावित्री सिंह, उप मुख्य कार्यकारी	
2	श्री आशीष द्विवेदी, कार्यकारी निदेशक	प्रशासन और सीईडीसी
3	श्री वेद प्रकाश सेतिया, कार्यकारी निदेशक	सम्पदा, जीसीपी और लीगल (कानूनी) सेल
4	श्री राजीव शर्मा, कार्यकारी निदेशक	परियोजना एवं कूप कनैक्ट
5	श्री रितेश दे, कार्यकारी निदेशक	कार्मिक, कार्यक्रम एवं संपर्क, एनसीडीबी और अध्यक्ष सचिवालय
6	श्री रमेश कौल, निदेशक	बोर्ड, एनसीसीई छात्रावास (दिनांक: 29 फरवरी, 2024 को सेवानिवृत्त)

अध्याय 02

सहकारी शिक्षा

वर्ष 2023-24 के दौरान राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केंद्र की उपलब्धियाँ एवं गतिविधियाँ

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के तत्वावधान में राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केंद्र को सहकारी समितियों के सभी शैक्षिक और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का दायित्व सौंपा गया है। इस केंद्र के प्रशिक्षण कार्यक्रम सामान्य रूप से सहकारी क्षेत्र के सामने आने वाली वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केंद्र, नई दिल्ली ने कुल 134 के लक्ष्य के मुकाबले 215 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इसमें सहकारी शिक्षा और विकास में 12-सप्ताह का डिप्लोमा कार्यक्रम भी शामिल था। प्रशिक्षण में स्वरोजगार सहकारी समितियाँ, महिलाएँ, डेयरी, मत्स्य पालन, उपभोक्ता और सेवा सहकारी समितियाँ जैसे महत्वपूर्ण और उभरते क्षेत्र शामिल थे। इन कार्यक्रमों के तहत विभिन्न राज्यों के कुल 8,646 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

प्रशिक्षण केंद्र द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिनमें सहकारी समितियों के हजारों पदाधिकारियों, सदस्यों और कर्मचारियों, विभिन्न विश्वविद्यालयों के संकायों, सहकारी प्रशिक्षण केंद्रों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को शिक्षित किया गया। श्रम, मत्स्य पालन, आदिवासी सहकारी समितियों, हथकरघा और हस्तशिल्प जैसे अपेक्षाकृत कमजोर क्षेत्रों को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। प्रशिक्षित कुल प्रतिभागियों में से 1,229 एससी श्रेणी से, 670 एसटी श्रेणी से, 2,624 महिलाएं, 2,910 ओबीसी, 3,394 'अन्य और ई डब्ल्यू एस' श्रेणियों में थे और इसके अतिरिक्त 816 प्रतिभागी पूर्वोत्तर क्षेत्र से भी थे। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, सोनीपत, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयूएच) और गुजरात विद्यापीठ के ग्रामीण प्रबंधन अध्ययन केंद्र के छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को वर्ष के दौरान काफी गति मिली। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य महिला सहकारी समितियों, संयुक्त खेती, मत्स्य पालन, श्रम, डेयरी, बागवानी, आवास, जनजातीय, युवा सहकारी समितियों, विपणन, सेवा सहकारी समितियों और वानिकी सहित विविध सहकारी क्षेत्रों के सदस्यों को प्रशिक्षित करना था।

प्रत्येक वर्ष ही फीडबैक, सुझाव और नीतिगत माहौल में बदलावों के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है और तदनुसार उन्हें समायोजित किया जाता है। एनसीसीई प्रशिक्षण सामग्री को आगे बढ़ाने और आधुनिक बनाने हेतु इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने और सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण में पाठ्यक्रमों को बढ़ाने के लिए सुधारों की सिफारिश करने के लिए प्रतिबद्ध है।

नई पहल:

1. वर्ष 2023-24 के दौरान केंद्र ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया। महिलाओं के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के सहयोग से दो बार आयोजित किया गया था। यह दो सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम एनसीसीई, नई दिल्ली में हुआ जबकि व्यावहारिक प्रशिक्षण एनएसआईसी में आयोजित किया गया।

2. इस वर्ष युवाओं के लिए "सहकारी समिति के गठन" पर एक नया पांच दिवसीय कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से 67 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

3. एनसीयूआई ने पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों में संयुक्त रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके किसानों और सहकारी समितियों के हित हेतु एग्रीफेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। किसानों, एफपीओ और पैक्स को लक्षित करने वाले इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए, एनसीयूआई एग्रीफेड को संसाधन व्यक्ति और अध्ययन सामग्री प्रदान करेगा। एग्रीफेड इन संसाधनों का उपयोग चंडीगढ़ में अपने प्रशिक्षण केंद्र में प्रभावी प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने के लिए करेगा।

वर्ष 2023-24 के दौरान एनसीसीई, नई दिल्ली में आयोजित कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक झलक इस प्रकार हैं:-

देश के राज्य एवं जिला सहकारी संघों और जेसीटीसी के सहकारी शिक्षा कर्मियों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन (दिनांक: 07-11 अगस्त 2023,

अनुकूलन करने में उनकी सहायता करने तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को व्यवस्थित और पेशेवर ढंग से क्रियान्वित करने में सहायता करने के लिए तैयार किया गया है।

इस कार्यक्रम की शुरुआत दिनांक 7 अगस्त, 2023 को हुई। इसमें अंडमान और निकोबार राज्य सहकारी संघ, असम राज्य सहकारी संघ, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ, जिला सहकारी संघ मर्यादित (रतलाम, मध्य प्रदेश), पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी संघ, सिक्किम राज्य सहकारी संघ, महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ, कर्नाटक राज्य सहकारी संघ, तेलंगाना राज्य सहकारी संघ, गुजरात राज्य सहकारी संघ और श्री रावलनाथ सहकारी आवास समिति लिमिटेड (महाराष्ट्र) के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमे कुल मिलाकर 10 राज्यों के 39 सहकारी शिक्षा कर्मियों और प्रशिक्षकों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

इसमे पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में प्रतिभागियों के लिए दिनांक 10 अगस्त, 2023 को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) का अध्ययन दौरा आयोजित किया गया। सहकारी विकास में एक प्रमुख संगठन एनसीडीसी सहकारी व्यवसायों के विकास के लिए वित्तीय सहायता और विभिन्न योजनाएँ प्रदान करता है। इस दौरे ने प्रतिभागियों को एनसीडीसी की परियोजनाओं, योजनाओं और गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान की।

कृषि विपणन पर नेतृत्व विकास कार्यक्रम का आयोजन (दिनांक: 16 -18 अगस्त, 2023): एनसीसीई (एनसीयूआई) ने 16 से 18 अगस्त, 2023 तक देश के कृषि विपणन सहकारी समितियों के अध्यक्षों और निदेशकों के लिए तीन दिवसीय नेतृत्व विकास कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, नागालैंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल और अन्य राज्यों से कुल 44 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। श्रीमति सावित्री सिंह, उप मुख्य कार्यकारी ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और पाठ्यक्रम के बारे में बताया। सहकारिता के विशेषज्ञ संकाय सदस्यों की एक टीम ने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया और केंद्रीय भंडार का अध्ययन दौरा भी किया। नेतृत्व विकास कार्यक्रम का समापन दिनांक 18 अगस्त, 2023 को हुआ।

एग्रीफेड ने एनसीसीई (एनसीयूआई) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर:- दिनांक 17 अगस्त, 2023 को भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) ने एग्रीफेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर एनसीयूआई, मुख्य कार्यकारी डॉ. सुधीर महाजन और एग्रीफेड अध्यक्ष श्री गुरप्रताप सिंह द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस हस्ताक्षर समारोह में दिलीप संघाणी, अध्यक्ष, (एनसीयूआई और इफको), डॉ. बिजेंद्र सिंह, अध्यक्ष, नेफेड, और श्रीमति सावित्री सिंह, उप मुख्य कार्यकारी ने हिस्सा लिया।

यह समझौता ज्ञापन पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों में संयुक्त रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके किसानों और सहकारी समितियों की भलाई के उद्देश्य से हस्ताक्षरित किया गया। इन प्रशिक्षणों के लिए एनसीयूआई एग्रीफेड को संसाधन व्यक्ति और अध्ययन सामग्री प्रदान करेगा। एग्रीफेड इन संसाधनों का उपयोग चंडीगढ़ में अपने प्रशिक्षण केंद्र में प्रभावी प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने के लिए करेगा।

भारतीय विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के संकाय के लिए सहकारी नीति और विकास पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (दिनांक: 21-25 अगस्त, 2023)

एनसीसीई, एनसीयूआई ने 21-25 अगस्त, 2023 तक "सहकारी नीति और विकास" पर एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम ने सहकारी नीति की अपनी समझ को बढ़ाने के लिए कुल 40 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस पाठ्यक्रम का समापन दिनांक 25 अगस्त, 2023 को एक समापन सत्र के साथ हुआ जिसके दौरान एनसीयूआई उप मुख्य कार्यकारी ने सहकारी ज्ञान को आगे बढ़ाने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया और विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में और एनसीयूआई से निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया। इसमे प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त अंतर्दृष्टि को दर्शाते हुए प्रतिक्रिया दी और अपने अनुभव भी साझा किए।

भारतीय आवास सहकारी समितियों के अध्यक्षों और निदेशकों के लिए तीन दिवसीय नेतृत्व विकास कार्यक्रम (दिनांक: 11-13 सितंबर, 2023)

एनसीसीई ने सितंबर 2023 को भारतीय आवास सहकारी समितियों के अध्यक्षों और निदेशकों के लिए तीन दिवसीय नेतृत्व विकास कार्यक्रम आयोजित किया। दिनांक 11 से 13 सितंबर, 2023 तक आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर के विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 58 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम की शुरुआत एनसीयूआई उप मुख्य कार्यकारी श्रीमती सावित्री सिंह के उद्घाटन भाषण से हुई। इसमे प्रतिभागियों को पाठ्यक्रम के उद्देश्यों और संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ (एनसीएचएफ), प्रबंध निदेशक श्री एन.एस. मेहरा ने भी आवास सहकारी प्रबंधन के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

अमरेली जिला सहकारी संघ के लिए तीन दिवसीय नेतृत्व विकास कार्यक्रम (दिनांक 13 - 15 सितंबर, 2023)

एनसीसीई ने अमरेली जिला सहकारी संघ के 41 प्रतिभागियों के लिए 13 से 15 सितंबर 2023 तक तीन दिवसीय नेतृत्व विकास कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया। अमरेली जिला सहकारी संघ के अध्यक्ष श्री मनीष संघाणी ने जमीनी स्तर के नेताओं को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से ऐसे प्रभावशाली कार्यक्रमों के आयोजन में एनसीसीई के प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया और उनकी सराहना की। इस कार्यक्रम का समापन एनसीयूआई उप मुख्य कार्यकारी श्रीमती सावित्री सिंह और श्री मनीष संघाणी द्वारा प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित करने के साथ हुआ। इस कार्यक्रम में स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने में सहकारी शिक्षा के महत्व पर जोर दिया गया।

केरल कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों का एनसीयूआई का अध्ययन दौरा (18 सितंबर 2023)

दिनांक 18 सितंबर, 2023 को केरल कृषि विश्वविद्यालय के 40 छात्र, दो संकाय सदस्यों के साथ अपने बीएससी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) का दौरा किया। इस यात्रा का उद्देश्य छात्रों को सहकारी समितियों के कामकाज का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना और सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने में एनसीयूआई की भूमिका को समझना था। श्री राजीव शर्मा, कार्यकारी निदेशक ने सहकारी शिक्षा, नए सहकारिता मंत्रालय की भूमिका और सहकारी समितियों के मूल सिद्धांतों और मूल्यों पर जानकारी प्रदान की। अपनी यात्रा के दौरान छात्रों ने एनसीयूआई हाट और इनक्यूबेशन सेंटर के बारें में भी जानकारी प्राप्त की।

मत्स्य सहकारी समितियों के अध्यक्षों और निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम (18 - 20 सितंबर, 2023)

राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केंद्र (एनसीसीई), नई दिल्ली ने 18 से 20 सितंबर 2023 तक मत्स्य सहकारी समितियों के अध्यक्षों और निदेशकों के लिए तीन दिवसीय नेतृत्व विकास कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा, राजस्थान, असम और अन्य सहित विभिन्न राज्यों से कुल 38 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

सहकारी शिक्षा एवं विकास में 12-सप्ताह का डिप्लोमा कार्यक्रम (3 अक्टूबर 2023)

दिनांक 03 अक्टूबर, 2023 को सहकारी शिक्षा एवं विकास में 12-सप्ताह का डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू हुआ जिसमें मणिपुर, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, नागालैंड और असम जैसे विविध क्षेत्रों से 35 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस उद्घाटन सत्र में श्रीमति इंदरप्रीत कौर, सहायक निदेशक ने सभी उपस्थित लोगों का गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद एनसीयूआई कार्यकारी निदेशक श्री राजीव शर्मा ने सहकारिता प्रयासों को रेखांकित करने वाले महत्वपूर्ण सिद्धांतों और मूल्यों के बारे में प्रतिभागियों का मार्गदर्शन करते हुए विस्तृत जानकारी दी।

एनसीयूआई उप मुख्य कार्यकारी श्रीमती सावित्री सिंह ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और सत्रों में शामिल किए जाने वाले प्रमुख विषयों पर प्रकाश डालते हुए पाठ्यक्रम संरचना के बारें में जानकारी दी। सभी प्रतिभागियों के समूह फोटो लेने के बाद एनसीयूआई मुख्य कार्यकारी डॉ. सुधीर महाजन, आईएएस (सेवानिवृत्त) ने प्रतिभागियों के साथ बातचीत की और उनकी समितियों के संचालन, उत्पादों और प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग को बेहतर बनाने के बारे में जानकारी दी।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहकारी समितियों के लिए तीन दिवसीय नेतृत्व विकास कार्यक्रम (28-30 नवंबर 2023)

देश की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहकारी समितियों के अध्यक्षों और निदेशकों के लिए तीन दिवसीय नेतृत्व विकास कार्यक्रम (एलडीपी) दिनांक 28-30 नवंबर, 2023 को एनसीसीई, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों की सहकारी समितियों के कुल 43 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

दिनांक 15 से 17 नवंबर, 2023 तक एनसीसीई, नई दिल्ली में तीन दिवसीय नेतृत्व विकास कार्यक्रम (एलडीपी) आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नागालैंड, बिहार, असम, जम्मू और कश्मीर जैसे राज्यों की सहकारी समितियों के कुल 37 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

एनसीसीई (एनसीयूआई) ने 5 से 7 दिसंबर, 2023 तक भारत में सहकारी समितियों के अध्यक्षों और महिला निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम (एलडीपी) का आयोजन किया।

इस कार्यक्रम में महिला सहकारी समितियों के लिए वित्तीय प्रबंधन और लेखांकन, सहकारी समितियों के विकास में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का उपयोग, महिला सहकारी समितियों के लिए व्यावसायिक परियोजना नियोजन और महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए माइक्रोफाइनेंस प्रबंधन पर सत्र शामिल थे। इसमे 30 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसमे छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व किया। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित करने के साथ कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

एनसीसीई ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, नई दिल्ली के सहयोग से 11 से 22 दिसंबर 2023 तक

यह कार्यक्रम किया। यह दो सप्ताह का 'उद्यमिता विकास कार्यक्रम' था जो विशेष रुप से कौशल विकास हेतु महिलाओं के लिए तैयार किया गया था। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़, सिक्किम, मणिपुर बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की कुल पच्चीस महिलाओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन श्रीमति सावित्री सिंह, उप मुख्य कार्यकारी, जीना पोत्संगम, गवर्निंग काउंसिल सदस्य, एनसीयूआई और एनएसआईसी के सीनियर फैकल्टी श्री सुशांत शर्मा ने किया। इस कार्यक्रम का समापन दिनांक 22 दिसंबर, 2023 को हुआ।

एनसीसीई ने भारत के राज्य/जिला सहकारी संघों के अध्यक्षों और निदेशकों के लिए दिनांक 13 से 15 दिसंबर 2023 तक

एनसीसीई, नई दिल्ली में तीन दिवसीय नेतृत्व विकास कार्यक्रम (एलडीपी) का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कृभको का अध्ययन दौरा भी आयोजित किया गया।

एनसीसीई ने 3 अक्टूबर से 23 दिसंबर, 2023 तक 'सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण' में 12 सप्ताह का डिप्लोमा कोर्स आयोजित किया।

इस कार्यक्रम में 32 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रत्येक प्रतिभागी ने चर्चाओं में जो उत्साह और समर्पण दिखाया, उसे देखना प्रेरणादायक था जिससे एक जीवंत और आकर्षक शिक्षण वातावरण बना। उप मुख्य कार्यकारी श्रीमती सावित्री सिंह ने प्रत्येक प्रतिभागी को प्रमाण पत्र वितरित किया।

एनसीसीई, नई दिल्ली ने 29 जनवरी से 2 फरवरी, 2024 तक "सहकारी समितियों के गठन" पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

इसमे नए छात्रों, युवाओं और सहकारी प्रशिक्षकों को सहकारी समितियों की स्थापना और प्रबंधन के लिए आवश्यक जानकारी दी गई। इस समापन समारोह में सहकारिता मंत्रालय, निदेशक श्री कपिल मीना, आईएएस और उप मुख्य कार्यकारी श्रीमती सावित्री सिंह ने भाग लिया और सहकारी प्रथाओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी दी। इस कार्यक्रम के सफल समापन उपरांत कुल 67 प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए।

एनसीयूआई सहकारी शिक्षा क्षेत्र परियोजनाओं की महिला मोबिलाइजर्स और एलसीईआई के लिए तीन दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स दिनांक 03 से 5 जनवरी, 2024 तक एनसीसीई में आयोजित किया गया।

इस कार्यक्रम में डॉ. राधिका महाजन और डॉ. वी.के. दुबे ने सहकारी विकास के लिए भारत सरकार की नई पहलों पर चर्चा की और श्री नवीन ने प्रेरक सफलता की कहानियों और सहकारी मॉडल की सफलता में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों को साझा किया।

सहकारी कानून और प्रथाओं' पर सर्टिफिकेट कोर्स दिनांक 08 से 19 जनवरी, 2024 तक आयोजित किया गया।

इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से 18 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित प्रोफेसरों ने इस नेतृत्व कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। इन सत्रों में नवीनतम संशोधन अधिनियम एमएससीएस 2023, नई सहकारी नीति, राज्य अधिनियम, मध्यस्थता मामले, विवाद समाधान और सोसायटी पंजीकरण सहित कई विषयों को शामिल किया गया। इसमे प्रतिभागियों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासित एक लिखित परीक्षा भी शामिल थी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रतिभागी को एक लिखित असाइनमेंट के लिए एक विषय दिया गया था और तदुपरान्त उसे सावधानीपूर्वक ग्रेड भी किया गया था। इस समारोह में उप मुख्य कार्यकारी श्रीमती सावित्री सिंह ने सभी सफल प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए।

एनसीसीई ने 22 से 24 जनवरी 2024 तक 'कृषि विपणन सहकारी समितियों' के लिए तीन दिवसीय नेतृत्व विकास कार्यक्रम आयोजित किया।

इस कार्यक्रम में मानव संसाधन प्रबंधन, सहकारी व्यवसाय विकास और वित्तीय प्रबंधन एवं लेखांकन के लिए सोशल मीडिया और प्रौद्योगिकी का उपयोग जैसे विभिन्न विषयों को शामिल किया गया। इस दौरान केंद्रीय भंडार का एक अध्ययन दौरा भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का समापन दिनांक 24 जनवरी,2024 को एनसीयूआई उप मुख्य कार्यकारी श्रीमती सावित्री सिंह द्वारा सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित करने के साथ हुआ।

एडवांस्ड एमएस ऑफिस और कंप्यूटर ऑपरेशन पर चार सप्ताह का सर्टिफिकेट कोर्स: दिनांक 05 फरवरी, 2024 को एडवांस्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और कंप्यूटर ऑपरेशन पर चार सप्ताह का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू हुआ।

इसका उद्देश्य सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में प्रतिभागियों के कौशल को बढ़ाना था। इस कोर्स में विभिन्न राज्यों से 31 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एआई टूल्स और गूगल फॉर्म क्रिएशन के बारें में बताया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन एनसीयूआई उप मुख्य कार्यकारी श्रीमती साविंत्री सिंह ने किया और उन्होने आज की पेशेवर दुनिया में कंप्यूटर साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डाला। यह कार्यक्रम 29 फरवरी, 2024 को संपन्न हुआ और इसमे प्रतिभागियों को करियर में उन्नति और कार्यालय दक्षता के लिए व्यावहारिक जानकारी दी।

एनसीसीई ने 12 से 14 फरवरी, 2024 तक मत्स्य सहकारी समितियों के लिए तीन दिवसीय नेतृत्व विकास कार्यक्रम आयोजित किया।

इस कार्यक्रम में सहकारी प्रबंधन के लिए मानव संसाधन प्रबंधन और संचार, सहकारिता मंत्रालय, नई सहकारी नीति, एमएससीएस अधिनियम और सहकारी समितियों पर उनके प्रभाव और वित्तीय प्रबंधन और लेखांकन जैसे विषयों पर अनुभवी संकाय द्वारा सत्र शामिल थे। इस कार्यक्रम का समापन 14 फरवरी को एनसीयूआई उप मुख्य कार्यकारी श्रीमती साविंत्री सिंह द्वारा सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित करने के साथ हुआ।

National Cooperative Union of India
National Centre for Cooperative Education
Leadership Development Programme for Chairman/Director of IFFDC (PFFCS)
From 19 – 21 February, 2024

दिनांक 19 से 21 फरवरी, 2024 तक एनसीसीई ने भारतीय कृषि वानिकी विकास सहकारी लिमिटेड (आईएफएफडीसी) के अध्यक्षों, निदेशकों और सचिवों के लिए तीन दिवसीय नेतृत्व विकास कार्यक्रम का आयोजन किया।

इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के 23 प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी देखी गई और इसमें एमएससीएस अधिनियम, सहकारी नीतियां, सरकारी पहल, नेतृत्व रणनीति, वित्तीय प्रबंधन और साइबर सुरक्षा जैसे आवश्यक विषयों को शामिल किया गया। इस कार्यक्रम ने सहकारी शिक्षा को बढ़ावा दिया और आईएफएफडीसी के अधिकारियों के लिए व्यावहारिक समाधान प्रदान किए गए। दिनांक 21 फरवरी को उप मुख्य कार्यकारी श्रीमती सावित्री सिंह की अध्यक्षता में समापन समारोह में व्यावहारिक फीडबैक सत्र और प्रमाण पत्र वितरण भी शामिल था।

एनसीसीई के सहयोग से कलबुर्गी जिला शोहारदा सहकारी संघ लिमिटेड ने दिनांक 24-26 फरवरी, 2024 तक कमलापुर, कलबुर्गी में प्रबंध निदेशकों, अध्यक्षों और निदेशक मंडल हेतु तीन दिवसीय नेतृत्व विकास कार्यक्रम आयोजित किया।

इस कार्यक्रम का उद्घाटन शोहारदा सहकारी संघ, बैंगलोर के प्रबंध निदेशक श्री श्रवणगौड़ा पाटिल ने किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों में श्री सिद्धरामप्पा होर्से, निदेशक, श्री महेश पाटिल, निदेशक, श्री एसएस पाटिल, निदेशक और डॉ ए.आर. श्रीनाथ पूर्व निदेशक इत्यादि शामिल थे। इस कार्यक्रम में क्रेडिट, मार्केटिंग, उपभोक्ता, महिला और डेयरी क्षेत्रों सहित शोहारदा सहकारी संघ के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 35 से 40 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सभी प्रतिभागियों ने कार्यक्रम के सफल समापन को सुनिश्चित करने में एनसीसीई के समर्थन और प्रोत्साहन के लिए भी हार्दिक धन्यवाद दिया।.

दिनांक 04 मार्च, 2024 को कौशल विकास के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के सहयोग से एनसीसीई का दो सप्ताह का उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुरू हुआ।

इस कार्यक्रम में असम, मणिपुर, बिहार, छत्तीसगढ़ और गुजरात से कुल 34 प्रतिभागी शामिल हुए। उद्घाटन समारोह में श्रीमती सावित्री सिंह, उप मुख्य कार्यकारी, एनएसआईसी मुख्य प्रबंधक सुश्री मधु मालती और एनएसआईसी उप प्रबंधक श्रीमती विजयता गौतम भी शामिल हुईं। श्रीमती सिंह ने पाठ्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डाला जबकि श्रीमती मालती ने उन लाभों पर भी जोर दिया जो प्रतिभागी अपने उद्यमशील उपक्रमों को शुरू करने के लिए प्राप्त कर सकते हैं। पहले दिन के सत्र का संचालन श्री संजय वर्मा, निदेशक, एनसीयूआई द्वारा किया गया जिन्होंने सहकारी अवधारणा और उद्यमिता में एनसीयूआई की भूमिका पर चर्चा की। इसके अतिरिक्त उन्होने इस पर प्रकाश डाला कि एनएसआईसी और एनसीयूआई के बीच इस सहयोगात्मक प्रयास का उद्देश्य महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है तथा उन्हें आर्थिक विकास में सार्थक योगदान देने के लिए सशक्त बनाना है। यह कार्यक्रम उन महिला उद्यमियों को विकसित करने के लिए है जो अपने समुदायों पर भी प्रभाव डाल सकती हैं।

राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केंद्र (एनसीसीई) नई दिल्ली में दिनांक 11 मार्च, 2024 को सहकारी कानून और प्रथाओं पर दो सप्ताह का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शुरू हुआ। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को सहकारी कानून और प्रथाओं में आवश्यक ज्ञान और कौशल से युक्त करना है।

इस कार्यक्रम में गुजकोमासोल, गुजरात के नव नियुक्त तीस प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन श्रीमती सावित्री सिंह, उप मुख्य कार्यकारी ने किया और सभी उपस्थित लोगों को सहकारिता के बारें में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। जीजीएसआईपीयू प्रोफेसर डॉ अमर पाल सिंह और डॉ राकेश कुमार भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। डॉ अमर पाल सिंह ने अपने संबोधन में पाठ्यक्रम के महत्व को रेखांकित किया और इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण विषयों के बारें में विस्तार से बताया।

दिनांक 26 मार्च से 28 मार्च, 2024 तक राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केंद्र (एनसीसीई), नई दिल्ली ने सीएसआरएम, गुजरात विद्यापीठ में सहकारी प्रबंधन में डिप्लोमा करने वाले छात्रों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

इस कार्यक्रम में तीन संकाय सदस्यों के साथ कुल 23 छात्रों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम 28 मार्च, 2024 को संपन्न हुआ। सभी का मत था कि इस तरह के कार्यक्रम ज्ञान, सहयोग और व्यावहारिक अंतर्दृष्टि से निस्संदेह सहकारी क्षेत्र के भविष्य के नेताओं को लाभान्वित करेगी।

एनसीसीई ने 27 मार्च से 29 मार्च, 2024 तक राष्ट्रीय ग्रामीण बैंकिंग संस्थान (एनआईआरबी), बेंगलुरु में शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम का आयोजन किया।

इस कार्यक्रम में ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के 24 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उनको उभरते बैंकिंग परिदृश्य के लिए आवश्यक कौशल से युक्त करना था। इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में एनसीसीई के कार्यक्रम समन्वयक श्री हेमंत यादव, श्री योगेश शर्मा (सीईओ, नेफकॉब), श्री के. गणेश (सेवानिवृत्त जीएम आरबीआई), श्री वेणु सलागुंडी (निदेशक और कार्यक्रम समन्वयक, एनआईआरबी) और श्री अरुण एम. तल्लूर (निदेशक, एनआईआरबी) सहित गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति थी। यह कार्यक्रम दिनांक 29 मार्च, 2024 को समाप्त हुआ। इस कार्यक्रम ने निदेशकों को अपने शहरी सहकारी बैंकों को और अधिक सफल एवं सशक्त बनाने के लिए प्रेरित किया।

राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केंद्र, नई दिल्ली
वर्ष 2023-2024 के दौरान एनसीसीई द्वारा आयोजित राज्यवार कार्यक्रम

राज्य

(1) कार्यक्रमों की संख्या

(2) प्रतिभागियों की संख्या

पूर्वी क्षेत्र	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	6	167
बिहार	2	90
ओडिसा	1	37
पश्चिम बंगाल	7	193
झारखंड	0	0
उत्तर क्षेत्र		
सम्पूर्ण भारत	50	1849
जम्मू	4	171
हरियाणा	10	412
पंजाब	11	470
उत्तराखंड	7	285
हिमाचल प्रदेश	1	26
राजस्थान	1	36
उत्तर प्रदेश	3	111
लद्दाख	1	41

दक्षिण क्षेत्र	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
तेलंगाना	3	111
आंध्र प्रदेश	4	218
केरल	1	30
कर्नाटक	11	446
लक्षद्वीप	0	0
तमिलनाडु	0	0
पश्चिम क्षेत्र		
मध्य प्रदेश	44	1969
छत्तीसगढ़	2	102
गोवा	2	76
गुजरात	10	430
महाराष्ट्र दमन & दीव	12	514
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र	17	1680
नई दिल्ली	4	157
अंतर्राष्ट्रीय	1	26
	215	**8646**

राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केंद्र, नई दिल्ली
वर्ष 2023-2024 के दौरान एनसीसीई द्वारा क्षेत्रवार आयोजित कार्यक्रमों का ब्यौरा

क्र.	स्थल	कार्यक्रमों की संख्या	क्र.	स्थल	कार्यक्रमों की संख्या
	सहकारी शिक्षा				
1	एआरडीबी	1	19	मुर्गी पालन	2
2	कृषि	9	20	एससी/एसटी सहकारी समितियांए	3
3	उपभोक्ता	1	21	ससीबी/डीसीसीबी	0
4	सहकारी शिक्षण	43	22	एससीयू/डीसीयू	2
5	सहकारी प्रबंधन	0	23	सेवा सहकारी समितियां	3
6	डेरीफार्म	19	24	चीनी	3
7	वानिकी	5	25	पर्यटन	0
8	उर्वरक	5	26	जनजातीय	2
9	मत्स्य पालन	20	27	शहरी ऋण	0
10	हथकरघा/ हस्तशिल्प	5	28	ऋण	12
11	बागवानी	0	29	महिला सहकारिताएं	26
12	आवास	2	30	युवा सहकारी समितियां	2
13	संयुक्त खेती	1	31	आईटी	3
14	श्रम	9	32	पैक्स	25
15	विपणन	2	33	सहकारी नियम	4
16	एमपीसीएस	0			
17	बहु-राज्यीय सहकारी समितियां	6			
18	एनसीयूआई सहकारी शिक्षा क्षेत्र परियोजना	0			215

राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केंद्र वर्ष के दौरान आयोजित कार्यक्रम (अप्रैल, 2023 से मार्च, 2024 तक)											
क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	कुल प्रतिभागी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	महिला	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य	पूर्वोत्तर	दिनांक	क्षेत्र	कार्यक्रम का स्थान
1	राज्य और जिला सहकारी संघ के सहकारी शिक्षा कार्मिकों के लिए प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम	50	2	1	9	19	28	6	10-14 अप्रैल, 23	सहकार शिक्षा	सम्पूर्ण भारत
2	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के श्रम सहकारी समितियों के अध्यक्षों और निदेशकों हेतु नेतृत्व विकास कार्यक्रम	21	0	0	21	1	0	0	11-13 अप्रैल, 23	श्रम	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
3	सहकारी कानून एवं व्यवहार पर सर्टिफिकेट कोर्स	18	2	0	3	5	11	0	17-29 अप्रैल, 23	सहकारी कानून	भारत
4	भारतीय सहकारी समितियों के अध्यक्षों और महिला निदेशकों हेतु नेतृत्व विकास कार्यक्रम	43	9	4	43	16	13	6	18-20 अप्रैल, 23	महिला समिति	भारत
5	गुजरात के शहरी सहकारी बैंकों और टी/सी सोसायटियों के अध्यक्षों और निदेशकों के लिए एलडीपी	29	0	0	12	1	28	0	24-26 अप्रैल, 23	ऋण	गुजरात
6	हरियाणा (पंचकूला) के डेयरी सहकारी समितियों के अध्यक्षों और निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	50	8	0	26	20	22	0	26-28 अप्रैल, 23	डेरी	हरियाणा
7	भारतीय मत्स्य सहकारी समितियों के अध्यक्षों और निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	46	5	4	10	18	18	6	1-3 मई, 2023	मत्स्य पालन	भारत
8	सेमिनार,संगोष्ठी ,सम्मेलन,प्रशिक्षण,कार्यशालाएं,पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	31	6	1	5	6	18	0	2 मई, 2023	सहकार शिक्षा	भारत
9	छतीसगढ़ के पैक्स के प्रबंधकों और सचिवों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम	52	1	2	1	45	3	0	2-6 मई, 2023	पैक्स	छतीसगढ़
10	सेमिनार/संगोष्ठी/सम्मेलन/प्रशिक्षण/कार्यशालाएं/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	34	7	3	5	3	21	0	3 मई, 2023	सहकार शिक्षा	भारत
11	सेमिनार/संगोष्ठी/सम्मेलन/प्रशिक्षण/कार्यशालाएं/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	31	6	1	6	9	15	0	4 मई, 2023	सहकार शिक्षा	भारत
12	भारतीय सहकारी समितियों के अध्यक्षों/महिला निदेशकों हेतु नेतृत्व विकास कार्यक्रम	38	12	0	38	11	14	0	8-10 मई, 23	महिला समिति	भारत
13	इफको फूलपुर, इलाहाबाद (यूपी) के अधिकारियों हेतु सहकारिता एवं सहकारी प्रबंधन पर कार्यक्रम	41	10	0	2	16	13	0	10-11 मई, 2023	उर्वरक	उतार प्रदेश
14	हरियाणा के पैक्स के प्रबंधकों और सचिवों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम	50	3	0	0	5	42	0	15-19 मई, 23	सहकारी शिक्षा	हरियाणा
15	राज्य और जिला संघ के सहकारी शिक्षा कार्मिकों के लिए प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम	50	5	0	2	8	35	0	15-19 मई, 23	सहकारी शिक्षा	महाराष्ट्र
16	बहु-राज्यीय सहकारी समितियों के अध्यक्षों अरु निदेशकों हेतु नेतृत्व विकास कार्यक्रम	34	8	3	0	9	14	2	16 - 18 मई, 23	बहु राज्य सहकारी समितियां	भारत
17	सिक्किम के स्वरोजगार सहकारी समितियों के अध्यक्षों और निदेशकों हेतु नेतृत्व विकास कार्यक्रम	50	5	11	50	12	22	50	17-19 मई, 23	सेवा सहकारी समितियां	पूर्वोत्तर राज्य
18	शहरी सहकारी बैंकों के अध्यक्षों और निदेशकों हेतु नेतृत्व विकास कार्यक्रम	25	0	1	7	16	8	0	17-19 मई, 23	ऋण	कर्नाटक
19	असम (नागांव) के मत्स्य सहकारी समितियों के अध्यक्षों और निदेशकों हेतु नेतृत्व विकास कार्यक्रम	30	17	8	0	4	1	30	24-26 मई, 23	मत्स्य पालन	पूर्वोत्तर राज्य
20	भारतीय उपभोक्ता सहकारी समितियों के अध्यक्षों और निदेशकों हेतु नेतृत्व विकास कार्यक्रम	54	11	2	11	4	35	0	29-31 मई, 23	उपभोक्ता	भारत
21	वित्तीय लेखांकन और कराधान पर प्रमाणपत्र कार्यक्रम	24	2	0	7	6	16	5	1-28 जून, 2023	सहकारी शिक्षा	भारत

22	इफको आंवला, बरेली (यूपी) के अधिकारियों के लिए सहकारिता एवं सहकारी प्रबंधन पर कार्यक्रम	40	6	0	1	13	20	0	5-6 जून, 2023	उर्वरक	उतार प्रदेश
23	अमरेली जिला सहकारी संघ के अध्यक्षों और निदेशकों हेतु नेतृत्व विकास कार्यक्रम	41	0	0	41	13	28	0	7-9 जून, 2023	सहकारी शिक्षा	गुजरात
24	नेपाल के अध्यक्षों और निदेशकों हेतु नेतृत्व विकास कार्यक्रम	26	0	0	7	0	19	0	13-15 जून, 2023	सहकारी शिक्षा	अंतरराष्ट्रीय
25	लद्दाख के लूम्स अध्यक्षों और निदेशकों हेतु नेतृत्व विकास कार्यक्रम	41	0	40	41	0	1	0	20-22 जून, 2023	महिला समिति	लद्दाख
26	महाराष्ट्र के मत्स्य सहकारी समितियों के अध्यक्षों और निदेशकों हेतु नेतृत्व विकास कार्यक्रम	51	3	0	7	29	12	0	21-23 जून, 2023	मत्स्य पालन	महाराष्ट्र
27	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सहकारी समितियों के अध्यक्षों और महिला निदेशकों हेतु नेतृत्व विकास कार्यक्रम	27	0	0	27	3	24	0	22-24 जून, 2023	महिला समिति	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
28	पंजाब के उर्वरक सहकारी समितियों के निदेशकों/किसानों/सदस्यों हेतु नेतृत्व विकास कार्यक्रम	44	3	0	0	4	37	0	27-29 जून, 2023	सहकारी शिक्षा	पंजाब
29	महाराष्ट्र (उस्मानाबाद) के मत्स्य सहकारी समितियों के अध्यक्षों और निदेशकों हेतु नेतृत्व विकास कार्यक्रम	40	25	0	19	9	15	0	3-5 जुलाई, 2023	मत्स्य पालन	महाराष्ट्र
30	असम (नलबाड़ी) की सहकारी समितियों के अध्यक्षों और महिला निदेशकों हेतु नेतृत्व विकास कार्यक्रम	40	3	1	40	4	32	40	4-6 जुलाई, 2023	महिला समिति	पूर्वोत्तर राज्य
31	पंजाब के मत्स्य सहकारी समितियों के निदेशकों/सदस्यों हेतु नेतृत्व विकास कार्यक्रम	40	10	0	0	2	28	0	4-6 जुलाई, 2023	मत्स्य पालन	पंजाब
32	महाराष्ट्र (वाशी) की मत्स्यपालन महिला सहकारी समितियों के अध्यक्षों और निदेशकों हेतु नेतृत्व विकास कार्यक्रम	40	0	0	40	0	0	0	7-9 जुलाई, 2023	महिला समिति	महाराष्ट्र
33	भारतीय मत्स्य सहकारी समितियों के अध्यक्षों और निदेशकों हेतु नेतृत्व विकास कार्यक्रम	45	10	3	8	30	5	5	10-12 जुलाई, 2023	मत्स्य पालन	भारत
34	मध्य प्रदेश (खंडवा) की स्वरोजगार सहकारी समितियों के अध्यक्षों और महिला निदेशकों हेतु नेतृत्व विकास कार्यक्रम	51	10	13	51	16	11	0	10-12 जुलाई, 2023	महिला समिति	मध्य प्रदेश
35	एनसीयूआई सहकारी शिक्षा क्षेत्र परियोजनाओं के परियोजना अधिकारियों / एफजीआई के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	33	1	2	9	7	22	2	11-13 जुलाई, 2023	सहकारी शिक्षा	भारत
36	पंजाब के श्रम सहकारी समितियों के अध्यक्षोंऔर निदेशकों हेतु नेतृत्व विकास कार्यक्रम	43	6	0	0	3	34	0	12-14 जुलाई, 2023	ऋण	पंजाब
37	महाराष्ट्र (उस्मानाबाद) के मत्स्य सहकारी समितियों के अध्यक्षों और निदेशकों हेतु नेतृत्व विकास कार्यक्रम	40	40	0	16	0	0	0	13-15 जुलाई, 2023	मत्स्य पालन	महाराष्ट्र
38	तेलंगाना राज्य के औद्योगिक सेवा सहकारी समितियों के अध्यक्षों और निदेशकों हेतु एलडीपी (बांस)	36	0	0	0	36	0	0	13-15 जुलाई, 2023	सेवा सहकारी समितियां	तेलंगाना
39	सहकारी कानून से संबन्धित सर्टिफिकेट कोर्स	24	0	0	3	2	19	2	17 - 29 जुलाई 2023	सहकारी कानून	भारत
40	मध्य प्रदेश (रतलाम) की आजीविका बहुयोजना सहकारी समितियों की अध्यक्षों/महिला निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	43	8	21	41	14	3	0	18-20 जुलाई, 2023	महिला समिति	मध्य प्रदेश
41	बिहार के राज्य/जिला कृषि विपणन समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	50	1	1	6	15	25	0	20-22 जुलाई, 2023	कृषि	बिहार
42	भारतीय डेयरी सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	74	19	0	15	12	42	10	24-26 जुलाई, 2023	डेरी	भारत
43	केरल के डेयरी सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	30	6	0	11	9	15	0	25-27 जुलाई, 2023	डेरी	केरल

44	मध्य प्रदेश (सीहोर) के दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	40	0	0	0	40	0	0	26-28 जुलाई, 2023	डेरी	मध्य प्रदेश
45	कर्नाटक के विजयपुर जिले की सहकारी समितियों के अध्यक्षों/महिला निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	50	3	6	50	21	20	0	28-30 जुलाई, 2023	महिला समिति	कर्नाटक
46	भारतीय मत्स्य सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	47	12	3	10	23	9	5	1-3 अगस्त, 2023	मत्स्य पालन	भारत
47	मध्य प्रदेश (धार) के पैक्स के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	44	2	11	0	16	15	0	1-3 अगस्त, 2023	पैक्स	मध्य प्रदेश
48	पश्चिम बंगाल (झारग्राम) के मत्स्य सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	45	15	0	12	6	24	0	2-4 अगस्त, 2023	मत्स्य पालन	पश्चिम बंगाल
49	राजस्थान के कृषि वानिकी सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	35	1	5	1	8	20	0	2-4 अगस्त, 2023	फार्म वानिकी	राजस्थान
50	मध्य प्रदेश (भोपाल) की क्रेडिट समितियों के स्वयं सहायता समूहों के अध्यक्षों/महिला निदेशकों हेतु नेतृत्व विकास कार्यक्रम	55	22	3	55	15	14	0	4-6 अगस्त, 2023	महिला समिति	मध्य प्रदेश
51	भारतीय राज्य/जिला सहकारी संघ के सहकारी शिक्षा कार्मिकों के लिए प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम	39	2	1	7	20	16	7	7-11 अगस्त, 2023	सहकारी शिक्षा	भारत
52	मध्य प्रदेश (ज़बुआ) के डेयरी सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	43	0	9	0	34	0	0	8-10 अगस्त, 2023	डेरी	मध्य प्रदेश
53	मध्य प्रदेश उपभोक्ता सहकारी समितियों (कैम्पको), भिंड के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	52	7	0	9	28	17	0	9-11 अगस्त, 2023	पैक्स	मध्य प्रदेश
54	मध्य प्रदेश सहकारी समितियों (कैम्पको), भिंड के पैक्स के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	55	6	0	8	25	24	0	16-18 अगस्त, 2023	पैक्स	मध्य प्रदेश
55	हरियाणा के पैक्स अध्यक्षों/निदेशकों/सदस्यों हेतु नेतृत्व विकास कार्यक्रम	32	2	0	0	6	24	0	16-18 अगस्त, 2023	पैक्स	हरियाणा
56	भारत के कृषि विपणन सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों हेतु नेतृत्व विकास कार्यक्रम	44	0	5	7	22	17	4	16-18 अगस्त, 2023	कृषि	भारत
57	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के जनजातीय सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों हेतु नेतृत्व विकास कार्यक्रम	30	0	30	11	0	0	0	17-19 अगस्त, 2023	जनजातीय	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
58	महाराष्ट्र (पुणे) के आवास सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों हेतु नेतृत्व विकास/कार्यक्रम	40	2	0	2	3	33	0	19-21 अगस्त, 2023	आवास	महाराष्ट्र
59	कृभको हजीरा प्लांट, सूरत (गुजरात) के अधिकारियों के लिए सहकारिता एवं सहकारी प्रबंधन पर कार्यक्रम	30	0	2	0	10	18	0	21-22 अगस्त, 2023	उर्वरक	गुजरात
60	भारत के कॉलेज/विश्वविद्यालयों के संकाय के लिए सहकारी नीति और विकास पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	35	8	2	13	12	13	0	21-25 अगस्त, 2023	सहकार शिक्षा	भारत
61	आंध्र प्रदेश (विजयवाडा) के श्रम सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	40	5	35	0	0	0	0	22-24 अगस्त, 2023	श्रम	आंध्र प्रदेश
62	आंध्र प्रदेश (राजमुंदरी) के मत्स्य सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	81	51	0	11	0	18	0	22-24 अगस्त, 2023	मत्स्य पालन	आंध्र प्रदेश
63	मध्य प्रदेश बीज उत्पादक सहकारी समितियां (कैम्पको), भिंड के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	53	4	0	11	40	9	0	22-24 अगस्त, 2023	कृषि	मध्य प्रदेश

64	आंध्र प्रदेश (विजयवाड़ा) के संयुक्त कृषि सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	52	37	0	0	4	11	0	25-27 अगस्त, 2023	संयुक्त खेती	आंध्र प्रदेश
65	देवभूम एग्रो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी उत्तराखंड के सदस्यों/किसानों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	42	2	2	0	2	36	0	2-4 सितंबर, 2023	कृषि	उत्तराखंड
66	भारत की चीनी सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	62	2	0	1	19	41	0	4-6 सितंबर, 2023	चीनी	भारत
67	छतीसगढ़ के हथकरघा/हस्तशिल्प सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	50	2	0	10	48	0	0	4-6 सितंबर, 2023	हथकरघा/ हस्तशिल्प	छतीसगढ़
68	एनसीयूआई सहकारी शिक्षा क्षेत्र परियोजनाओं के सहकारी शिक्षा प्रशिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	33	3	3	0	5	22	0	4-6 सितंबर, 2023	सहकार शिक्षा	भारत
69	गुजरात की सहकारी ऋण समितियों के अध्यक्षों/सचिवों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	50	2	0	0	15	35	0	9-10 सितंबर, 2023	ऋण	गुजरात
70	भारतीय आवास सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों हेतु नेतृत्व विकास कार्यक्रम	60	2	0	14	17	0	0	11-13 सितंबर, 2023	आवास	भारत
71	पश्चिम बंगाल (बीरभूम), श्रीनिकेतन के राज्य/जिला सहकारी संघों के सहकारी शिक्षा कार्मिकों हेतु प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम	18	3	0	1	3	12	0	11-15 सितंबर, 2023	सहकर शिक्षा	पश्चिम बंगाल
72	मध्य प्रदेश के कृषि वानिकी सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	41	7	2	9	7	16	0	12-14 सितंबर, 2023	फार्म वानिकी	मध्य प्रदेश
73	गुजरात के कृषि एवं ग्राम विकास सहकारी समिति लिमिटेड के सचिवों/प्रबंधकों/सदस्यों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	41	0	0	0	22	19	0	13-15 सितंबर, 2023	सहकार शिक्षा	भारत
74	भारतीय मत्स्य सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	35	2	1	4	28	4	0	18-20 सितंबर, 2023	मत्स्य पालन	भारत
75	केरल कृषि विश्वविद्यालय का अध्ययन दौरा	40	0	40	33	0	0	0	45187	सहकार शिक्षा	भारत
76	भारतीय श्रम सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	33	7	4	0	8	14	0	25-27 सितंबर, 2023	श्रम	भारत
77	मिजोरम के जनजातीय सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	40	0	40	19	0	0	40	25-27 सितंबर, 2023	जनजातीय	पूर्वोत्तर राज्य
78	भावनगर में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	40	2	0	0	11	27	0	25-27 सितंबर, 2023	कृषि	भारत
79	इफको पारादीप (ओडिशा) के अधिकारियों के लिए सहकारिता और सहकारी प्रबंधन पर कार्यक्रम	37	6	0	0	4	27	0	3-4 अक्टूबर, 2023	उर्वरक	ओडिशा
80	भारत की बहुराज्यीय सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	43	5	3	8	10	25	6	3-5 अक्टूबर, 2023	बहु राज्य सहकारी समितियां	भारत
81	सहकारी शिक्षा एवं विकास में डिप्लोमा का 28वां सत्र	35	2	2	12	18	13	11	3 अक्टूबर - 22 दिसंबर, 2023	सहकार शिक्षा	भारत
82	महाराष्ट्र (बीड) के श्रम सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	50	16	0	2	0	32	0	4-6 अक्टूबर, 2023	श्रम	महाराष्ट्र
83	गुजरात की क्रेडिट सोसायटियों के अध्यक्षों/निदेशक मंडल/पदाधिकारियों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	30	3	1	4	11	15	0	7-10 अक्टूबर, 2023	ऋण	गुजरात

84	कर्नाटक सहकारी समितियों के अध्यक्षों/महिला निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	31	0	0	31	31	0	0	16-18 अक्टूबर, 2023	महिला समिति	कर्नाटक
85	पंजाब के युवा सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	44	1	0	0	13	30	0	16-18 अक्टूबर, 2023	युवा सहकारी समितियां	पंजाब
86	भारतीय मत्स्य सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	43	10	2	8	20	11	6	17-19 अक्टूबर, 2023	मत्स्य पालन	भारत
87	सहकारी कानून अभ्यास, लेखांकन सिद्धांत और सेवा मामलों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	62	2	0	0	3	57	0	18-20 अक्टूबर, 2023	सहकारी कानून	हरियाणा
88	मणिपुर (थौबल) के हथकरघा/हस्तशिल्प सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	35	3	0	14	23	9	35	18-20 अक्टूबर, 2023	हथकरघा/ हस्तशिल्प	पूर्वोत्तर राज्य
89	हरियाणा की सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों/सदस्यों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	42	4	0	1	12	26	0	25-27 अक्टूबर, 2023	पैक्स	हरियाणा
90	उत्तराखंड की देवभूमि एग्रो बहुराज्यीय सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	37	2	0	0	2	37	0	25-27 अक्टूबर, 2023	बहु राज्य सहकारी समितियां	उत्तराखंड
91	पैक्स के प्रबंधकों/सचिवों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम	45	4	0	0	44	0	0	25-29 अक्टूबर, 2023	पैक्स	आंध्र प्रदेश
92	महाराष्ट्र के शहरी सहकारी बैंकों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	41	2	0	8	4	27	0	26-28 अक्टूबर, 2023	ऋण	महाराष्ट्र
93	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के पैक्स के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	29	0	0	0	4	0	25	27-29 अक्टूबर, 2023	पैक्स	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
94	पंजाब के किसानों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	42	2	0	0	3	37	0	1-3 नवंबर, 2023	कृषि	पंजाब
95	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के मत्स्य सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	30	0	0	2	0	30	0	6-8 नवंबर, 2023	मत्स्य पालन	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
96	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के युवा/निर्माण सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	30	0	0	0	8	22	0	9-11 नवंबर, 2023	सहकार शिक्षा	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
97	मणिपुर (थौबल) के श्रम सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	35	4	2	26	19	10	35	9-11 नवंबर, 2023	श्रम	पूर्वोत्तर राज्य
98	भारतीय सहकारी समितियों के अध्यक्षों/महिला निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	36	9	5	36	6	16	9	15-17 नवंबर, 2023	महिला समिति	भारत
99	पंजाब के मत्स्य सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	42	2	0	0	3	37	0	20-22 नवंबर, 2023	मत्स्य पालन	पंजाब
100	सिक्किम की सहकारी समितियों के अध्यक्षों/महिला निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	41	3	23	40	15	0	0	20-22 नवंबर, 2023	महिला समिति	पूर्वोत्तर राज्य
101	पश्चिम बंगाल (झारग्राम) की सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों/सदस्यों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	33	5	2	8	10	16	0	22-24 नवंबर, 2023	सहकार शिक्षा	पश्चिम बंगाल
102	महाराष्ट्र की बहुराज्यीय सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	40	0	1	6	0	33	0	23-25 नवंबर, 2023	बहु राज्य सहकारी समितियां	महाराष्ट्र
103	मणिपुर (थौबल) की सहकारी समितियों के अध्यक्षों/महिला निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	35	3	0	35	20	12	35	27-29 नवंबर, 2023	महिला समिति	पूर्वोत्तर राज्य
104	भारत के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	42	35	7	23	0	0	0	28-30 नवंबर	एससी/एसटी सहकारी समितियां	भारत

105	मणिपुर के मत्स्य सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	35	8	0	4	17	8	35	28-30 नवंबर	मत्स्य पालन	पूर्वोत्तर राज्य
106	सिक्किम के पैक्स के प्रबंधकों/सचिवों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम	40	4	11	0	21	0	40	28 नवंबर-2 दिसंबर, 2023	पैक्स	पूर्वोत्तर राज्य
107	पश्चिम बंगाल सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों/सदस्यों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम (बारसूल)	29	3	0	0	4	15	0	28-30 नवंबर, 2023	सहकार शिक्षा	पश्चिम बंगाल
108	हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के श्रम एवं वन श्रम सहकारी समितियों के पदाधिकारियों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	26	2	3	1	0	21	0	30 नवंबर - 2 दिसंबर, 2023	श्रम	हिमाचल प्रदेश
109	जम्मू (बरनोटी) की सहकारी समितियों के अध्यक्षों/महिला निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	40	19	0	40	12	7	0	2-4 दिसंबर, 2023	महिला समिति	जम्मू
110	भारतीय सहकारी समितियों के अध्यक्षों/महिला निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	30	10	2	30	13	0	0	5-7 दिसंबर, 2023	महिला समिति	भारत
111	जम्मू (बरनोटी) की क्रेडिट सोसायटियों के अध्यक्षों/महिला निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	40	28	0	40	7	5	0	9-11 दिसंबर, 2023	महिला समिति	जम्मू
112	पश्चिम बंगाल (उत्तरपारा) के लिए पैक्स के प्रबंधक/सचिव/कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम	32	2	0	0	3	27	0	23 नवंबर-9 दिसंबर, 2023	पैक्स	पश्चिम बंगाल
113	कौशल विकास पर महिलाओं के लिए उद्यमिता विकास	23	3	1	23	13	6	4	11 - 22 दिसंबर, 2023	महिला समिति	भारत
114	भारत के एससीयू/डीसीयू के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	36	5	4	3	14	13	0	13-15 दिसंबर,	एससीयू/डीसीयू	भारत
115	कर्नाटक की सहकारी समितियों के अध्यक्षों/महिला निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	33	2	0	33	21	0	0	14-16 दिसंबर, 2023	महिला समिति	कर्नाटक
116	उत्तराखंड (रुड़की) के डेयरी सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	41	2	0	0	0	37	0	18-20 दिसंबर, 2023	डेरी	उत्तराखंड
117	मध्य प्रदेश (खरगौन) की मत्स्य सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	42	10	17	3	15	0	0	18-20 दिसंबर, 2023	मत्स्य पालन	मध्य प्रदेश
118	बिहार के डेयरी सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	40	3	1	6	16	14	0	19-21 दिसंबर, 2023	डेरी	बिहार
119	तेलंगाना के हथकरघा/हस्तशिल्प सहकारी समितियों के अध्यक्ष/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	31	0	0	2	31	0	0	19-21 दिसंबर, 2024	हथकरघा/ हस्तशिल्प	तेलंगाना
120	जम्मू की सहकारी समितियों के अध्यक्षों/महिला निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	40	32	0	40	2	5	0	20-22 दिसंबर, 2023	महिला समिति	जम्मू
121	मणिपुर के लिए पैक्स के प्रबंधक/सचिव/कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम	42	7	0	14	25	10	42	22-26 दिसंबर, 2024	पैक्स	पूर्वोत्तर राज्य
122	भारत के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	24	14	10	13	0	0	9	27-29 दिसंबर, 2023	एससी/एसटी सहकारी समितियां	भारत
123	मध्य प्रदेश (खरगौन) के लिए पैक्स के प्रबंधक/सचिव/कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम	51	2	1	0	37	10	0	27 दिसम्बर,23 - 12 जनवरी,24	पैक्स	मध्य प्रदेश
124	मध्य प्रदेश (सीहोर) की प्राथमिक बीज उत्पादक सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	42	0	0	0	37	5	0	28-30 दिसंबर, 2023	सहकार शिक्षा	मध्य प्रदेश

125	गुजरात (अमरेली) के लिए पैक्स के प्रबंधक/सचिव/कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम	65	0	0	0	10	55	0	28 दिसंबर-11 जनवरी, 2024	पैक्स	गुजरात
126	मध्य प्रदेश के डेयरी सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	40	5	11	0	23	11	0	29-31 दिसंबर, 2023	डेरी	मध्य प्रदेश
127	पश्चिम बंगाल (जलपाईगुड़ी) के लिए पैक्स के प्रबंधक/सचिव/कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम	25	20	0	0	2	3	0	2-20 जनवरी, 2024	पैक्स	पश्चिम बंगाल
128	एनसीयूआई सहकारी शिक्षा क्षेत्र परियोजनाओं की महिला मोबिलाइजर्स/महिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	25	2	1	25	4	18	6	3-5 जनवरी, 2024	सहकार शिक्षा	भारत
129	मध्य प्रदेश (भिंड) के पैक्स के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	40	3	0	0	12	25	0	3-5 जनवरी, 2024	पैक्स	मध्य प्रदेश
130	उत्तराखंड (रुड़की) की सहकारी समितियों के अध्यक्षों/महिला निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	44	0	0	44	1	0	0	4-6 जनवरी, 2024	महिला समिति	उत्तराखंड
131	सहकारी कानून एवं व्यवहार पर सर्टिफिकेट कोर्स	18	3	0	3	9	6	0	8-19 जनवरी, 2024	सहकार शिक्षा	भारत
132	गुजरात की सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	40	0	1	0	18	21	0	10-12 जनवरी, 2024	सहकार शिक्षा	गुजरात
133	हरियाणा के किसानों और समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों एवं अन्य सदस्यों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया गया	38	6	0	8	8	16	0	15-17 जनवरी, 2024	सहकार शिक्षा	नई दिल्ली
134	उत्तराखंड (रुड़की) के युवा सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों/कर्मचारियों/सदस्यों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	40	2	3	0	32	3	0	15-17 जनवरी, 2024	सहकार शिक्षा	उत्तराखंड
135	पंजाब के किसानों/सदस्यों/सहकारी समितियों के निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	42	2	0	0	3	37	0	17 - 19 जनवरी, 2024	सहकार शिक्षा	पंजाब
136	मध्य प्रदेश (रतलाम) के डेयरी सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	40	30	3	2	25	9	0	17-19 जनवरी, 2024	डेरी	मध्य प्रदेश
137	मध्य प्रदेश सहकारी समितियों के पैक्स के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम (कैम्पको), भिंड	57	6	0	8	27	24	0	18-20 जनवरी, 2024	पैक्स	मध्य प्रदेश
138	हरियाणा के किसानों और समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों एवं अन्य सदस्यों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया गया	39	5	0	18	6	10	0	19-21 जनवरी, 2024	सहकार शिक्षा	नई दिल्ली
139	भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एनआईआरबी) के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	32	0	0	6	32	0	0	22-24 जनवरी, 2024	एआरडीबी	भारत
140	भारत की कृषि विपणन सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	48	17	9	2	3	14	0	22-24 जनवरी, 2024	कृषि	भारत
141	मध्य प्रदेश डेयरी सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम (कैम्पको)भिंड	54	8	0	6	26	20	0	22-24 जनवरी, 2024	डेरी	मध्य प्रदेश
142	हरियाणा के किसानों और समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों एवं अन्य सदस्यों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित	40	3	0	27	5	5	0	23-25 जनवरी, 2024	सहकार शिक्षा	नई दिल्ली

143	पंजाब के कृषि विपणन एवं प्रसंस्करण सहकारी समितियों के सदस्यों/युवा सहकारी समितियों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	44	2	0	0	3	39	0	23-25 जनवरी, 2024	कृषि	पंजाब
144	हरियाणा के किसानों और समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों एवं अन्य सदस्यों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित	40	2	0	27	3	8	0	27-29 जनवरी, 2024	सहकार शिक्षा	नई दिल्ली
145	"सहकारी समितियों के गठन" पर शैक्षणिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों के छात्रों, नए छात्रों, नवनियुक्तों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	68	5	1	25	31	30	10	29 जनवरी-2 फरवरी, 2024	सहकार शिक्षा	भारत
146	मध्य प्रदेश (धार) की शहरी साख सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	45	2	6	4	17	21	0	29-31 जनवरी, 2024	ऋण	मध्य प्रदेश
147	मध्य प्रदेश विपणन सहकारी समितियों (कैम्पको), भिंड के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	53	7	0	7	23	23	0	29-31 जनवरी, 2023	विपणन	मध्य प्रदेश
148	पश्चिम बंगाल के एससीयू/डीसीयू के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	11	1	0	0	1	9	0	31 जनवरी-2 फरवरी, 24	एससीयू/डीसीयू	पश्चिम बंगाल
149	उत्तराखंड (रुड़की) की सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	40	0	0	0	38	2	0	29-31 जनवरी, 2024	सहकार शिक्षा	उत्तराखंड
150	मध्य प्रदेश (धार) के शहरी सहकारी बैंकों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	45	2	5	5	16	21	0	29-31 जनवरी, 2024	ऋण	मध्य प्रदेश
151	महाराष्ट्र के कार्मिकों के लिए प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम	42	1	2	0	0	39	0	3-5 फरवरी, 2024	सहकार शिक्षा	महाराष्ट्र
152	पंजाब के अध्यक्षों/निदेशकों/सदस्यों/किसानों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	41	2	0	2	2	37	0	5-7 फरवरी, 2024	सहकार शिक्षा	पंजाब
153	सिक्किम के बागवानी सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	40	4	8	30	28	0	40	6-8 फरवरी, 2024	हथकरघा/हस्तशिल्प	पूर्वोत्तर राज्य
154	कर्नाटक की बहुराज्यीय सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों/प्रबंधकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	40	1	0	40	39	0	0	6-8 फरवरी, 2024	बहु राज्य सहकारी समितियां	कर्नाटक
155	"उन्नत एमएस-ऑफिस और कंप्यूटर ऑपरेशन" में सर्टिफिकेट कोर्स	31	5	0	16	16	11	7	5-29 फरवरी, 2024		भारत
156	मध्य प्रदेश (इंदौर) की बहुराज्यीय सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	40	6	0	0	31	3	0	7-9 फरवरी, 2024	बहु राज्य सहकारी समितियां	मध्य प्रदेश
157	कर्नाटक की क्रेडिट सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों और सदस्यों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	49	5	0	14	18	26	0	8-10 फरवरी, 2024	ऋण	कर्नाटक
158	कर्नाटक के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु नेतृत्व विकास कार्यक्रम	43	4	7	4	28	0	0	9-11 फरवरी, 2024	सहकार शिक्षा	कर्नाटक
159	इफको कलोल इकाई (गुजरात) के कार्मिकों के लिए सहकारिता एवं सहकारी प्रबंधन पर कार्यक्रम	45	5	0	0	4	35	0	12-13 फरवरी, 2024	उर्वरक	गुजरात
160	भारत की मत्स्य सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	47	10	1	5	4	10	8	12-14 फरवरी, 2024	मत्स्य पालन	भारत
161	पंजाब राज्य की युवा सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	44	2	0	8	2	40	0	12-14 फरवरी, 2024	सहकार शिक्षा	पंजाब
162	मध्य प्रदेश (पन्ना) के डेयरी सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	40	0	3	9	32	5	0	12-14 फरवरी, 2024	डेरी	मध्य प्रदेश
163	मध्य प्रदेश (भोपाल) की महिला ऋण सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	33	1	4	33	22	6	0	13-15 फरवरी, 2024	ऋण	मध्य प्रदेश

164	मध्य प्रदेश (रतलाम) की कृषि साख सहकारी समितियों के अध्यक्षों/संचालकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	42	7	10	0	15	10	0	14-16 फरवरी, 2024	ऋण	मध्य प्रदेश
165	मध्य प्रदेश (जबलपुर) के डेयरी सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	46	35	8	46	1	2	0	14-16 फरवरी, 2024	डेरी	मध्य प्रदेश
166	गोवा की सहकारी समितियों की नेतृत्व विकास कार्यक्रम अध्यक्ष/महिला निदेशक	40	0	2	19	40	19	0	15-17 फरवरी, 2024	महिला समिति	गोवा
167	कर्नाटक के अध्यक्षों/महिला निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	50	1	2	50	47	0	0	16-18 फरवरी, 2024	महिला समिति	कर्नाटक
168	मध्य प्रदेश (खंडवा) के मत्स्य सहकारी समितियों के अध्यक्षों/संचालकों द्वारा नेतृत्व विकास कार्यक्रम	47	11	23	6	10	3	0	17-19 फरवरी, 2024	मत्स्य पालन	मध्य प्रदेश
169	आईएफएफडीसी पीएफएफसीएस के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	22	0	0	0	6	16	0	19-21 फरवरी, 2024	फार्म वानिकी	भारत
170	गुजरात की प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम	50	0	0	0	19	31	0	20 फरवरी - 5 मार्च, 2024	पैक्स	गुजरात
171	हरियाणा के श्रम सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	35	5	0	0	10	20	0	20-22 फरवरी, 2024	श्रम	हरियाणा
172	तेलंगाना की सहकारी समितियों की नेतृत्व विकास कार्यक्रम अध्यक्ष/महिला निदेशक	44	11	0	44	28	5	0	21-23 फरवरी, 2024	महिला समिति	तेलंगाना
173	मध्य प्रदेश (धार) के डेयरी सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	43	0	1	1	34	8	0	21-23 फरवरी, 2024	डेरी	मध्य प्रदेश
174	कर्नाटक की क्रेडिट सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों/सदस्यों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	45	5	0	14	17	21	0	21-23 फरवरी, 2024	ऋण	कर्नाटक
175	कलबुर्गी (कर्नाटक) के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	46	2	0	9	2	33	0	24-26 फरवरी, 2024	सहकार शिक्षा	कर्नाटक
176	मध्य प्रदेश (खंडवा) की कृषि वानिकी सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	46	8	26	0	4	7	0	26-28 फरवरी, 2024	फार्म वानिकी	मध्य प्रदेश
177	भारत की श्रम सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	21	1	0	1	3	17	0	26-28 फरवरी, 2024	श्रम	भारत
178	हरियाणा के पैक्स के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	33	5	0	0	3	25	0	27-29 फरवरी, 2024	पैक्स	हरियाणा
179	मध्य प्रदेश (खंडवा) के डेयरी सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	45	5	1	0	31	8	0	1-3 मार्च, 2024	डेरी	मध्य प्रदेश
180	सिक्किम की प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम	47	5	20	25	22	0	47	1-15 मार्च, 2024	पैक्स	पूर्वोत्तर राज्य
181	गोवा के डेयरी सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	36	2	8	14	3	9	0	4-6 मार्च, 2024	डेरी	गोवा
182	मध्य प्रदेश (ज़बुआ) के कड़कनाथ सहकारी समितियों के मुर्गीपालन के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	42	0	42	1	0	0	0	4-6 मार्च, 2024	मुर्गीपालन	मध्य प्रदेश
183	मध्य प्रदेश (जबलपुर) की सहकारी समितियों के अध्यक्षों/महिला निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	45	5	13	45	20	7	0	4-6 मार्च, 2024	महिला समिति	मध्य प्रदेश
184	भारत की महिला सहकारी प्रशिक्षकों एवं अधिकारियों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम	32	2	1	32	16	13	8	4-16 मार्च, 2024	महिला समिति	भारत

185	गुजरात की प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम	50	0	0	0	25	24	0	4-22 मार्च, 2024	पैक्स	गुजरात
186	डिजिटल बैंकिंग और महिला सशक्तिकरण पर बैंक की महिला सदस्यों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम मध्य प्रदेश (ग्वालियर)	40	1	0	40	0	0	0	5-7 मार्च, 2024	आईटी	मध्य प्रदेश
187	मध्य प्रदेश (पन्ना) के पैक्स के सचिवों/प्रबंध निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	37	1	0	0	16	20	0	5-7 मार्च, 2024	पैक्स	मध्य प्रदेश
188	मध्य प्रदेश (नागांव) के मत्स्य सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	40	0	0	4	40	0	0	5-7 मार्च, 2024	मत्स्य पालन	मध्य प्रदेश
189	मणिपुर की प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) के लिए 15 दिवसीय क्षमता विकास कार्यक्रम	50	14	1	32	18	17	50	5-21 मार्च, 2024	पैक्स	पूर्वोत्तर राज्य
190	मध्य प्रदेश (रतलाम) के डेयरी सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	40	3	0	1	21	16	0	10-12 मार्च, 2024	डेरी	मध्य प्रदेश
191	मध्य प्रदेश (भिंड) के डेयरी सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	53	9	0	24	20	10	0	11-13 मार्च, 2024	डेरी	मध्य प्रदेश
192	पंजाब के सदस्यों/युवा सहकारी समितियों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	44	2	0	0	4	38	0	11-13 मार्च, 2024	युवा सहकारी समितियां	पंजाब
193	सहकारी कानून एवं व्यवहार पर सर्टिफिकेट कोर्स	30	0	0	0	7	22	0	11-22 मार्च, 2024	सहकारी कानून	भारत
194	भारत की चीनी सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	23	0	4	4	3	16	7	11-13 मार्च, 2024	चीनी	भारत
195	मध्य प्रदेश (खरगौन) के डेयरी सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	45	0	1	0	30	14	0	12-14 मार्च, 2024	डेरी	मध्य प्रदेश
196	हरियाणा के डेयरी सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	34	0	0	8	2	34	0	13-15 मार्च, 2024	डेरी	हरियाणा
197	उत्तर प्रदेश के कृषि वानिकी सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	30	2	0	0	6	22	0	13-15 मार्च, 2024	फार्म वानिकी	उतार प्रदेश
198	प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	40	8	0	0	0	32	0	13-15 मार्च, 2024	पैक्स	महाराष्ट्र
199	मध्य प्रदेश (भिंड) की विपणन सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	55	7	0	25	23	8	0	14-16 मार्च, 2024	विपणन	मध्य प्रदेश
200	मध्य प्रदेश (हथोद) की कृषि सहकारी समितियों के अध्यक्षों/संचालकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	44	1	0	0	40	3	0	16-18 मार्च, 2024	कृषि	मध्य प्रदेश
201	मध्य प्रदेश (खरगौन) के प्राथमिक बीज उत्पादकों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	45	0	4	0	9	32	0	18-20 मार्च, 2024	पैक्स	मध्य प्रदेश
202	मणिपुर के मत्स्य सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	40	19	0	28	15	6	40	18-20 मार्च, 2024	मत्स्य पालन	पूर्वोत्तर राज्य
203	मध्य प्रदेश (जबलपुर) के पोल्ट्री सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	43	4	1	43	38	0	0	18-20 मार्च, 2024	मुर्गीपालन	मध्य प्रदेश
204	हरियाणा की प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	26	4	0	0	1	22	0	19-21 मार्च, 2024	पैक्स	हरियाणा
205	मणिपुर की एचएल/एचसी सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	40	12	0	40	14	14	40	19-21 मार्च, 2024	हथकरघा/ हस्तशिल्प	पूर्वोत्तर राज्य
206	जम्मू की सहकारी समितियों के प्रबंध समिति सदस्यों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	51	13	1	45	0	37	0	21-23 मार्च, 2024	सहकार शिक्षा	जम्मू

207	उत्तराखंड के नेताओं/सदस्यों/किसानों सहकारी समितियों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	41	3	0	0	2	36	0	21-23 मार्च, 2024	सहकार शिक्षा	उत्तराखंड
208	मणिपुर के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	40	40	0	40	0	0	40	21-23 मार्च, 2024	एससी/एसटी सहकारी समितियां	पूर्वोत्तर राज्य
209	महाराष्ट्र के चीनी सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	40	4	5	2	0	29	0	21-23 मार्च, 2024	चीनी	महाराष्ट्र
210	बीपीएसएमवी, हरियाणा के सहकारी शिक्षा पर सीओपी/डीओपी के छात्रों की अनुबंध कक्षाएं	48	5	0	48	35	8	0	45373	सहकार शिक्षा	हरियाणा
211	ग्रामीण प्रबंधन अध्ययन केंद्र, गुजरात विद्यापीठ	26	3	1	12	13	9	0	26-28 मार्च, 2024	सहकार शिक्षा	भारत
212	भारतीय शहरी सहकारी बैंकों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम (एनआईआरबी, बैंगलुरु)	26	1	1	3	4	20	1	27-29 मार्च, 2024	ऋण	भारत
213	मध्य प्रदेश (भोपाल) की आजीविका सहकारी समितियों के अध्यक्षों/संचालकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	32	2	0	33	25	5	0	27-29 मार्च, 2024	सेवा सहकारी समितियां	मध्य प्रदेश
214	कर्नाटक की सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों/सदस्यों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम	34	5	2	12	0	0	0	28-30 मार्च, 2024	सहकार शिक्षा	कर्नाटक
215	मध्य प्रदेश (भोपाल) की सहकारी समितियों के लिए महिला सशक्तिकरण और डिजिटल बैंकिंग का ज्ञान	40	15	3	40	20	2	0	29-31 मार्च, 2024	आईटी	मध्य प्रदेश
	कुल	8646	1229	670	2624	2910	3394	816			

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की सहकारी शिक्षा क्षेत्र परियोजनाएँ (कुल-34)

परिचय

भारत सरकार ने वर्ष 1976 में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक विशेष उपाय के रूप में देश के दूर-दराज के क्षेत्रों और राज्यों तक पहुँचने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) की सहकारी शिक्षा योजना को मंजूरी दी। इसमे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित केंद्रीय क्षेत्र की योजना का उद्देश्य क्षेत्रीय विकास असंतुलन को दूर करना और अविकसित क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से है।

उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य परियोजना क्षेत्रों में सहकारी समितियों का विकास और संवर्धन करना हैं। इसके अतिरिक्त इनके माध्यम से किसान सदस्यों की उत्पादकता बढ़ाकर उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है।

दृष्टिकोण

सहकारी विकास के लिए परियोजना दृष्टिकोण कृषि और तकनीकी मार्गदर्शन के साथ 'सहकारी शिक्षा' के माध्यम से गहन प्रयासों पर जोर देता है। इसके तहत परियोजना को अपनाने वाली समितियों के पदाधिकारियों और सदस्यों को व्यावसायिक गतिविधियों की योजना, परिचालन प्रबंधन और इसके मूल्यांकन में उनकी सक्रिय भागीदारी के माध्यम से व्यवसाय विकास योजनाओं को लागू करने के लिए प्रेरित और शिक्षित किया जाता है। इसमें सूक्ष्म ऋण और सतत आय सृजन गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए परियोजना कर्मियों द्वारा स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं। इन समूहों का गठन और कामकाज सहकारिता के मूल्यों पर आधारित हैं। सभी शैक्षिक, कृषि मार्गदर्शन और विकासात्मक गतिविधियों को परियोजनाओं द्वारा अपनाई गई पैक्स (प्राथमिक कृषि ऋण समितियों) और लैम्प्स (बड़े क्षेत्र बहुउद्देश्यीय समितियों) की व्यावसायिक विकास योजनाओं के साथ एकीकृत किया जाता हैं जिससे व्यापक विकास सुनिश्चित होता है।

कार्यान्वयन

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ कुल 34 सहकारी शिक्षा क्षेत्र परियोजनाओं के माध्यम से सहकारी शिक्षा को आगे बढ़ाने हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना को लागू कर रहा है। इनमें महिलाओं और पूर्वोत्तर क्षेत्र पर केंद्रित परियोजनाएं शामिल हैं जो कम और अविकसित सहकारी समितियों वाले राज्यों और क्षेत्रों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित हैं। इन परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:-

ज़ोन	क्रमांक	राज्य	परियोजना का स्थान	संख्या
दक्षिण	1	कर्नाटक	गुलबर्गा (यादगीर), शिमोगा	2
	2	केरल	तिरुवनंतपुरम	1
	3	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	1
	4	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	पोर्ट ब्लेयर	1
				5

ज़ोन	क्रमांक	राज्य	परियोजना का स्थान	संख्या
पश्चिम	5	गोवा	पणजी	1
	6	गुजरात	गांधीनगर ,सुरेंदरनगर	2
	7	मध्य प्रदेश	उज्जैन ,भोपाल,रतलाम	3
	8	छत्तीसगढ़	रायपुर	1
				7
पूर्व	9	बिहार	हाजीपुर &आरा	2
	10	ओडिशा	खुर्दा,पूरी	3
	11	पश्चिम बंगाल	रायगंज	1
				6
उत्तर क्षेत्र	12	जम्मू & कश्मीर	ऊधमपुर	1
	13	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर	1
	14	पंजाब	फाजिल्का, होशियारपुर	2
	15	राजस्थान	झुंझुनू, जोधपुर	2
	16	उत्तर प्रदेश	फ़तेहपुर बागपत, झांसी, देवरिया	4
				10
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	17	असम	मोरीगाओन	1
	18	मणिपुर	थौबल, पूर्वी इम्फाल	2
	19	मेघालय	शिलांग	1
	20	.नागालेंड	कोहिमा	1
	21	मिजोरम	आइज़ोल	1
				6

परियोजना की गतिविधियां: -

परियोजना की गतिविधियों को मुख्यतः चार भागों में विभाजित किया गया है:

1. शैक्षिक/विकासात्मक गतिविधियाँ
2. कृषि/तकनीकी मार्गदर्शन गतिविधियाँ
3. सामाजिक-विकासात्मक गतिविधियाँ
4. महिला विकास गतिविधियाँ

1. शैक्षिक और विकास गतिविधियाँ: शैक्षिक और विकास गतिविधियाँ सदस्यों को उनके व्यक्तिगत विकास को बढ़ाने, सहकारी के संचालन में सुधार करने और उनके समुदायों में सकारात्मक योगदान देने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। इन गतिविधियों में भाग लेने से सहकारी समितियाँ सदस्य क्षमताओं को बढ़ा सकती हैं, परिचालन दक्षता को बढ़ावा दे सकती हैं और सहकारी की समग्र सफलता और स्थिरता में योगदान दे सकती हैं।

2. कृषि और तकनीकी मार्गदर्शन गतिविधियाँ:

कृषि और तकनीकी मार्गदर्शन गतिविधियाँ कृषि कार्यों की उत्पादकता, स्थिरता और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये गतिविधियाँ सदस्यों को सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने, नई तकनीकों को लागू करने और उनके समग्र कृषि प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और उपकरण प्रदान करती हैं। कृषि और तकनीकी मार्गदर्शन के माध्यम से, सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों के ज्ञान, कौशल और उत्पादकता को बढ़ा सकती हैं, जिससे बेहतर कृषि उत्पादन, बढ़ी हुई आय और सतत विकास हो सकता है।

3. सामाजिक-विकासात्मक गतिविधियाँ:

सामाजिक-विकासात्मक गतिविधियाँ अपने सदस्यों और उनके द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले समुदायों की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक भलाई को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। ये गतिविधियाँ सहकारी समितियों को समुदाय, एकजुटता और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देते हुए व्यापक सामाजिक विकास में योगदान करने में सक्षम बनाती हैं। सामाजिक-विकासात्मक गतिविधियों में संलग्न होकर, सहकारी समितियाँ समावेशी और सतत सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये प्रयास न केवल सदस्यों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हैं बल्कि समुदाय के भीतर सहकारी के सामाजिक प्रभाव और प्रासंगिकता को भी मजबूत करते हैं।

4. महिला विकास गतिविधियाँ:

महिला विकास गतिविधियों का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिला सदस्यों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बढ़ाना है। इन गतिविधियों से सहकारी नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सकती है, आर्थिक अवसरों में सुधार हो सकता है और समग्र सामुदायिक विकास हो सकता है। इन महिला विकास गतिविधियों को लागू करके, सहकारी समितियाँ एक अधिक समावेशी और न्यायसंगत वातावरण बना सकती हैं जो महिलाओं को सशक्त बनाती है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है और सहकारी की समग्र सफलता और स्थिरता को बढ़ाती है।

कौशल विकास कार्यक्रम: कौशल विकास कार्यक्रम सदस्यों की क्षमताओं को बढ़ाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने और सहकारी की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये कार्यक्रम बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता से लेकर उन्नत तकनीकी और प्रबंधकीय दक्षताओं तक कौशल के व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करते हैं। कौशल विकास में निवेश करके, सहकारी समितियाँ सदस्यों की क्षमताओं में सुधार कर सकती हैं, उत्पादकता बढ़ा सकती हैं और सहकारी की समग्र सफलता और स्थिरता का समर्थन कर सकती हैं।

प्रगति:

सहकारी समिति में प्रगति का मूल्यांकन वित्तीय प्रदर्शन, सदस्य संतुष्टि, परिचालन दक्षता, सामाजिक प्रभाव और शासन सहित कई आयामों में किया जा सकता है।

परियोजनावार गतिविधियाँ, उपलब्धियाँ, प्रगति और विशेष गतिविधियों की मुख्य बातें अनुलग्नक I, II, III और IV में वर्णित हैं।

अनुलग्नक I

2023 से मार्च 2024 तक की अवधि के लिए लक्ष्य और उपलब्धियां

क्रमांक	विवरण	वित्त वर्ष 2023-24 के लक्ष्य	वर्ष 2023-2024 की उपलब्धियां
1.	आयोजनों की संख्या	15930	14697
2.	प्रतिभागियों की संख्या	334650	291991

अनुलग्नक II

अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक की प्रगति रिपोर्ट: सहकारी रूप से अविकसित राज्य और विकसित राज्यों के अविकसित क्षेत्रों में सहकारी शिक्षा का गहनीकरण (कुल 34 परियोजनाएँ)

क्रम सं.	**गतिविधियाँ**	आयोजनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
ए)	सहकारी शिक्षा गतिविधियाँ		
1	सहकारी शिक्षा कार्यक्रम	954	16489
2	जागरुकता संपर्क कार्यक्रम	1433	31921
3	आईटी हस्तक्षेप और साइबर सुरक्षा	846	23774
4	सहकारिता का संवर्धन एवं पुनरुद्धार	856	17575
5	बीडीपी कार्यक्रम	857	22406
	कुल (ए)	**4946**	**112165**
बी	सामाजिक शिक्षा गतिविधियाँ	आयोजनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	सामान्य जागरुकता कार्यक्रम	812	15672
2	लघु कौशल कार्यक्रम	941	13196
3	बीमा योजनाएँ	776	15079
4	विशेष समुदायों के लिए जागरुकता कार्यक्रम	1201	20184
5	पंचायती राज प्रणाली का कामकाज	744	14388
	कुल(बी)	**4474**	**78519**
सी	महिला विकास शिक्षा	आयोजनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	स्वयं सहायता समूहों का गठन	709	13094
2	सूक्ष्म वित्त योजनाएँ	877	14271
3	लघु कौशल कार्यक्रम	380	6055
4	महिला किसान क्लब	470	8933
5	सरकार की महिला सशक्तिकरण योजनाएँ	697	12874
	कुल(सी)	**3133**	**55227**
डी	फार्म तकनीकी मार्गदर्शन गतिविधियाँ	आयोजनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	प्राकृतिक एवं जैविक खेती	216	4567
2	पशुपालन	411	8854
3	बीज उपचार	192	3138
4	विपणन एवं प्रसंस्करण	208	4171
5	मृदा परीक्षण एवं उर्वरक उपयोग	188	3066
6	जल की बचत और संचयन	170	2777
7	कृषि सरकारी योजनाएं	181	3829
	कुल(डी)	**1566**	**30402**

ई	कौशल विकास कार्यक्रम	आयोजनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	टेलरिंग कोर्स	64	1934
2	कृत्रिम आभूषण बनाने का पाठ्यक्रम	47	1041
3	कढ़ाई और फैब्रिक पेंटिंग पाठ्यक्रम	52	1268
4	ब्यूटी पार्लर शॉर्ट कोर्स	58	1262
5	सुगंधित मोमबत्ती बनाना	50	1353
6	आय सृजन के लिए व्यावसायिक पशु पालन जैसे सुअर पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, डेयरी, मत्स्य पालन पर कार्यशाला	140	3672
7	स्वयं सहायता समूह/सहकारी सदस्यों का एक्सपोजर दौरा/अध्ययन दौरा	55	1637
8	पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम	53	1778
9	पैक्स/एसएचजी के निदेशकों और सदस्यों के लिए एलडीपी कार्यक्रम	59	1733
	कुल(ई)	**578**	**15678**
	कुल योग (ए से ई)	**14697**	**2,91,991**

अनुलग्नक III

एनसीयूआई सहकारी शिक्षा क्षेत्र परियोजनाओं की मुख्य विशेषताएं और अन्य गतिविधियां अप्रैल, 2023 से मार्च, 2024 तक

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	कुल संख्या
1	**पंजीकृत समिति**	134
2	**समिति का पुनरुद्धार**	119
3	**स्वयं सहायता समूहों का समितियों में परिवर्तन**	562
4	**नए सदस्य सोसायटी में नामांकित**	25241
5	**मिट्टी के नमूने का परीक्षण**	8017
6	**बीज के नमूना का परीक्षण किया गया**	1514
7	**गठित स्वयं सहायता समूह**	2761
8	**एसएचजी टी/सी बैठक**	9646
9	**स्वयं सहायता समूह में नए सदस्य**	18990
10	**एमसी की बैठकें**	3340
11	**एजी की बैठकें**	1535

अनुलग्नक- IV
अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक की अवधि हेतु वार्षिक रिपोर्ट

क. सहकारी शिक्षा क्षेत्र परियोजनाएँ

			पुरुष प्रतिभागी				महिला प्रतिभागी					
क्रम सं.	परियोजना का नाम	कार्यक्रम	एससी	एसटी	ओबीसी	अन्य	एससी	एसटी	ओबीसी	अन. आ.	अन्य	कुल
1	गांधीनगर	187	254	3	534	772	271	36	899	1,032	542	4,343
2	आरा	65	375	-	554	564	63	-	80	54	-	1,690
3	बागपत	150	799	570	860	650	151	96	352	222	120	3,820
4	बिलासपुर	256	705	25	335	2,629	533	16	139	1,424	535	6,341
5	फाजिल्का	137	195	15	1,592	1,190	78	46	176	178	2	3,472
6	पुरी	82	160	47	292	99	388	94	527	168	102	1,877
7	देवरिया	200	1,057	155	1,911	474	244	214	824	241	20	5,140
8	फतेहपुर	202	1,098	12	1,756	1,403	280	3	404	208	2	5,166
9	गुलबर्गा	216	621	444	1,052	441	613	365	415	237	-	4,188
10	हाजीपुर	142	476	-	701	908	391	5	485	547	178	3,691
11	होशियारपुर	252	2,136	-	322	3,193	586	-	17	274	13	6,541
12	उधमपुर	136	541	393	361	333	444	361	346	361	356	3,496
13	झांसी	128	854	107	917	447	314	25	364	237	-	3,265
14	झुंझुनू	185	562	499	1,735	724	342	306	480	343	2	4,993
15	जोधपुर	66	149	140	434	268	159	50	189	257	-	1,646
16	खुर्दा	122	399	121	620	567	263	47	451	331	113	2,912
17	पणजी गोवा	131	2	-	4	84	3	340	878	819	11	2,141
18	पोर्ट ब्लेयर	106	-	-	26	135	45	52	317	1,088	1,011	2,674
19	रायगंज	378	310	310	310	310	310	310	310	310	310	2,790
20	रायपुर	104	219	48	1,177	64	123	138	344	6	-	2,119
21	रतलाम	195	603	612	1,488	706	164	26	3,100	108	-	6,807
22	सुरेन्द्र नगर	181	34	19	738	2,934	268	-	-	-	-	3,993
23	तिरुवनंतपुरम	147	291	88	-	-	2,387	733	30	-	-	3,529
24	उज्जैन	299	1,128	131	1,452	1,185	142	17	162	97	-	4,314
25	विजयवाड़ा	54	51	6	90	198	439	4	196	123	-	1,107

26	**शिमोगा**	65	-	-	-	-	63	73	110	18	902	1,166
27	**आस्का**	86	59	-	599	40	185	30	1,079	40	6	2,038
28	**मणिपुर (इम्फाल)**	59	-	-	-	-	620	175	633	190	-	1,618
29	**भोपाल**	22	-	-	-	-	445	46	132	58	19	700
30	**आइज़ोल**	180	-	2,415	-	-	-	2,235	-	-	-	4,650
31	**थौबल**	47	134	33	357	100	66	28	354	136	2	1,210
32	**कोहिमा**	91	-	911	-	-	-	964	-	-	-	1,875
33	**मोरीगांव**	161	59	52	131	8	908	1,215	978	333	-	3,684
34	**शिलांग**	114	7	1,407	-	-	-	1,648	15	-	92	3,169
	कुल	**4,946**	**13,278**	**8,563**	**20,348**	**20,426**	**11,288**	**9,698**	**14,786**	**9,440**	**4,338**	**1,12,165**

ए) सामाजिक शिक्षा कार्यक्रम												
			पुरुष प्रतिभागी				**महिला प्रतिभागी**					
क्रम सं.	**परियोजना का नाम**	**कार्यक्रम**	**एससी**	**एसटी**	**ओबीसी**	**क्रम सं.**	**परियोजना का नाम**	**कार्यक्रम**	**एससी**	**एसटी**	**ओबीसी**	**क्रम सं.**
1	**गांधीनगर**	139	32	-	166	393	230	196	610	1,066	371	3,064
2	**आरा**	64	276	-	303	341	51	7	101	41	-	1,120
3	**बागपत**	154	575	443	729	435	211	82	290	179	166	3,110
4	**बिलासपुर**	238	672	9	128	1,414	522	20	83	1,079	214	4,11
5	**फाजिल्का**	126	147	-	1,014	701	94	-	198	144	-	2,298
6	**पुरी**	81	43	12	86	54	432	164	667	190	31	1,679
7	**देवरिया**	188	597	99	1,146	230	237	89	696	212	10	3,316
8	**फतेहपुर**	185	661	9	933	723	338	25	452	193	-	3,334

9	गुलबर्गा	87	409	281	412	347	390	307	287	214	19	2,666
10	हाजीपुर	140	325	-	491	603	281	-	343	357	121	2,521
11	होशियारपुर	225	1,108	-	98	1,257	1,219	-	50	254	12	3,998
12	उधमपुर	121	419	276	255	226	351	278	210	219	205	2,439
13	झांसी	123	568	98	686	294	217	13	286	145	-	2,307
14	झुंझुनू	176	329	262	1,049	492	295	198	501	230	-	3,356
15	जोधपुर	66	92	88	146	112	189	108	262	180	3	1,180
16	खुर्दा	112	256	114	345	239	289	48	441	309	122	2,163
17	पणजी गोवा	150	4	6	4	105	18	534	806	809	48	2,334
18	पोर्ट ब्लेयर	107	-	1	22	55	4	16	352	940	522	1,912
19	रायगंज	303	-	-	2,134	-	-	-	-	-	-	2,134
20	रायपुर	110	232	33	839	84	120	47	327	18	-	1,700
21	रतलाम	186	425	507	1,296	840	35	31	45	51	-	3,230
22	सुरेन्द्र नगर	155	40	-	702	2,023	-	-	-	-	-	2,765
23	तिरुवनंतपुरम	125	108	36	8	-	1,598	430	16	-	-	2,196
24	उज्जैन	269	887	136	1,192	860	156	21	177	111	29	3,569
25	विजयवाड़ा	33	20	1	78	262	141	28	40	37	-	607

26	**शिमोगा**	63	10	-	-	7	82	61	5	36	902	1,103
27	**आस्का**	71	5	-	83	6	187	43	916	65	20	1,325
28	**मणिपुर (इम्फाल)**	48	-	-	-	-	335	120	395	100	45	995
29	**भोपाल**	27	-	-	-	-	364	281	111	270	114	1,140
30	**आइज़ोल**	180	-	2,100	-	-	-	1,050	-	-	-	3,150
31	**थौबल**	46	98	23	293	-	58	14	301	18	-	805
32	**कोहिमा**	94	-	637	-	-	-	846	-	-	-	1,483
33	**मोरीगांव**	146	24	27	33	18	729	824	813	209	9	2,686
34	**शिलांग**	136	8	930	-	-	13	1,640	-	-	102	2,693
	कुल	**4,474**	**8,370**	**6,128**	**14,671**	**12,121**	**9,186**	**7,521**	**9,781**	**7,676**	**3,065**	**78,519**

सी) महिला विकास कार्यक्रम

			पुरुष प्रतिभागी				**महिला प्रतिभागी**					
क्रम सं.	**परियोजना का नाम**	**कार्यक्रम**	**एससी**	**एसटी**	**ओबीसी**	**क्रम सं.**	**परियोजना का नाम**	**कार्यक्रम**	**एससी**	**एसटी**	**ओबीसी**	**कुल**
1	**गांधीनगर**	110	-	-	-	98	185	197	881	498	217	2,076
2	**आरा**	कोई लेडी मोबिलाइज़र (एलएम) नहीं										
3	**बागपत**	135	-	-	-	-	847	762	619	415	359	3,002
4	**बिलासपुर**	कोई लेडी मोबिलाइज़र (एलएम) नहीं										
5	**फाजिल्का**	कोई लेडी मोबिलाइज़र (एलएम) नहीं										
6	**पुरी**	138	-	-	-	-	650	480	802	758	50	2,740
7	**देवरिया**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	**फतेहपुर**	132	60	-	-	-	794	-	748	1,021	-	2,623

9	गुलबर्गा	135	-	-	12	-	951	448	746	282	-	2,439
10	हाजीपुर	कोई लेडी मोबिलाइज़र (एलएम) नहीं										
11	होशियारपुर	कोई लेडी मोबिलाइज़र (एलएम) नहीं										
12	उधमपुर	103	293	217	199	194	244	220	216	232	232	2,047
13	झांसी	127	-	-	-	-	656	648	587	574	-	2,465
14	झुंझुनू	152	-	-	-	-	267	249	1,770	972	4	3,262
15	जोधपुर	कोई लेडी मोबिलाइज़र (एलएम) नहीं										
16	खुर्दा	128	-	-	-	-	414	297	740	373	-	1,824
17	पणजी गोवा	कोई लेडी मोबिलाइज़र (एलएम) नहीं										
18	पोर्ट ब्लेयर	110	-	-	-	6	129	15	331	1,448	189	2,118
19	रायगंज	191	15	-	-	10	1,730	120	72	1,184	10	3,141
20	रायपुर	कोई लेडी मोबिलाइज़र (एलएम) नहीं										
21	रतलाम	137	-	-	-	-	606	517	706	312	-	2,141
22	सुरेन्द्र नगर	128	-	-	-	-	472	76	1,958	51	-	2,557
डी) कृषि तकनीकी मार्गदर्शन												
23	तिरुवनंतपुरम	173	-	-	-	42	1,950	-	138	32	242	2,404
24	उज्जैन	48	-	-	-	-	206	186	229	251	-	872
25	विजयवाड़ा	13	-	-	-	-	3	41	174	46	1	265
26	शिमोगा	354	-	-	4,250	-	-	-	-	-	-	4,250
27	आस्का	84	8	-	6	1	282	61	1,195	181	-	1,734
28	मणिपुर (इम्फाल)	91	-	-	-	20	400	265	445	265	160	1,555
29	भोपाल	56	-	-	-	-	394	85	299	187	56	1,021
30	आइज़ोल	116	-	-	-	-	80	2,145	-	-	-	2,225
31	थौबल	99	22	-	86	16	78	165	984	564	-	1,915
32	कोहिमा	85	-	-	-	-	54	1,408	-	-	-	1,462
33	मोरीगांव	148	-	-	-	-	870	676	954	324	10	2,834
34	शिलांग	140	-	-	-	-	520	1,585	150	-	-	2,255
	कुल	**3,133**	**398**	**217**	**4,553**	**387**	**12,782**	**10,646**	**14,744**	**9,970**	**1,530**	**55,227**

			पुरुष प्रतिभागी				महिला प्रतिभागी					
क्रमांक	कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रम	एससी	एसटी	ओबीसी	अन्य	एससी	एस टी	ओबीसी	यूआर	अन्य	कुल
1	गांधीनगर	132	-	-	4	76	4	209	1,993	563	-	2,849
2	आरा	115	264	-	282	109	134	-	118	16	1,158	2,081
3	बागपत	कोई फार्म मार्गदर्शन प्रशिक्षक (एफजीआई) नहीं										
4	बिलासपुर	105	284	-	43	574	253	-	23	738	-	1,915
5	फाजिल्का	156	130	-	1,389	1,083	81	8	149	160	1	3,001
6	पुरी	कोई फार्म मार्गदर्शन प्रशिक्षक (एफजीआई) नहीं										
7	देवरिया	कोई फार्म मार्गदर्शन प्रशिक्षक (एफजीआई) नहीं										
8	फतेहपुर	कोई फार्म मार्गदर्शन प्रशिक्षक (एफजीआई) नहीं										
9	गुलबर्गा	कोई फार्म मार्गदर्शन प्रशिक्षक (एफजीआई) नहीं										
10	हाजीपुर	157	370	119	472	652	381	261	345	201	19	2,820
11	होशियारपुर	163	651	-	-	2,261	-	-	-	-	-	2,912
12	उधमपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	झांसी	136	645	3	1,170	301	163	-	130	54	-	2,466
14	झुंझुनू	139	654	280	1,165	657	-	-	-	-	-	2,756
15	जोधपुर	कोई फार्म मार्गदर्शन प्रशिक्षक (एफजीआई) नहीं										
16	खुर्दा	कोई फार्म मार्गदर्शन प्रशिक्षक (एफजीआई) नहीं										
17	पणजी गोवा	कोई फार्म मार्गदर्शन प्रशिक्षक (एफजीआई) नहीं										
18	पोर्ट ब्लेयर	कोई फार्म मार्गदर्शन प्रशिक्षक (एफजीआई) नहीं										
19	रायगंज	कोई फार्म मार्गदर्शन प्रशिक्षक (एफजीआई) नहीं										
20	रायपुर	194	2,275	2,275	-	-	-	-	-	-	-	4,550
21	रतलाम	कोई फार्म मार्गदर्शन प्रशिक्षक (एफजीआई) नहीं										
22	सुरेन्द्र नगर	कोई फार्म मार्गदर्शन प्रशिक्षक (एफजीआई) नहीं										
23	तिरुवनंतपुरम	कोई फार्म मार्गदर्शन प्रशिक्षक (एफजीआई) नहीं										
24	उज्जैन	कोई फार्म मार्गदर्शन प्रशिक्षक (एफजीआई) नहीं										
25	विजयवाड़ा	कोई फार्म मार्गदर्शन प्रशिक्षक (एफजीआई) नहीं										

26	शिमोगा	कोई फार्म मार्गदर्शन प्रशिक्षक (एफजीआई) नहीं										
27	आस्का	कोई फार्म मार्गदर्शन प्रशिक्षक (एफजीआई) नहीं										
28	मणिपुर (इम्फाल)	4	-	-	-	-	10	30	95	-	-	135
29	भोपाल	कोई फार्म मार्गदर्शन प्रशिक्षक (एफजीआई) नहीं										
30	आइज़ोल	कोई फार्म मार्गदर्शन प्रशिक्षक (एफजीआई) नहीं										
31	थौबल	112	121	-	1,135	95	73	6	545	25	-	2,000
32	कोहिमा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	मोरीगांव	153	316	340	291	297	452	438	403	370	10	2,917
34	शिलांग	कोई फार्म मार्गदर्शन प्रशिक्षक (एफजीआई) नहीं										
	कुल	**1,566**	**5,710**	**3,017**	**5,951**	**6,105**	**1,551**	**952**	**3,801**	**2,127**	**1,188**	**30,402**

ई) कौशल विकास गतिविधियाँ											
			पुरुष प्रतिभागी				महिला प्रतिभागी				
क्रमांक	**कार्यक्रम का नाम**	**कार्यक्रम**	**एससी**	**एसटी**	**ओबीसी**	**अन्य**	**एससी**	**एसटी**	**ओबीसी**	**अनारक्षित**	**कुल**
1	गांधीनगर	45	-	-	10	9	211	35	1,046	1,271	105	2,687
2	आरा	9	29	-	40	26	62	-	145	54	-	356
3	बागपत	5	22	14	52	6	30	11	88	8	6	237
4	बिलासपुर	14	16	1	15	97	117	32	60	215	1	554
5	फाजिल्का	5	5	-	34	31	9	-	25	41	-	145
6	पुरी	6	-	-	151	-	-	30	-	-	-	181
7	देवरिया	9	14	1	66	48	27	11	96	41	-	304
8	फतेहपुर	11	32	-	51	35	94	-	52	81	-	345
9	गुलबर्गा	1	-	16	17	8	17	24	23	19	21	145
10	हाजीपुर	5	7	-	16	33	25	-	51	23	-	155
11	होशियारपुर	13	61	-	24	82	107	-	58	81	-	413
12	उधमपुर	24	89	70	68	47	102	88	89	68	70	691
13	झांसी	11	80	1	133	51	40	1	50	10	-	366
14	झुंझुनू	35	4	8	48	1	80	4	59	7	-	211

15	जोधपुर	21	75	4	174	29	49	-	117	95	-	543
16	खुर्दा	2	6	-	30	9	38	23	70	52	17	245
17	पणजी गोवा	36	-	-	-	-	-	205	347	448	-	1,000
18	पोर्ट ब्लेयर	4	-	1	-	-	1	1	14	75	20	112
19	रायगंज	175	1,720	191	6	13	46	-	13	69	-	2,058
20	रायपुर	5	-	-	-	14	36	30	79	3	-	162
21	रतलाम	1	-	-	-	-	11	9	30	5	-	55
22	सुरेन्द्र नगर	10	-	-	-	32	84	-	25	1	-	142
23	तिरुवनंतपुरम	15	97	19	11	-	168	88	-	-	-	383
24	उज्जैन	15	40	6	54	10	263	23	244	61	-	701
25	विजयवाड़ा	10	-	-	-	-	144	1	23	32	-	200
26	शिमोगा	10	-	-	-	-	57	25	2	-	355	439
27	आस्का	5	-	-	46	-	11	-	107	6	-	170
28	मणिपुर (इम्फाल)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	भोपाल	3	-	-	-	-	64	8	44	38	-	154
30	आइज़ोल	9	-	58	-	-	-	449	-	-	-	507
31	थौबल	38	-	-	264	60	-	16	470	334	45	1,189
32	कोहिमा	10	-	34	-	-	-	132	-	-	-	166
33	मोरीगांव	10	35	28	20	30	116	94	64	73	-	460
34	शिलांग	6	-	33	-	-	-	155	-	-	14	202
	कुल	**578**	**2,332**	**485**	**1,330**	**671**	**2,009**	**1,495**	**3,491**	**3,211**	**654**	**15,678**
कुल योग		**14697**	**30088**	**18410**	**46853**	**39710**	**36816**	**30,312**	**46,603**	**32,424**	**10,775**	**2,91,991**

अध्याय 03

सामान्य सहकारी नीति

वार्षिक रिपोर्ट 2023-2024

कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति

सामान्य सहकारी नीति (जीसीपी) विभाग ने 17वां भारतीय सहकारी महासम्मेलन, क्षेत्रीय सम्मेलन, 'सहकारिता' के क्षेत्र में चौधरी ब्रह्मप्रकाश स्मारक अनुसंधान छात्रवृत्ति प्रदान करने और नई राष्ट्रीय सहकार नीति के मसौदे पर राष्ट्रीय समिति की बैठक सहित कई अन्य कार्यक्रम आयोजित किए।

17वां भारतीय सहकारी महासम्मेलन

उद्घाटन समारोह

दिनांक 01-02 जुलाई, 2023 को भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र (आईईसीसी), प्रगति मैदान, नई दिल्ली में सहकारी आंदोलन के सर्वोच्च मंच 17वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया और इसकी अध्यक्षता माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने की। इस कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री बी एल वर्मा और अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन - एशिया प्रशांत (आईसीए-एपी) अध्यक्ष डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव भी शामिल थे। इस महासम्मेलन में भारत सरकार,सहकारिता मंत्रालय के सचिव और अतिरिक्त सचिव-सह-सीआरसीएस जैसे उच्च पदस्थ अधिकारियों, विभिन्न राज्यों के सहकारिता मंत्रियों और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इसके अतिरिक्त सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, विभिन्न राज्य पदाधिकारी और राष्ट्रीय से लेकर प्राथमिक स्तर तक की विभिन्न सहकारी समितियों के 3,500 प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस सम्मेलन की शोभा बढ़ाई।.

इस कार्यक्रम का आयोजन बहुत ही खुशनुमा मौहल में किया गया था जिसका विषय था "अमृत काल: जीवंत भारत, सहकार से समृद्धि", जिसमें सामूहिक विकास के सार और एक मजबूत अर्थव्यवस्था को आकार देने में सहकार की क्षमता को समाहित किया गया।

भारत की समृद्ध सहकारी विरासत से प्रेरणा लेते हुए सम्मेलन का उद्देश्य सहकारी आंदोलन को प्रभावशीलता, दक्षता और समावेशिता के एक नए युग में ले जाने के लिए नवीन रणनीतियों और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना था। विषय का चयन सहकारी क्षेत्र में नई गतिशीलता लाने और इसे भारत की विकास यात्रा की आधारशिला के रूप में स्थापित करने की आकांक्षा के साथ प्रतिध्वनित हुआ। तकनीकी सत्र के दौरान सहकारी ऋण प्रणालियों, लैंगिक समानता, सामाजिक समावेश और भारतीय अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों के महत्व के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करते हुए कुल सात तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। सत्रों के विषय निम्नलिखित थे:

1. अनुकूल सहकारी विधान और नीति सुधार
2. सहकारी आंदोलन को मजबूत करने हेतु अंतर-क्षेत्रीय सहयोग
3. सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान को मजबूत करना
4. प्रतिस्पर्धी सहकारी व्यवसाय उद्यमों के लिए व्यापार करने में आसानी
5. सहकारी शासन हेतु नवाचार और प्रौद्योगिकी
6. सहकारिता के माध्यम से लैंगिक समानता और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना
7. भारतीय अर्थव्यवस्था में सहकारी ऋण प्रणाली का महत्व

इन सत्रों में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ, विचारक और व्यवसायी एक साथ आए, सार्थक संवादों किया, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया और सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए कार्रवाई योग्य सिफारिशों की पहचान की। वक्ताओं, विशेषज्ञों और पैनलिस्टों ने बहुमूल्य अंतर्दृष्टि, रणनीति और नवाचारों की पेशकश की जो भारत के सहकारी आंदोलन को और अधिक समृद्धि की ओर ले जाने के लिए तैयार एवं सक्षम हैं।

सम्मेलन समापन समारोह में मुख्य अतिथि एवं अन्य सम्मानित अतिथि.

समापन समारोह

17वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन का समापन समारोह दिनांक 02 जुलाई, 2023 को अपराह्न 4 बजे आयोजित किया गया। यह समापन कार्यक्रम बहुत ही समृद्ध और ज्ञानवर्धक था। इस सम्मेलन में देश भर से प्रतिष्ठित अतिथि, सहकारी नेता, विशेषज्ञ और इच्छुक लोग शामिल हुए जो "अमृत काल: जीवंत भारत, सहकार से समृद्धि" विषय पर अपने विचार रखें और अन्य विषयों पर भी विचार-विमर्श किया।

इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भी अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। माननीय केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रुपाला भी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे जिन्होंने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस अवसर को और भी अधिक गौरवान्वित किया।

दीप प्रज्वलित करते विशिष्ट अतिथिगण

दक्षिण क्षेत्र के राज्यों के लिए सहकारी विकास पर सम्मेलन

दिनांक 11 अक्टूबर, 2023 को दक्षिण क्षेत्र के राज्यों जैसे केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी इत्यादि में सहकारी विकास पर क्षेत्रीय सम्मेलन फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के केएलएन प्रसाद ऑडिटोरियम, हैदराबाद में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य दक्षिणी राज्यों में सहकारी आंदोलन के विकास, उपलब्धियों, मुद्दों और समस्याओं की समीक्षा करना और इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए रणनीति तैयार करना था। इस सम्मेलन का उद्घाटन तेलंगाना की माननीय राज्यपाल और पुडुचेरी की माननीय उपराज्यपाल डॉ. (श्रीमती) तमिलिसाई सुंदरराजन ने किया। इस सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया जिनमें अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बोर्ड के सदस्य, सचिव, पैक्स सदस्य और विभिन्न प्राथमिक सहकारी समितियों के प्रतिनिधि शामिल थे जो मुख्य रूप से तेलंगाना और अन्य दक्षिणी राज्यों से थे। अपने उद्घाटन भाषण में माननीय राज्यपाल ने सहकारी शिक्षा पर केंद्रित अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों और क्षेत्रीय परियोजनाओं के माध्यम से पूरे भारत में किसानों और कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए एनसीयूआई के प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने तमिलनाडु के एक प्रतिष्ठित कवि और दार्शनिक संत तिरुवल्लुवर का हवाला देते हुए बताया कि भारत में सहकारी दर्शन एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री के 'सहकारिता के माध्यम से समृद्धि' के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से सहकारी क्षमताओं को बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि भारत को पाँच ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में सहकारी क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए और देश में सहकार को मजबूत करने के लिए पिछले तीन वर्षों में विभिन्न पहलों को आगे बढ़ाने के लिए एनसीयूआई अध्यक्ष को बधाई दी।.

श्री दिलीप संघाणी, अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ ने तेलंगाना के राज्यपाल, पुडुचेरी के उपराज्यपाल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिनिधियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने राज्यपाल के प्रति उनकी भागीदारी के लिए आभार व्यक्त किया और उपस्थित लोगों को विभिन्न गतिविधियों जिसमें शिक्षा और प्रशिक्षण पहल और प्राथमिक समितियों के उत्पादों के विपणन के लिए एनसीयूआई-हाट को बढ़ावा देना शामिल है, उसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री को एक अलग सहकारिता मंत्रालय की स्थापना करने और एक अनुभवी सहकारी नेता श्री अमित शाह को इसका नेतृत्व करने के लिए नियुक्त करने के लिए भी धन्यवाद दिया। इस सम्मेलन में प्रमुख सहकारी नेताओं ने भाग लिया जिनमें नेफ्सकॉब अध्यक्ष और तेलंगाना राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री कोंडुरु रविंदर राव, एनसीसीई के समिति सदस्य और इफको निदेशक श्री रामचंद्रन, आंध्र प्रदेश महेश सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड अध्यक्ष श्री रमेश कुमार बंग, तमिलनाडु सहकारी आवास संघ के अतिरिक्त रजिस्ट्रार और प्रशासक टीएमटी वी. देवकी, मार्कफेड अध्यक्ष श्री एम. गंगा रेड्डी और तेलंगाना राज्य सहकारी संघ के अध्यक्ष श्री राजा वरप्रसाद राव आदि गणमान्य शामिल थे। सम्मेलन में सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, पदाधिकारी और तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी की विभिन्न सहकारी समितियों के सदस्य भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

सम्मेलन के अवसर पर एनसीयूआई अध्यक्ष श्री दिलीप संघाणी बोलते हुए

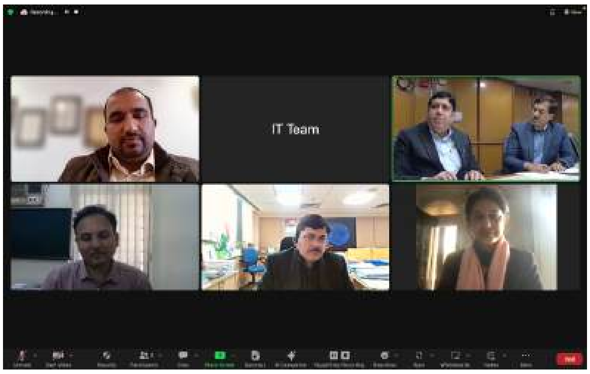

वेबिनार के माध्यमों से बैठक में
शामिल हुए प्रतिष्ठित प्रतिभागियों का एक दृश्य

सहकारिता विषय में चौ. ब्रह्मप्रकाश स्मारक अनुसंधान अनुदान (2023-2024)

वर्ष 2023-2024 में शासी परिषद के निर्णय के अनुसार एनसीयूआई अध्यक्ष ने सहकारिता विषय में चौधरी ब्रह्मप्रकाश स्मारक अनुसंधान अनुदान प्रदान करने के लिए एक समिति गठित की। इस समिति ने दो प्राप्तकर्ताओं का चयन किया और उन्हें अनुदान प्रदान किया। श्री राम कृष्ण मिशन विद्यालय, कला और विज्ञान महाविद्यालय, कोयंबटूर, तमिलनाडु से श्री दर्शन एस और महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राजस्थान से श्री विजेंद्र कुमार को यह प्रदान किया गया।

राष्ट्रीय सहकार नीति

सहकारिता मंत्रालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में नई राष्ट्रीय सहकार नीति दस्तावेज का मसौदा तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया। एनसीयूआई अध्यक्ष श्री दिलीप संघाणी समिति के सदस्यों में से एक हैं। नई राष्ट्रीय सहकार नीति दस्तावेज का मसौदा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की समिति की दो बैठकें एनसीयूआई द्वारा अपने परिसर में 28 दिसंबर, 2022 और 14 फरवरी, 2023 को श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु, पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में आयोजित की गईं।

अध्याय 04

प्रकाशन एवं जनसंपर्क

जनसंपर्क

जनसंपर्क विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान संस्थान की छवि में वृद्धि करने और मीडिया आउटलेट्स के साथ संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विभाग ने रणनीतिक पहलों और योजनाओं के माध्यम से प्रभावी रूप से महत्वपूर्ण संदेशों का प्रसार किया और विभिन्न प्लेटफार्मों पर सहकारी लोकाचार को बढ़ावा दिया। विभाग की गतिविधियों का एक वर्णन इस प्रकार हैं:

सहकारी सप्ताह समारोह के लिए राष्ट्रीय स्तर के संघों के प्रबंध निदेशक और वरिष्ठ अधिकारियों की नामकरण बैठक:-

दिल्ली स्थित राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संगठनों के प्रबंध निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों की सहकारी सप्ताह समारोह के लिए नामकरण बैठक दिनांक 07 अगस्त, 2023 को आयोजित की गई । राष्ट्रीय स्तर के संघों के प्रबंध निदेशकों और प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ परामर्श के आधार पर सहकारी सप्ताह समारोह का विषय "भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और एसडीजी बनाने में सहकारी समितियों की अहम भूमिका" तय किया गया।

70वां अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह:-

दिनांक 14 से 20 नवंबर, 2023 तक पूरे देश में 70वें अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह का भव्य आयोजन किया गया। इस बार "भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और सतत विकास लक्ष्य बनाने में सहकारिता की भूमिका" नामक थीम के तहत सप्ताह भर चलने वाले इस समारोह की शुरुआत 15 नवंबर 2023 को एनसीयूआई में उद्घाटन समारोह के साथ हुई। इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री श्री पुरुषोत्तम रुपाला थे। एनसीयूआई अध्यक्ष श्री दिलीप संघाणी ने अध्यक्षीय भाषण दिया जबकि एनसीयूआई मुख्य कार्यकारी डॉ. सुधीर महाजन ने इस समारोह में उद्घाटन भाषण दिया। इस उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय स्तर और राज्य संघों के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशकों, विभिन्न संगठनों के सहकारी अधिकारी और अन्य सहित 400 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

सहकारिता सप्ताह थीम पर एक राष्ट्रीय स्तर की वेबिनार दिनांक 17 नवंबर, 2023 को आयोजित की गई। इस वेबिनार में मुख्य वक्ता जयन मेहता प्रबंध निदेशक, अमूल और संतोष शुक्ला महाप्रबंधक इफको थे। राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिलों के महासंघ के सहयोग से 17 नवंबर, 2023 को "सहकारी चीनी क्षेत्र को मजबूत करने में सहकारिता मंत्रालय की पहल" पर एक और वेबिनार आयोजित की गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिलों के महासंघ के प्रबंध निदेशक प्रकाश नाइकनवरे मुख्य वक्ता थे।

इस वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण आयोजनों की प्रेस विज्ञप्तियाँ और एनसीयूआई अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी के भाषणों और संदेशों का मसौदा तैयार किया गया।

- 70वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के उद्घाटन समारोह और अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर अंग्रेजी और हिंदी में प्रेस विज्ञप्तियाँ तैयार की गईं। इन आयोजनों को मीडिया में भरपूर कवर किया गया।
- विभिन्न विदेशी प्रतिनिधिमंडलों की यात्राओं और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, दक्षिण क्षेत्र सम्मेलन और अन्य कार्यक्रमों पर आयोजित बैठकों के लिए अंग्रेजी और हिंदी में प्रेस विज्ञप्तियाँ तैयार की गईं।

- 17वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन से पहले 29 जून, 2023 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई जिसका आयोजन 1-2 जुलाई, 2023 को किया गया। 17वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस कार्यक्रम में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 60 से अधिक पत्रकारों के साथ-साथ राष्ट्रीय महासंघों के अध्यक्ष, एमडी और अन्य सहकारी अधिकारी शामिल हुए।

- अंग्रेजी और हिंदी में प्रेस नोट और विज्ञप्तियां तैयार की गई और उन्हें व्यापक मीडिया कवरेज मिला। भारतीय सहकारी महासम्मेलन के पूर्व-प्रचार के लिए ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से दैनिक आधार पर महासम्मेलन के नवीनतम अपडेट एफएम रेनबो पर भी प्रसारित किए गए।

- 17वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन के दौरान दिनांक 1 और 2 जुलाई, 2023 को आयोजित उद्घाटन और समापन समारोह के लिए अंग्रेजी और हिंदी में प्रेस विज्ञप्तियां तैयार की गईं। इस आयोजन को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छी तरह से कवर किया गया। इसे आयोजन से पहले और बाद में व्यापक सोशल मीडिया कवरेज भी मिला।

- एनसीयूआई की एजीएम, सहकारी सप्ताह समारोह, दक्षिण क्षेत्र सम्मेलन आदि के अवसर पर एनसीयूआई अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी के अंग्रेज और हिंदी में भाषणों का मसौदा तैयार किया गया। माननीय केंद्रीय सहकारिता मंत्री और राज्य सहकारिता मंत्री के भाषणों का मसौदा भी तैयार किया गया।

- एनसीयूआई और सामान्य रूप से सहकारी क्षेत्र में विकास के सोशल मीडिया अपडेट और विशेष रूप से एनसीयूआई की गतिविधियों और कार्यक्रमों से संबंधित एनसीयूआई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नियमित रूप से प्रदान किए गए।

- सभी सदस्यों और अन्य हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ सहकारिता मंत्रालय और एनसीयूआई के सोशल मीडिया हैंडल की पहुंच बढ़ाने के लिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा बुलाई गई बैठकों में विभागीय अधिकारियों ने नियमित रूप से भाग लिया। एनसीयूआई में विकास से संबंधित समाचार नियमित रूप से व्यापक कवरेज के लिए वेबसाइट (indiancooperative.com) को भेजे जाते थे।

प्रकाशन द कोऑपरेटर:-

एनसीयूआई द्वारा मासिक पत्रिका "द कोऑपरेटर" प्रकाशित की जाती हैं। जिसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों खंड शामिल होते हैं। यह सहकारी संस्थाओं सहित सहकारी बिरादरी के लिए एक नियमित संचार चैनल के रूप में कार्य करता है। "द कोऑपरेटर" पत्रिका के सभी अंक निर्धारित समय पर प्रकाशित किए गए और सभी ग्राहकों को वितरित किए गए। ऑनलाइन संस्करण एनसीयूआई वेबसाइट पर अपलोड किए गए और एक पीडीएफ प्रति सहकारी संगठनों के बीच व्यापक रूप से प्रसारित की गई।

"द कोऑपरेटर" पत्रिका का विशेष अंक ::-

इस वर्ष के दौरान विभाग ने 70वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के उपलक्ष्य में नवंबर 2023 में इसका एक विशेष अंक प्रकाशित किया। इस अंक का मुख्य विषय "भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और सतत विकास लक्ष्य बनाने में सहकारिता की भूमिका" सहकारी सप्ताह की थीम के अनुरूप था। इस विशेष अंक में राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संगठनों के अध्यक्षों और प्रबंध निदेशकों और अन्य विशेषज्ञों द्वारा दिए गए कई लेख शामिल थे। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, बजट का विश्लेषण आदि महत्वपूर्ण विषयों पर लेख "द कोऑपरेटर" के विशेष अंक में प्रकाशित किए गए।

"इंडियन कूपरेटिव रिव्यू"

यह एनसीयूआई की त्रैमासिक शोध पत्रिका है। अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर 2023 और जनवरी 2024 के महीनों में इसके अंक मुद्रित किए गए। इस पत्रिका में प्रकाशन के लिए बड़ी संख्या में गुणवत्तापूर्ण लेख प्राप्त करने के लिए सहकारी संगठनों, शिक्षण संकाय, शिक्षाविदों, विशेषज्ञों के एमडी/सीईओ को लेखों के लिए आमंत्रण पत्र भेजे गए।

"सहकार जागरण"

सहकारिता मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2023 से 'सहकार जागरण' प्रकाशित करने के निर्देश के अनुसार विभाग ने हिंदी, अंग्रेजी और 10 क्षेत्रीय भाषाओं में पत्रिका नियमित रूप से प्रकाशित की। सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से एनसीयूआई द्वारा प्रकाशित इस पत्रिका की हर तरफ से सराहना हुई है। पत्रिका से संबंधित संपादकीय, संचलन और डाक संबंधी मामलों को देखने के लिए मंत्रालय द्वारा आयोजित बैठकों में विभागियों कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

17वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन के अवसर पर स्मारिका:-

17वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन के अवसर पर 200 पृष्ठों की स्मारिका प्रकाशित की गई। इस पत्रिका में भारतीय सहकारी महासम्मेलन के मुख्य विषय और सहकारिता से संबंधित अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर लेख और पत्र शामिल किए गए। यह लेख सहकारी संगठनों के अध्यक्षों और प्रबंध निदेशकों एवं अन्य विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए थे। यह स्मारिका भारतीय सहकारी महासम्मेलन के सभी प्रतिनिधियों को वितरित की गई। पत्रिका की हार्ड और सॉफ्ट प्रतियां भी कई सहकारी संगठनों को वितरित की गईं। यह स्मारिका सहकारिताओं के सभी बंधुओं के लिए एक मूल्यवान दस्तावेज साबित हुई हैं।

अध्याय 05

राजभाषा विभाग

वर्ष के दौरान (01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक) राजभाषा के कार्यान्वियन से संबंधित विशिष्ट उपलब्धियों/कार्यों का संक्षिप्त विवरण

1. संघ कार्यालय की हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित त्रैमासिक रिपोर्ट (जनवरी, 2023 से मार्च, 2023 भाग - 1 एवं अप्रैल 2022 से मार्च, 2023, भाग - 2) तैयार की गई एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को उनकी वेबसाइट पर निर्धारित प्रोफार्मा में ऑनलाइन प्रेषित की गई तथा नराकास एवं अन्य संबंधितों को इसकी एक प्रति प्रेषित की गई।

2. छमाही रिपोर्ट महानिदेशक, केन्द्रीय होम्योपथी अनुसंधान परिषद्, जवाहर लाल नेहरू अनुसंधान भवन, 61-65 इंस्टीट्यूशनल एरिया, 'डी' ब्लाक के सामने, जनकपुरी नई दिल्ली - 110058 (नोडल कार्यालय) एवं नराकास दक्षिण दिल्ली-03, भारतीय जन संचार संस्थान (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार) अरुणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली - 110067, को प्रेषित किया गया।

3. राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन से संबंधित वर्ष 2022-23 की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट निदेशक (राजभाषा), मंत्रालय को भिजवाई गयी

4. संघ कार्यालय की हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित त्रैमासिक रिपोर्ट (अप्रैल, 2023 से जून, 2023 तक) तैयार की गई एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उप निदेशक (कार्यान्वियन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को उनकी वेबसाइट पर निर्धारित प्रोफार्मा में ऑनलाइन प्रेषित की गई तथा निदेशक (राजभाषा), मंत्रालय को भी एक प्रति प्रेषित की गई।

5. संघ कार्यालय की हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित त्रैमासिक रिपोर्ट (01 जुलाई, 2023 से 31 सितम्बर, 2023 तक) तैयार कर आवश्यक कार्रवाई हेतु उप निदेशक (कार्यान्वियन), राजभाषा विभाग को प्रेषित की गई एवं गृह मंत्रालय को उनकी वैबसाइट पर निर्धारित प्रेाफोर्मा में ऑनलाईन रिपोर्ट प्रेषित की गई एवं नराकास को इसकी एक प्रति भिजवाई गई।

6. राजभाषा विभाग के पोर्टल पर भेजी गयी जुलाई से सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा रिपोर्ट के प्रत्युत्तर में कार्यालय द्वारा ठोस कदम उठाए जाने का आश्वासन क्षेत्रीय कार्यान्वियन कार्यालय को भेजा गया।

7. राजभाषा कार्यान्वियन समिति (दक्षिण दिल्ली-03) की बैठक का आयोजन गूगल मीट पर किया गया और उस बैठक में निदेशक (राजभाषा) व हिंदी अधिकारी/कर्मचारी ने भाग लिया। इस बैठक में हिंदी की प्रगति के बारे में विस्तृत चर्चा की गई।

8. नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति, दक्षिण दिल्ली-3 की छमाही बैठक में राजभाषा विभाग से हिंदी अधिकारी ने भाग लिया। यह बैठक 23 जून, 2023 को आयोजित की गई।

9. संघ कार्यालय में हिन्दी कार्यशाला आयोजन मार्च, 2023 एवं 31.05.2023 को किया गया जिसमें मुख्य कार्यकारी महोदय के हस्ताक्षर से कार्यालय विज्ञप्ति जारी किया गया। कार्यशाला से संबंधित सूचना बोर्ड पर लगाई गई। इस कार्यशाला में कार्यालय के सभी कार्मिकों ने हिस्सा लिया।

10. संघ कार्यालय के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को कार्यालयीन कार्य को अधिक से अधिक हिंदी में करने के लिए निर्देशित किया गया, जिसके उपरांत हिंदी कार्य में प्रगति देखी गई।

11. जोधपुर, राजस्थान में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के तत्वावधान में आयोजित राजभाषा सम्मेलन में हिंदी अधिकारी ने भाग लिया। सम्मेलन में माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार उपस्थित थे।

12. संघ कार्यालय की हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित त्रैमासिक रिपोर्ट भाग -1 (01 अक्तूबर, 2023 से दिसम्बर, 2023 तक) तैयार की गई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु गृह मंत्रालय को उनकी वेबसाइट पर निर्धारित प्रोफार्मा में सभी संबंधितों को ऑनलाइन प्रेषित की गई एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को भी इसकी एक-एक प्रति भिजवाई गई।

13. दिनांक 14 सितम्बर, 2023 को संघ कार्यालय द्वारा हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया। उक्त समारोह में संघ कार्यालय के 84 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया एवं इसी दिन हिंदी काव्य पाठ व कथा कहानी कहो अपनी जुबानी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया।

14. हिन्दी दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि एवं भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ कार्यालय मुख्य कार्यकारी महोदय हमारे बीच उपस्थित थे। हिन्दी दिवस समारोह के अवसर पर संस्था के 15 अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा स्वरचित कविता एवं कहानी का पाठ किया गया एवं विजेता प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया गया और सभी विजेताओं और प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र/प्रशस्ति पत्र वितरित किए गए।

15. संघ कार्यालय में दिनांक 14 - 29 सितंबर, 2023 तक हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस दौरान निम्नांकित गतिविधियाँ आयोजित की गयी:-
   i. निबंध लेखन (एम.टी.एस. से यू.डी.सी.)
   ii. निबंध लेखन (सहायक एवं उससे ऊपर के कर्मचारी एवं अधिकारी)
   iii. हिंदी टिप्पण एवं मसौदा लेखन प्रतियोगिता
   iv. हिंदी राजभाषा एवं सहकारिता ज्ञान संबंधी प्रतियोगिता
   v. हिंदी श्रुतलेख/सुलेख प्रतियोगिता (केवल एम.टी.एस. कार्मिकों हेतु)
   vi. वाद-विवाद प्रतियोगिता

16. राजभाषा हिन्दी के प्रति जागरुकता तथा उत्तरोत्तर कार्य में प्रगति लाने के उद्देश्य से संघ कार्यालय में दिनांक 29.09.2023 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया एवं उत्साहपूर्वक इस कार्यक्रम को सफल बनाया और अतिथि वक्ता ने कार्मिकों का ज्ञानवर्धन किया।

17. दिनांक 29.09.2023 को आयोजित कार्यशाला में अतिथि वक्ता व निदेशक (राजभाषा) द्वारा हिंदी पखवाड़ा के दौरान आयोजित प्रातियोगिताओं के विजेताओं को प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया व पुरस्कार की राशि श्रीमती संध्या कपूर, निदेशक (वित्त) द्वारा सभी विजेताओं के खाते में ट्रांसफर की गई। मंच का संचालन श्री राजपाल, हिंदी अधिकारी द्वारा किया गया।

18. संघ कार्यालय के विभिन्न विभागों के प्रोफार्मा/पत्रों एवं अन्य प्राप्त दस्तावेजों को हिन्दी में अनुवाद किया गया।

19. संघ कार्यालय के विभिन्न विभागों से प्राप्त अनुवाद कार्य को पूर्ण कर वांछित समय में उपलब्ध कराया गया।

20. राजभाषा नियम 1976 के नियम 8(4) के अनुरुप संबंधितों को व्यक्तिशः कार्यालय आदेश दिया गया।

21. संघ कार्यालय से प्रकाशित होने वाली अंग्रेजी पत्रिका "दॅ को-ऑपरेटर" में सहकारिता विषय से संबंधित हिन्दी के लेख प्रकाशित करने हेतु सामग्री प्रकाशन विभाग को भिजवाई गयी।

22. हिन्दी दिवस समारोह एवं पखवाड़े से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर पब्लिकेशन विभाग को द कोआपरेटर में प्रकाशन के लिए भेजी गई।

23. संघ कार्यालय से प्रकाशित होने वाली अंग्रेजी पत्रिका द को-ऑपरेटर में हिन्दी कार्यशाला से संबंधित प्रकाशन हेतु सामग्री प्रकाशन विभाग को भिजवाई गयी।

24. प्रशासनिक तथा सहकारिता से संबंधित हिन्दी शब्दों से संघ कार्यालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अवगत कराने तथा दैनिक काम.काज में इनका प्रयोग बढ़ाने के उद्देश्य से इन शब्दों के अंग्रेजी तथा हिन्दी पर्याय सप्ताह का शब्द एवं आज का सुविचार के रुप में नोटिस बोर्ड पर निरंतर लगाए / लिखे गये।

25. संघ कार्यालय के विभिन्न विभागों को हिन्दी के काम-काज में सहयोग प्रदान किया गया।

26. विभागीय राजभाषा कार्यान्वियन समिति की तिमाही बैठक का कार्यवृत्त सभी विभागों एवं राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय तथा नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति को भिजवाया गया।

27. दिनांक 14.12.2023 को तिमाही (अक्टूबर से दिसंबर) की विभागीय राजभाषा कार्यान्वियन समिति की बैठक का आयोजन सभी विभागाध्यक्षों की मौजूदगी में तथा मुख्य कार्यकारी महोदय की अध्यक्षता में हुआ।

28. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ में राजभाषा संबंधी आदेशों के कार्यान्वियन के लिए स्थापित जांच बिंदुओं के अनुपालन के संबंध में कार्यालय ज्ञापन सभी विभागाध्यक्षों को भेजा गया।

29. कार्यालयीन कार्य में हिंदी को बढावा देने के लिए मुख्य कार्यकारी महोदय के हस्ताक्षर से हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करने का आदेश जारी किया गया।

30. 17वें आईसीसी सम्मेलन में सभी विभागों को आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया और उस दौरान के सभी दस्तावेजों और विज्ञापन सामग्री को द्विभाषी रूप में हिंदी विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया।

31. सहकारी महासम्मेलन के दौरान रिपोर्टों और मसौदा भाषणों को हिंदी माध्यम में अनूदित कर संबंधित विभागों को भिजवाया गया।

32. नराकास दक्षिण दिल्ली-03 के कार्यालय के नवीनतम संपर्क नंबर एवं ई-मेल आईडी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किए गए।

33. प्रत्येक विभाग के एक कर्मचारी को जिसका अधिकाधिक कार्य हिंदी में था उन्हे प्रोत्साहन स्वरुप रु. 2500/- की राशि दी गई।

34. ऑडिट रिपोर्ट एवं एनसीयूआई कार्यालय की वार्षिक रिपोर्ट को हिंदी माध्यम में अनूदित कर आगामी कार्रवाई हेतु संबंधित विभागों को उपलब्ध कराया गया।

अध्याय 06

अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग

वर्ष 2023-24 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग ने निम्नलिखित गतिविधियाँ कीं जो कि इस प्रकार हैं :-

1. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) ने दिनांक 01 और 02 जुलाई, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र (आईईसीसी), प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 17वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन का आयोजन किया।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिनांक 01 जुलाई, 2023 को 17वें

भारतीय सहकारी महासम्मेलन का उद्घाटन किया और श्री अमित शाह, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार ने समारोह की अध्यक्षता की। 17वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन का विषय "अमृत काल: जीवंत भारत हेतु "सहकार से समृद्धि" था। इस कार्यक्रम में विभिन्न देशों के 28 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमे बांग्लादेश, ईरान, मलेशिया, नेपाल, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, मालदीव, एशियाई क्रेडिट यूनियन परिसंघ (एसीसीयू) के सदस्य, थाईलैंड और वानुअतु तथा इसके अतिरिक्त दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और दूतावासों जैसे आईएलओ, एफएओ, एएआरडीओ, आईसीए-एपी, ब्राजील दूतावास, श्रीलंका उच्चायोग, ईरान गणराज्य दूतावास, बांग्लादेश दूतावास और पापुआ न्यू गिनी दूतावास के 10 प्रतिनिधियों ने भी इस महासम्मेलन में हिस्सा लिया।

1. अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) ने सहकारी समितियों को अग्रिम पंक्ति में स्थापित करने और जी-20 में सार्थक नीतिगत चर्चा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जी-20 देशों के सबसे प्रमुख सहकारी व्यापार नेताओं को एक साथ लाने के लिए वर्ष 2021 में जी-20 कार्य समूह का गठन किया गया।

वर्ष 2022 में जी-20 की मेजबानी इंडोनेशिया ने की और वर्ष 2023 में इसकी मेजबानी भारत द्वारा की गई। आईसीए ने जी-20 समूह में

भागीदारी की सहायता के लिए ट्रोइका का गठन किया। इस ट्रोइका में इतालवी, इंडोनेशियाई और भारतीय सहकारी सदस्य शामिल थे।

इंडोनेशिया की अध्यक्षता के अंत में इस समूह ने आईसीए जी-20 के अध्यक्ष श्री हॉवर्ड ब्रोडस्की ने एनसीयूआई और आईएनकुर के साथ ऑनलाइन बैठक की। आईएनकुर ने इंडोनेशिया में जी-20 के साथ अपने अनुभव साझा किए। इस बैठक में एनसीयूआई और इफको अध्यक्ष श्री दिलीप संघाणी , आईसीए एपी अध्यक्ष डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव और एनसीयूआई के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। श्री दिलीप संघाणी और डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव के नेतृत्व में एनसीयूआई ने भारत के जी-20 समूह की जिम्मेदारी संभाली। इसके दौरान देश में सहकारी संस्थाओं और सदस्यों को संगठित करने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई। इसी

के अंतर्गत श्री दिलीप संघाणी , डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव, डॉ. बिजेंद्र सिंह और एनसीयूआई उप मुख्य कार्यकारी जैसे वरिष्ठ सहकारी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत के जी-20 प्रेसीडेंसी के शेरपा श्री अमिताभ कांत से मुलाकात की।

एनसीयूआई ने शेरपा द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत अन्य हितधारकों से भी संपर्क किया गया और भारत में सभी सहकारी संस्थाओं को व्यवसाय-20, नागरिक समाज- 20, महिला-20 और

युवा-20 जैसे विभिन्न कार्य समूहों के साथ पंजीकरण करने और जुड़ने के लिए आमंत्रित किया गया। एनसीयूआई ने सुनिश्चित किया कि सभी बैठकों और कार्यक्रमों में सहकारी सदस्यों की उपस्थिति हो। इसी के तहत जनवरी, 2023 में अहमदाबाद, गुजरात में आयोजित बी-20 की निरीक्षण बैठक में भाग लेने के लिए श्री दिलीप संघाणी , डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव और श्रीमती सावित्री सिंह, उप मुख्य कार्यकारी

को आमंत्रित किया गया।

इन कार्यक्रमों की चर्चाओं में सक्रिय योगदान और नीति दस्तावेजों में इनपुट प्रदान करके एनसीयूआई ने सुनिश्चित किया कि समावेशी सतत विकास में सहकारी समितियों के योगदान को विधिवत मान्यता और स्वीकृति मिले। यह बेहद खुशी की बात है कि जी-20, भारत रिपोर्ट-2023 में सहकारी समितियों के काम को विभिन्न समूहों (बी-20 पॉलिसी पैक और सी-20 पॉलिसी पैक) में विस्तार से शामिल किया गया जिनका विवरण इस प्रकार हैं: -

1. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) के सहयोग से सार्क देशों के सदस्यों के लिए सिसटैब (सीआईसीटीएबी) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

1.1. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) ने अंतर्राष्ट्रीय कृषि बैंकिंग सहयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र (सीआईसीटीएबी) पुणे और पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी संघ, कोलकाता के साथ मिलकर दिनांक 21 से 24 नवंबर, 2023 तक कोलकाता में "सहकारी समितियों और ग्रामीण वित्तपोषण संस्थानों के सीईओ और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए सहकारी शासन" पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया।

इस कार्यक्रम का उद्घाटन श्री प्रदीप मजूमदार, माननीय मंत्री (एमआईसी), सहकारिता विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किया गया । इस कार्यक्रम में श्री स्वर्ण कमल साहा, विधायक, पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी संघ अध्यक्ष, डॉ. सुधीर महाजन, मुख्य कार्यकारी, एनसीयूआई, श्रीमति सावित्री सिंह, उप मुख्य कार्यकारी, एनसीयूआई, संगीता साधु, डीआरसीएस, मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

डब्ल्यूबीएससीयू जैसे अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। भारत और नेपाल के सीई, निदेशक मंडल, वरिष्ठ, मध्यम स्तर के अधिकारी और प्रशिक्षकों सहित कुल 31 प्रतिभागियों ने चार दिवसीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में बर्ड (बीआईआरडी), नाबार्ड, आईसीएमएआरडी, वैमनीकॉम और पश्चिम बंगाल सरकार के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार कार्यालय जैसे प्रमुख संस्थानों के संसाधन व्यक्तियों द्वारा भाग लिया गया। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों के लिए कुल 11 सत्र आयोजित किए गए। इसमें शामिल कुछ महत्वपूर्ण विषयों में सहकारी शासन - एक दृष्टि , बोर्ड मीटिंग का संचालन, वित्तीय निर्णय लेने के साधन, निर्णय लेने में मानव संसाधन मुद्दे, सहकारी समितियों और आरएफआई के लिए सूचना प्रौद्योगिकी शासन आदि विषय शामिल थे। सहकारी समितियों के कामकाज को समझने के लिए मुदियाली मछुआरा सहकारी समिति और बनिबन, जदीसपुर, दुलोपुर राजापुर एस.के.यू.एस. लिमिटेड का एक दिवसीय क्षेत्रीय दौरा भी आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की सभी प्रतिभागियों के साथ-साथ संसाधन व्यक्तियों ने भी इस कार्यक्रम की भरपूर सराहना की।

1.2. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) ने अंतरराष्ट्रीय कृषि बैंकिंग सहयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र (सीआईसीटीएबी) पुणे के साथ मिलकर एनसीयूआई, नई दिल्ली में दिनांक 05 से 09 मार्च, 2024 तक सहकारी समितियों और ग्रामीण वित्त पोषण संस्थाओं की महिला निदेशक मंडल के लिए सहकारी शासन पर एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया। इस पांच दिवसीय कार्यक्रम में भारत और नेपाल के सीईओ, निदेशक मंडल, वरिष्ठ, मध्यम स्तर के अधिकारी और प्रशिक्षकों सहित कुल 28 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

इस कार्यक्रम में 12 सत्रों की व्यवस्था की गई थी। उपरोक्त विषयों पर इन सत्रों के अलावा प्रतिभागियों ने कार्य योजना की प्रस्तुति के साथ-साथ भारत और नेपाल के अपने-अपने संगठनों के संदर्भ में भी प्रस्तुतियाँ दीं। सहकारी समितियों के कामकाज को समझने के लिए आगरा का एक दिवसीय क्षेत्रीय दौरा भी आयोजित किया गया जिसकी सभी प्रतिभागियों के साथ-साथ संसाधन व्यक्तियों ने भी भरपूर सराहना की।

1.1. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) और कृषि बैंकिंग में अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र (सीआईसीटीएबी) पुणे और अमरेली जिला सहकारी संघ ने दिनांक 18 से 21 मार्च, 2024 तक अमरेली, गुजरात में "सहकारी विकास के लिए परियोजना दृष्टिकोण पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमे एनसीयूआई सहकारी शिक्षा क्षेत्र परियोजना के अनुभवों को साझा करना" नामक विषय पर एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया । इस चार दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में श्रीलंका, नेपाल और भारत के कुल 33 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों में सीईओ, निदेशक मंडल, वरिष्ठ/मध्यम स्तर के अधिकारी, प्रशिक्षक और सार्क क्षेत्र के देशों में सहकारी समितियों के राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों और ग्रामीण वित्तपोषण संस्थानों के प्रशिक्षक शामिल थे। इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में एनसीयूआई अध्यक्ष श्री दिलीप संघाणी सहित कई प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम में अमरेली जिला सहकारी संघ अध्यक्ष मनीष संघाणी और एनसीयूआई महिला समिति की सदस्य सुश्री भावना गोंदलिया भी मौजूद थी।

भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आए परियोजना अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में अपने अनुभव साझा किए। इसमे प्रतिभागियों ने

अपने संगठन पर प्रस्तुतियाँ भी दीं और कार्य योजना भी तैयार की। यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के सभी प्रतिभागियों और संसाधन व्यक्तियों ने इसकी सराहना की। कार्यक्रम के समापन के समय फीडबैक

सत्र में प्रतिभागियों ने कार्यक्रम की खूब सराहना की और इस तरह से इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।

1. अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग को सीआईसीटीएबी द्वारा

आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संगठन के समन्वय का कार्य सौंपा गया। सीआईसीटीएबी अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए एनसीयूआई के सदस्य संगठनों से उपयुक्त उम्मीदवारों के नामांकन आमंत्रित किए गए और उन्हें सीआईसीटीएबी को भेज दिया गया।

3. ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, सम्मेलन, कार्यशालाओं और बैठकों में भागीदारी

दिनांक 27 से 30 जुलाई, 2023 तक मलेशिया के सबा में आईसीए एशिया पैसिफिक (आईसीए-एपी) क्षेत्रीय कार्यालय ने एशिया पैसिफिक कोऑपरेटिव यूथ समिट (एपीसीवाईएस 4.0) के चौथे संस्करण का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का विषय "मानव जीवन शैली में सहकार की भूमिका " और हरित ग्रह के लिए स्थायी जीवन शैली को आगे बढ़ाने में युवाओं की भूमिका पर चर्चा की गई।

गई। आईसीए-एपी क्षेत्रीय कार्यालय ने मलेशियाई राष्ट्रीय सहकारी आंदोलन (एएनजीकेएएसए), युवा सहयोग पर आईसीए-एपी समिति (आईसीवाईसी) और पूर्वी मलेशिया के सबा में आईसीए डोमस ट्रस्ट के सहयोग से इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह युवा सहकारिताओं के लिए सहकारी समितियों पर नए और टिकाऊ उद्यम विचारों को खोजने और पेश करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। एनसीयूआई की युवा सहकारिता समिति के तीन सदस्यों को एपीसीवाईएस 4.0 में भाग लेने के लिए नामित किया गया था।

2.1. दिनांक 03 से 06 अक्टूबर, 2023 को आईआरयू की आम बैठक का बॉन, जर्मनी में आयोजन - अंतर्राष्ट्रीय रायफिसेन यूनियन (आईआरयू)

इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में प्रतिभागियों का एक विविध समूह एक साथ आया जिसमें दुनिया भर के आईआरयू सदस्य संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 35 से अधिक सहकर्मी शामिल थे। एनसीयूआई अध्यक्ष श्री दिलीप संघाणी अंतर्राष्ट्रीय रायफिसेन यूनियन (आईआरयू) बोर्ड सदस्य के पद पर बरकरार हैं।

एनसीयूआई प्रतिनिधिमंडल ने काठमांडू, नेपाल में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में कृषि सहकारी समितियों के विकास के लिए नेटवर्क (एनईडीएसी) द्वारा आयोजित जलवायु परिवर्तन से संबन्धित अन्य विषयों और सहकारी क्षेत्र के वर्तमान रुझानों, संभावनाओं और चुनौतियों पर कार्यकारी समिति की बैठक में भाग लिया और एनईडीएसी/एनसीबीएल कार्यशाला में भी भाग लिया। इस प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीएफ) और नेपाल के भूमि प्रबंधन, सहकारिता और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (एमओएलसीपीए) द्वारा आयोजित तीसरे राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन में भी भाग लिया।

2.2. अंतर्राष्ट्रीय रायफिसेन यूनियन (आईआरयू) का मुख्य उद्देश्य रायफिसेन के विचारों को बढ़ावा देना, उन्हें खुले तौर पर प्रचारित करना और सभी के सामने अनुभवों का आदान-प्रदान करना है। आईआरयू बोर्ड और प्रेसीडियम की बैठक मंगलवार, दिनांक 20 जून, 2023 को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की गई। इसमें एनसीयूआई अध्यक्ष श्री दिलीपभाई संघाणी और एनसीयूआई उप मुख्य कार्यकारी श्रीमती सावित्री सिंह ने भाग लिया।

2.3. दिनांक 30 मई, 2023 को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वित्तीय समावेशन पर टास्क फोर्स की चौथी बैठक में एनसीयूआई अध्यक्ष श्री दिलीपभाई संघाणी और एनसीयूआई उप मुख्य कार्यकारी श्रीमती सावित्री सिंह ने भाग लिया।

2.4 दिनांक 14 जून, 2023 को आईसीए ने एक ऑनलाइन सूचनात्मक बैठक आयोजित की। इस बैठक में आईसीए के एसोसिएशन के लेखों (एओए) में किए गए संशोधनों के बारे में बताया गया। इस बैठक में उप मुख्य कार्यकारी श्रीमती सावित्री सिंह ने भाग लिया।

2.5. दिनांक 6 से 10 नवंबर, 2023 तक मनीला, फिलीपींस में 16वीं आईसीए- एपी क्षेत्रीय सभा, 11वीं सहकारी फोरम, समिति की बैठकें और अन्य संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस क्षेत्रीय सभा के कार्यक्रमों की मेजबानी फिलीपींस सहकारी आंदोलन की ओर से फिलीपींस सहकारी संबद्ध (पीसीए) द्वारा की गई। सहकारी फोरम और समिति के कुछ कार्यक्रमों के माध्यम से, आईसीए- एपी ने सहकारी समितियों के लिए एक साझा एजेंडा बनाने और अन्य चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया। एनसीयूआई प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्रीय सभा और अन्य संबंधित कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया।

2.6 नेडाक महासभा और एक्सकोम बैठक-2023 दिनांक 5 से 8 नवंबर, 2023 को मनीला, फिलीपींस में आयोजित की गई। यह बैठक 11वें एशिया-प्रशांत सहकारी मंच के सहयोग से हुई। इसमे एनसीयूआई अध्यक्ष श्री दिलीपभाई संघाणी, आईसीए -एपी अध्यक्ष डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव, उप मुख्य कार्यकारी श्रीमती सावित्री सिंह और श्री रितेश दे, निदेशक, एनसीयूआई ने हिस्सा लिया।

2.7 दिनांक 30-31 जुलाई, 2023 को जयपुर, राजस्थान में सी-20 एंगेजमेंट ग्रुप के शिक्षा और डिजिटल परिवर्तन कार्य समूह ने श्रीमती सावित्री सिंह, उप मुख्य कार्यकारी को इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। इस कार्यक्रम में श्रीमती सावित्री सिंह, उप मुख्य कार्यकारी ने जयपुर के इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

2.8 नेडाक प्रशिक्षण केंद्र, बैंकॉक (एनटीसीबी) द्वारा एशिया-प्रशांत ग्रामीण और कृषि ऋण संघ, थाईलैंड और अंतर्राष्ट्रीय सहकारी बैंकिंग संघ (आईसीबीए), भारत के सहयोग से "कृषि सहकारी समितियों के लिए सतत वित्तपोषण और सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करना" पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला बैंकॉक, थाईलैंड में दिनांक 22 से 24 अगस्त, 2023 तक आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य सहकारी किसानों और उद्योग जगत

के नेताओं को लचीले और पर्यावरण के प्रति जागरूक कृषि पद्धतियों के निर्माण के लिए ज्ञान और उपकरणों से सशक्त बनाना था।

2.9 दिनांक 25 से 27 अगस्त, 2023 तक नई दिल्ली में बी-20 शिखर सम्मेलन-2023 आयोजित किया गया। । तीन दिवसीय बी-20 इंडिया शिखर सम्मेलन का समापन करते हुए बी-20 इंडिया

सचिवालय ने वर्ष 2024 में जी-20 की मेजबानी के लिए ब्राज़ील को अध्यक्षता सौंपी। इस कार्यक्रम नें एनसीयूआई अध्यक्ष और उप मुख्य कार्यकारी ने हिस्सा लिया।

2.10 दिनांक 19-20 सितंबर 2023 को टोक्यो, जापान में आईसीए-एपी महिला समिति ने महिला समिति के 25वें वर्षगांठ समारोह के लिए एक कार्यक्रम पुस्तिका तैयार की। । इसमे "सदस्य संगठनों का परिचय" पर एक लेख तैयार किया गया और पुस्तिका में शामिल करने के लिए भेजा गया।

2.11 आईसीए-एपी महिला समिति अध्यक्ष सुश्री चिटोसे आराई ने उप मुख्य कार्यकारी श्रीमती सावित्री सिंह से संपर्क किया और बताया कि समिति ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उन्होंने श्रीमती सावित्री सिंह से एक विशेष संदेश मांगा जिसे तैयार करके पुस्तिका में शामिल करने के लिए सुश्री आराई को भेजा गया।

2.12. दिनांक 29 जुलाई से 31 अगस्त, 2023 तक जयपुर में आयोजित जी-20 के आधिकारिक सहभागिता समूह सिविल-20 (सी-20) का अंतिम शिखर सम्मेलन वैश्विक सहयोग और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य आकर्षण सी-20 विज्ञप्ति, एक व्यापक सर्वेक्षण और इसके 16 कार्य समूहों द्वारा विकसित नीतिगत सिफारिशें प्रस्तुत करना था। भारत के नेतृत्व में सी-20 ने "जन भागीदारी" या लोगों की भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। इसमें ग्लोबल साउथ सहित 74 देशों के 184,000 से अधिक व्यक्तियों के साथ सी-20 की गतिविधियों में सम्मेलनों और कार्यशालाओं से लेकर "चौपालों" और व्यक्तिगत और ऑनलाइन कार्यक्रमों की एक विविध श्रृंखला शामिल थी। इस शिखर सम्मेलन में श्रीमती सावित्री सिंह, उप मुख्य कार्यकारी, एनसीयूआई ने भाग लिया और प्रतिनिधित्व किया।

2.13 श्री कोंग शान, महानिदेशक, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी विभाग, अखिल चीन आपूर्ति एवं विपणन सहकारी संघ (एसीएफएसएमसी) ने एनसीयूआई से आईसीए सहकारी आपूर्ति श्रृंखला मेले और सहकारी व्यापार एवं विकास पर आईसीए संगोष्ठी एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए एनसीयूआई से एक प्रतिनिधि को नामित करने का अनुरोध किया। श्री दिनेशभाई अमथाराम सुथार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गुजरात राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (गुजकोमासोल) को उपरोक्त कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए एनसीयूआई से नामित किया गया।

2.14 सुश्री किम, केंद्रीय कृषि सहकारी संघ (जेए-ज़ेंचू) ने उन प्रतिनिधियों के नाम की पुष्टि करने का अनुरोध किया हैं जिनके 12-13 मार्च, 2024 को टोक्यो, जापान में आयोजित एशियाई किसान समूह सहयोग (एएफजीसी) हाइब्रिड बैठक में भाग लेने और शामिल होने की उम्मीद है। उप मुख्य कार्यकारी ने एएफजीसी बैठक में ऑनलाइन मोड में भाग लिया और मुख्य विषय "बढ़ती उत्पादन लागत से निपटना: टिकाऊ कृषि के लिए हमारे तरीके, विधियाँ और अभ्यास" पर अपनी प्रस्तुति दी।

2.15 एनसीयूआई उप मुख्य कार्यकारी ने 13 मार्च, 2024 को श्रीलंका की राष्ट्रीय सहकारी परिषद के मुख्यालय सभागार में आयोजित महिला उद्यमी विकास कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में मुख्य भाषण दिया।

3 -अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां

3.1. आईसीए-एपी क्षेत्रीय कार्यालय ने एनसीयूआई से उनके द्विवार्षिक प्रकाशन, कॉप डायलॉग के बारे में संपर्क किया जिसमें एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सहकारी समितियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाती है। मई, 2023 में कॉप डायलॉग-4 जारी किया गया। इसका विषय 'एसडीजी में सहकारी समितियों का योगदान और उपलब्धियां और आगे का रास्ता।' था। वर्ष 2023 सतत विकास के लिए एजेंडा-2030- और 17 एसडीजी के कार्यान्वयन का मध्य बिंदु है। उन्होंने 2015 में शुरू किए गए आईसीए के कॉप्सफॉर-2030 अभियान के लिए एनसीयूआई द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं की प्रगति को प्रदर्शित करने के लिए एक लेख तैयार किया। इसमे एनसीयूआई ने निम्नलिखित सुनिश्चित किया कि :-

कार्य क्षेत्र — प्रतिज्ञा — बुनियादी वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए हम सहकारी क्षेत्रीय संघों के माध्यम से एक वैकल्पिक व्यवसाय मॉडल के रुप में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने, विकसित करने, प्रोत्साहित करने और समर्थन देने का संकल्प लेते हैं। हम सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हैं और सहकारी क्षेत्र में मानव संसाधनों को पेशेवर बनाने का भी प्रयास करते हैं।

इस संदर्भ में एक रिपोर्ट तैयार कर आईसीए-एपी क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत की गई।

3.1 डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव, आईसीए-एपी अध्यक्ष का वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया गया जिसमें उन्होंने दुनिया भर के सहकारी नेताओं से 17वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन में ऑनलाइन माध्यम से शामिल होने का अनुरोध किया था। वीडियो संदेश एनसीयूआई और आईसीए-एपी के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया।

- आईसीए-एपी क्षेत्रीय कार्यालय ने आईसीए-एपी सहकारी उत्कृष्टता पुरस्कारों के लिए नामांकन का अनुरोध किया जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में सहकारी समितियों के असाधारण योगदान और उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ये

पुरस्कार निम्नलिखित तीन अलग-अलग श्रेणियों में प्रदान किए गए:

- प्रेरणादायक सहकारी नेता पुरस्कार
- उद्यमी सहकारी पुरस्कार
- सक्षम सरकारी पुरस्कार

16वीं आईसीए-एपी क्षेत्रीय सभा में विजेताओं की घोषणा की गई। यह सभा दिनांक 08 नवंबर, 2023 को मनीला, फिलीपींस में आयोजित की गई। सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद एनसीयूआई के सभी सदस्य संस्थानों को एक ईमेल भेजा गया जिसमें भाग लेने और संबंधित नामांकन फॉर्म ऑनलाइन भरने का अनुरोध किया गया। एनसीयूआई की ओर से प्रेरणादायक सहकारी नेता पुरस्कार के लिए श्री बी.एस. विश्वनाथन जी का नामांकन भेजा गया।

3.2 सुश्री ग्रेटचेन हैक्चार्ड, आईसीए की सदस्यता निदेशक ने

एनसीयूआई से आईसीए सदस्य पुष्टिकरण और डेटा फॉर्म 2023 को विधिवत रूप से भरने का अनुरोध किया ताकि एनसीयूआई की पात्रता स्पष्ट हो सके और सदस्यों के रजिस्टर के लिए आवश्यक जानकारी एकत्रित की जा सके। इससे संबन्धित विधिवत भरा हुआ फॉर्म आईसीए को प्रस्तुत किया गया।

3.3 दिनांक 30 अक्तूबर, 2023 को मर्कोसुर समूह (अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे और उरुग्वे) के बीस सहकारी नेताओं और भारत में ब्राजील के दूतावास के अधिकारियों के एक समूह ने एनसीयूआई का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ब्राज़ील के कृषि मंत्री ने किया जो कि भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे। इस प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय सहकारी आंदोलन के बारे में जानने के साथ-साथ व्यावसायिक अवसरों पर चर्चा करने में भी रुचि दिखाई। इस बैठक में एनसीयूआई अध्यक्ष, आईसीए-एपी अध्यक्ष, नेफेड अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी, उप मुख्य कार्यकारी और एनसीयूआई के अन्य वरिष्ठ अधिकारी इत्यादि शामिल हुए।

3.4 भारत में ब्राज़ील दूतावा के श्री एंजेलो डे क्विरोज़ मौरिसियो, कृषि अटैची ने एनसीयूआई अध्यक्ष श्री दिलीप संघाणी को आगामी "कृषि व्यवसाय क्षेत्र में भारत-ब्राजील संबंधों की संभावनाएँ और भविष्य" सेमिनार में आमंत्रित किया। यह सेमिनार दिनांक 02 नवंबर, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। यह ब्राज़ील के माननीय कृषि और पशुधन मंत्री, महामहिम मंत्री कार्लोस फ़ेवरो की आधिकारिक यात्रा थी। उन्होंने ब्राज़ील के कृषि क्षेत्र के तीस से अधिक प्रमुख संस्थानों और कंपनियों के साथ एक प्रतिष्ठित मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। एनसीयूआई अध्यक्ष और एनसीयूआई उप मुख्य कार्यकारी ने इस सेमिनार में भाग लिया।

3.5 युवा सहकार पर आईसीए-एपी समिति (आईसीवाईसी) की शुरुआत वर्ष 2000 के शुरु में हुई। इस समिति के उद्देश्यों में सहकारी समितियों में युवाओं के बीच यात्राओं, ज्ञान और जानकारी तथा गतिविधियों के आदान-प्रदान के माध्यम से मजबूत करना और प्रोत्साहित करना शामिल था। इसके अतिरिक्त युवाओं को सहकारी समितियों के सक्रिय सदस्य, कर्मचारी और नेता बनने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें सहभागी लोकतंत्र सीखने में मदद करना, सदस्य शिक्षा/प्रचार, सदस्य भागीदारी आदि के माध्यम से युवाओं द्वारा सहकारी समितियों की व्यावसायिक गतिविधियों को मजबूत करना हैं । श्री अनुराग, सहायक निदेशक, एनसीयूआई को आईसीवाईसी के सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए नामित किया गया।

3.6. श्री इचिरो नाकामोरी, एनएफयूसीए प्रबंध निदेशक और सीईओ ने एनसीयूआई मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधीर महाजन से दिनांक 16 दिसंबर, 2023 को निर्धारित नेशनल फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी को-ऑपरेटिव एसोसिएशन (एनएफयूसीए) की 67वीं वार्षिक आम बैठक के लिए एक संदेश भेजने का अनुरोध किया। यह संदेश एनएफयूसीए को भेजा गया।

3.7. डॉ. हेमा यादव, सदस्य सचिव और निदेशक, सिसटैब (सीआईसीटीएबी) ने एनसीयूआई से दिनांक 14 और 15 दिसंबर,2023 को नई दिल्ली में आयोजित सिसटैब प्रबंध समिति की 54वीं बैठक और सामान्य परिषद की 24वीं बैठक में भाग लेने का अनुरोध किया। यह प्रबंध समिति की बैठक श्री विजय कुमार, आईएएस, विशेष सचिव की अध्यक्षता में हुई और सामान्य परिषद की बैठक श्री ज्ञानेश कुमार, आईएएस, सचिव, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अध्यक्षता में हुई। इन दोनों बैठकों में उप मुख्य कार्यकारी ने भाग लिया।

3.8 श्री कोर्बिनियन मार्ज, समन्वयक सचिवालय जनरल, अंतर्राष्ट्रीय रायफिसेन संघ (आईआरयू) ने एनसीयूआई से 22 दिसंबर तक जारी आईआरयू शीतकालीन समाचार पत्रों में शामिल करने के लिए एनसीयूआई से उल्लेखनीय अपडेट, उपलब्धियां या कार्यक्रम साझा करने का अनुरोध किया। यह एनसीयूआई द्वारा किए गए प्रभावशाली कार्यों और सकारात्मक विकास को प्रदर्शित करने का एक उत्कृष्ट अवसर था। वर्ष 2021-23 के दौरान एनसीयूआई की उपलब्धियों की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति आईआरयू शीतकालीन समाचारपत्र में शामिल करने के लिए साझा की गई थी।

3.9 दिनांक 15 दिसंबर, 2023 को सिसटैब (सीआईसीटीएबी) सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के एक समूह ने एनसीयूआई का दौरा किया। इस दौरे में नेपाल के राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीएफ) की महाप्रबंधक सुश्री चित्रा कुमार थमसुहांग सुभा, आरबीआई-सीएबी, पुणे डीजीएम और वित्त मंत्रालय के श्री नारायण, एनआईबीएम के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. नवीन कुमार और सीआईसीटीएबी के सलाहकार डॉ. डी रवि शामिल थे। मुख्य कार्यकारी डॉ. सुधीर महाजन और उप मुख्य कार्यकारी श्रीमती सावित्री सिंह ने प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। श्री रितेश दे, निदेशक ने एनसीयूआई की भूमिका और गतिविधियों पर एक प्रस्तुति दी।

3.10 जापान सरकार के कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन मंत्रालय (एमएएफएफ) के सहयोग से और एशिया में कृषि सहयोग के विकास के लिए संस्थान (आईडीएसीए) के साथ साझेदारी में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) ने "कृषि सहकारी समितियों के विकास के माध्यम से चुनौतियों का जवाब देने के लिए किसानों की क्षमता निर्माण - वित्त वर्ष 2023-24" पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में "ग्रामीण समुदायों में सतत कृषि को बढ़ावा देना" पर एक वीडियो कार्यक्रम आयोजित किया। इसमे किसान संगठनों को

बढ़ावा देने के लिए जापानी कृषि सहकारी प्रणाली और सरकारी नीतियों के बारे में आठ पूर्व-रिकॉर्ड व्याख्यान वीडियो तैयार किए गए। यह वीडियो 03 फरवरी, 2024 तक देखने के लिए उपलब्ध थे। एनसीयूआई के सभी सदस्य संस्थानों से अनुरोध किया गया कि वे उपयुक्त नामांकन प्रस्तुत करके इस अवसर का लाभ उठाएं।

3.11 दिनांक 25 जनवरी, 2024 गुरुवार को विश्व सहकारी मॉनिटर का 12वां संस्करण लॉन्च किया गया। भारत की उर्वरक सहकारी दिग्गज इफको और भारत की डेयरी सहकारी अमूल ने सहकारी मॉनिटर में पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। सहकारी मॉनिटर में अपना स्थान पाने वाले अन्य संगठन कृभको, यूएलसीसीएस, केरल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, कॉसमॉस सहकारी बैंक लिमिटेड, एसवीसी बैंक लिमिटेड, मध्य प्रदेश सहकारी बैंक लिमिटेड, बुलढाणा शहरी सहकारी ऋण सोसायटी लिमिटेड, टीजेएस बैंक लिमिटेड, उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लिमिटेड, गुजरात राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, सारस्वत सहकारी बैंक लिमिटेड, कर्नाटक राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड इत्यादि थे।

3.12 अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) के नीति निदेशक श्री जोसेफ न्जुगुना ने जी-20 और जी-7 सहभागिता समूहों में इस वर्ष की सहकारी समितियों की सहभागिता पर नवीनतम जानकारी एनसीयूआई को दी। ये समूह ब्राजील की जी-20 अध्यक्षता के तहत बिजनेस-20 (बी20) और सिविल-20 (सी20) तथा इतालवी जी-7 अध्यक्षता के तहत सी-7 और बी-7 इत्यादि हैं। आईसीए का लक्ष्य जी-20/जी-7 संचालन समिति बनाना है जो बी-20/सी-20 और बी-7/सी-7 में भाग लेने वाले सहकारी प्रतिनिधियों को टास्क फोर्स में उनकी भागीदारी बढ़ाने में सहायता करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि सतत विकास में सहकारी समितियों के योगदान को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं द्वारा मान्यता मिले। जी-20 और जी-7 कार्य समूहों में आईसीए सदस्यों की सहभागिता पर नवीनतम जानकारी भी साझा की गई। उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी को संचालन समिति तथा सी-20 और सी-7 के विभिन्न कार्य समूहों के सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए पंजीकृत किया गया।

3.13 भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) ने 8 मार्च, 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। इस अवसर पर मणिपुर की विश्व युवा महिला मुक्केबाजी चैंपियन सुश्री सरजूबाला देवी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता एनसीयूआई अध्यक्ष ने की।

3.14 अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) ने एनसीयूआई को सूचित किया कि आईसीए आवास सहकारी समितियों पर कानूनों का संकलन कर उनका विश्लेषण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी अनुसंधान और विश्लेषण पहल (आईएलआरएआई) शुरू कर रहा है जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025 के दौरान एक रिपोर्ट और लाइव डेटाबेस लॉन्च करना है। आईसीए ने कनाडा, स्वीडन और जिम्बाब्वे में आवास सहकारी समितियों के साथ परीक्षण किए हैं और वह चाहता है कि भारत भी इस प्रशिक्षण के चरण में चौथा देश बने। एनसीयूआई को इसमें भाग लेने और देश में आवास सहकारी समितियों को नियंत्रित करने वाले कानूनों पर विशेषज्ञता और जानकारी लाने और आईसीए को इस पहल को बड़े पैमाने पर ले जाने में मदद करने के लिए आमंत्रित किया गया है। आईसीए उत्तरदाताओं के साथ एक ऑनलाइन बैठक करेगा और आवास सहकारी समितियों पर कानूनों पर अपनी रिपोर्ट में प्रतिक्रियाओं को एकीकृत करेगा जिसे संभवत संयुक्त राष्ट्र आईवाईसी द्वारा जारी किया जाएगा और उससे पहले इस वर्ष नवंबर में नई दिल्ली में प्रस्तावित सम्मेलन के दौरान चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। एनसीएचएफ प्रबंध निदेशक से अनुरोध किया गया कि वे प्रश्नावली भरें और उसे आईसीए को प्रस्तुत करें।

4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता: एनसीयूआई ने निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की अपनी सदस्यता का नवीनीकरण किया:

- अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए)
- एशिया में कृषि सहकारी समितियों के विकास के लिए नेटवर्क (एनईडीएसी)
- अंतर्राष्ट्रीय रायफिसेन संघ (आईआरयू)
- कृषि बैंकिंग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रशिक्षण केंद्र (सीआईसीटीएबी)

अध्याय 07

कॉप कनेक्ट विभाग

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ ने स्कूल और कॉलेज के छात्रों को सहकारिता से परिचित कराने के लिए "कॉप कनेक्ट" नामक प्रभाग की स्थापना की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को यह सिखाना है कि सहकारी समितियाँ किस तरह से खुद के लिए और दूसरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त अपनी खुद की सहकारी समितियों का गठन और प्रबंधन करना सीखकर छात्र अपने लिए रोजगार सुरक्षित करने, दूसरों के लिए रोजगार सृजित करने और अपने समुदायों में सार्थक योगदान देने के कौशल हासिल करते हैं। इसके माध्यम से छात्रों को सहकारी प्रबंधन के आवश्यक सिद्धांत सिखाए जाते हैं जिससे उन्हें इस क्षेत्र की अनूठी विशेषताओं को समझने, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव और सहकारी व्यवसाय मॉडल के बारें में जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलती है। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सहकारी समितियों के बारें में जागरूक करना है और उनके फ़ायदों के बारें में विस्तार से अवगत कराना हैं। । गत वर्ष के दौरान पूरे देश से 5282 प्रतिभागियों के साथ 59 गतिविधियाँ आयोजित की हैं। कॉप कनेक्ट विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं। इसके अंतर्गत प्रमुख कार्यक्रम, "सफल सहकारी व्यवसाय मॉडल", ऑनलाइन, ऑफ़लाइन और हाइब्रिड मोड में पेश किया जाता है। इस मुख्य कार्यक्रम के अलावा कॉप कनेक्ट विभिन्न प्रतिस्पर्धी कार्यक्रमों की मेजबानी करता है जिसमें ड्राइंग प्रतियोगिता, वाद-विवाद, निबंध लेखन और सहकारी प्रश्नोत्तरी इत्यादि शामिल हैं। दिनांक 03 से 08 नवंबर, 2023 के बीच आयोजित सहकारी मेले के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों और स्कूलों के 750 से अधिक छात्रों ने इन गतिविधियों में हिस्सा लिया।

कॉप कनेक्ट विभाग द्वारा छात्रों के लिए इफको, एनसीएचएफ, एनसीयूआई इनक्यूबेशन सेंटर और एनसीयूआई हाट जैसे सफल सहकारी संगठनों में अध्ययन,शैक्षणिक,एक्सपोजर और औद्योगिक दौरे भी आयोजित किए गए। वर्ष 2023-24 के दौरान कॉप कनेक्ट ने

प्रबंधन संस्थानों, केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों, और केंद्रीय विद्यालयों सहित विभिन्न संस्थानों के छात्रों को प्रशिक्षित भी किया।

वर्ष 2023-24 के दौरान कॉप कनेक्ट विभाग ने कई

उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। इसके तहत हजारों छात्रों को प्रशिक्षण देने के अलावा असम, गुजरात, कर्नाटक, मणिपुर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली (एनसीआर), हरियाणा, मेघालय, राजस्थान, ओडिशा, पंजाब, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और नागालैंड सहित देश के विभिन्न राज्यों में अपनी पहुँच का विस्तार भी किया है। इसके अतिरिक्त विभाग सहकारिता के विभिन्न पहलुओं और एनसीयूआई और सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई

पहलों के बारे में भी सभी संबंधितों को जानकारी प्रदान करता है और जागरूकता बढ़ाता है। इस तरह के कार्यक्रम सफल सहकारी व्यवसाय मॉडल, एनसीडीसी की युवा सहकार योजना, नवीन व्यावसायिक विचार, सहकारी समितियों में रोजगार के अवसर, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों की भूमिका, एनसीयूआई और सहकारिता मंत्रालय द्वारा नई पहल, एनसीयूआई हाट, इनक्यूबेशन सेंटर और नोएडा (यूपी) में कौशल विकास केंद्र सहित कई विषयों को कवर भी करते हैं।

अध्याय 08

राष्ट्रीय सहकारी डाटा बैंक (एनसीडीबी)

वर्ष 2023-2024 के दौरान एनसीडीबी विभाग ने विभिन्न पहलों में सक्रिय रूप से भाग लिया। राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस (एनसीडी) पोर्टल के विकास और रखरखाव में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसके साथ ही सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस रिपोर्ट तैयार करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस परियोजना की शुरुआत से लेकर इसके सफल विमोचन तक विभाग द्वारा सहायता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त डेटा संग्रह, रिपोर्टिंग और हितधारक जुड़ाव के लिए विभाग ने सहकारी क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाई हैं।

राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस (एनसीडी पोर्टल) का विकास:
बैठकों का आयोजन:

एनसीडीबी के प्रतिनिधियों ने एनसीडी के लिए संचालन समिति और परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी/पीएमयू) की विभिन्न बैठकों में भी भाग लिया और परियोजना के दूसरे और तीसरे चरण के लिए बहुमूल्य इनपुट प्रदान किए। इन चरणों में श्रम, विपणन, उपभोक्ता, आवास, महिला, चीनी, राष्ट्रीय स्तर के महासंघ, राज्य/जिला सहकारी संघ/महासंघ और अन्य सहकारी समितियों से संबंधित डेटा शामिल हैं और विशेष रुप से जिन्हें चरण में शामिल नहीं किया गया था।

प्रशिक्षुओं, डेटा एंट्री ऑपरेटरों (डीईओ) और नोडल अधिकारियों के भुगतान विवरण तैयार करने में सहायता के लिए सहकारिता मंत्रालय के डेटा एनालिटिक्स डिवीजन में प्रभागीय कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की गई। उन्होंने अगस्त 2023 तक डेटा प्रविष्टि कार्य के लिए वजीफ़ा और मानदेय का समय पर जारी होना सुनिश्चित करने के लिए एनसीयूआई और मंत्रालय के बीच समन्वय भी किया।

वर्ष 2023-24 के दौरान विभाग ने एनसीडी पोर्टल पर विभिन्न सहकारी समितियों के लिए डेटा प्रविष्टि में शामिल प्रशिक्षुओं, डीईओ और नोडल अधिकारियों को वजीफा और मानदेय वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके तहत कुल मिलाकर 1,802 डीईओ, प्रशिक्षु और नोडल अधिकारियों को अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक वजीफा एवं मानदेय प्राप्त हुआ।

विभाग द्वारा डीईओ और नोडल अधिकारियों को सभी तरह के भुगतानों का विवरण देते हुए लेनदेन डेटा संकलित कर मंत्रालय को प्रस्तुत किया।

एनसीडी पोर्टल का विकास और रखरखाव:

विभाग ने एनसीडी पोर्टल की कार्यक्षमता के लिए आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अवसंरचना के विकास के लिए आवश्यक धन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक (एनआईसीएसआई) को अग्रिम भुगतान जारी करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया और यह सभी सहकारिता मंत्रालय द्वारा जारी अनुशंसा के अनुसार किया।
एनसीडी पोर्टल के पीएमजी के लिए एनआईसीएसआई को आवंटित अग्रिम धन के उपयोग का विवरण देते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की जिससे एनसीडी के विकास के लिए वित्तीय संसाधनों के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हुई।
एनसीडी पोर्टल के पीएमजी के लिए एनआईसीएसआई को आवंटित अग्रिम धन के उपयोग का विवरण देते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की जिससे एनसीडी के विकास के लिए वित्तीय संसाधनों के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हुई।

एनसीडी पोर्टल और एनसीडी रिपोर्ट का सफल विमोचन:-

सहकारी सांख्यिकी प्रोफ़ाइल के लिए सहकारी समितियों पर राज्य और क्षेत्रवार डेटा संकलित करने में राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) के लिए मंत्रालय के पीएमजी और पीएमयू को सहयोग प्रदान किया। इसके अतिरिक्त एनसीडी रिपोर्ट के लिए नमूना संरचनाओं का मसौदा तैयार करने में सहायता की जिसमें प्रकाशन में शामिल करने के लिए एनसीडी के विकास में एनसीयूआई के योगदान पर प्रकाश डालने वाला एक नोट भी शामिल था।

दिनांक 8 मार्च, 2024 को माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पोर्टल और एनसीडी रिपोर्ट के सफल शुभारंभ और विमोचन में सहायता प्रदान की। इसमें राष्ट्रीय और राज्य सहकारी संघों, बहु-राज्य सहकारी समितियों और अन्य सहकारी संस्थानों के लगभग 1,000 प्रतिनिधियों को जुटाना भी शामिल था। इस कार्यक्रम में उनकी भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए एक व्यापक डेटाबेस भी बनाया गया।

सहकारी विकास हेतु डेटा संग्रह और रिपोर्टिंग

- एनसीयूआई के ई-कॉमर्स पोर्टल और 'एनसीयूआई हाट' हेतु संपर्क विवरण सहित 7.5 लाख से अधिक सहकारी समितियों का राज्यवार डेटा संकलित किया गया।

- राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी), सहकारी डेटा और समग्र सहकारी क्षेत्र से संबंधित संसदीय प्रश्नों के जवाब के संदर्भ में सटीक और महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान किए। इसके अतिरिक्त देश में सहकारी विकास पर संक्षिप्त नोट्स भी तैयार किए।

- मंत्रालय की एनसीडी रिपोर्ट में शामिल करने हेतु "भारत में सहकारी आंदोलन" पर एक विस्तृत लेख तैयार किया।
- राजस्थान और केरल में विपणन सहकारी समितियों और प्राथमिक स्तर की ऋण सहकारी समितियों पर व्यापक डेटा प्रदान किया जो उनके लिए अध्ययन हेतु आवश्यक था।
- विभिन्न सहकारी क्षेत्रों को प्रदर्शित करने के लिए प्रस्तुतियाँ और संक्षिप्त प्रोफ़ाइल बनाई और विभिन्न संस्थानों और प्रभागों के लिए सहकारी समितियों पर डेटा विश्लेषण किया गया।

17 वां भारतीय सहकारी महासम्मेलन (आईसीसी-2023) :

- राष्ट्रीय महासंघों, राज्य सहकारी संघों, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, सहकारी बैंक, जिला संघों और सहकारी समितियों सहित विभिन्न सहकारी संस्थाओं को 17वें महासम्मेलन में भाग लेने के लिए निमंत्रण पत्र भेजा गया। विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय करके उनको इस कार्यक्रम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया और कार्यक्रम के बारे में उनके प्रश्नों के सवालों के जवाब दिये।

अन्य गतिविधियाँ:

- संसदीय प्रश्नों के उत्तर में पंजीकृत सहकारी समितियों, सहकारी क्षेत्र के समग्र प्रदर्शन, सहकारी समितियों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण और डेयरी सहकारी समितियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।

- वर्ष 2016 और 2018 के लिए भारतीय सहकारी आंदोलन के सांख्यिकीय प्रोफाइल को एनसीयूआई की वेबसाइट पर अपलोड किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे उपयोगकर्ताओं के लिए आसानी से सुलभ हों।

- प्राथमिक समितियों की संख्या के बारे में अद्यतन अनुमानों के साथ सहकारिता मंत्रालय को यह सूचना प्रदान की।

अध्याय 09

राष्ट्रीय सहकारी संसाधन केंद्र (एनसीआरसी) और सहकारी विस्तार एवं परामर्श सेवाएं (सीईएएस)

I. राष्ट्रीय सहकारी संसाधन केंद्र (एनसीआरसी)

राष्ट्रीय सहकारी संसाधन केंद्र (एनसीआरसी) की स्थापना दिसंबर 2022 में हुई थी। यह विभाग सभी सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण (सीईटी) संस्थानों के लिए राष्ट्रीय संसाधन एवं एक 'थिंक टैंक' के रूप में कार्य करता है। यह प्रशिक्षण सामग्री और मॉड्यूल विकसित करने, सहकारी क्षेत्र पर अभूतपूर्व शोध करने, शोध पत्र, नीति विवरण, लोकप्रिय लेख और इसके अतिरिक्त केस स्टडी भी तैयार करता है। यह केंद्र कुल सत्रह सहकारी क्षेत्रों की विविध गतिविधियों और पहलों में सार्थक योगदान देता है।

राष्ट्रीय सहकारी संसाधन केंद्र (एनसीआरसी) द्वारा 2023-24 के दौरान की जाने वाली विभिन्न गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:-

"एक संस्था के रूप में सहकारिता" उप शीर्षक के तहत सहकारिता के मूल सिद्धांतों पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास करना।

यह केंद्र सहकारी सदस्यों और प्रतिभागियों को व्यापक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित कर रहा है जिससे उन्हें सहकारी सिद्धांतों, संरचनाओं और कार्यों के बारे में आवश्यक ज्ञान प्रदान किया जा सके। अब तक यह केंद्र दस मॉड्यूल तैयार कर चुका है जो इस प्रकार हैं:-

1) सहकारी समितियों का सामुदायिक जुटाव एवं पंजीकरण*
2) सहकारी समितियों के लिए व्यवसाय विकास योजना
3) सहकारी समितियों में सदस्यों की भूमिका*
4) सहकारी समितियों में शासन*
5) सहकारी समितियों का प्रबंधन
6) सहकारी समितियों का वित्तीय प्रबंधन
7) सहकारी समितियों पर जीएसटी के निहितार्थ
8) सहकारी समितियों पर आयकर के निहितार्थ
9) सहकारी समितियों का कानूनी अनुपालन*
10) सहकारी समितियों का लेखा परीक्षण
11) सहकारी समितियों में लेखांकन

* ये चार प्रशिक्षण मॉड्यूल पहले ही जारी किए जा चुके हैं और सार्वजनिक डोमेन में भी उपलब्ध हैं। इन्हें हमारे सहकारी विस्तार और सलाहकार सेवा शिक्षण प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है। (C E A S - L M S पोर्टल: https://ncuicoop.education/home).

प्रत्येक मॉड्यूल को आकर्षक, सूचनात्मक और व्यावहारिक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि प्रतिभागियों को सहकारी मॉडल और समुदायों और अर्थव्यवस्थाओं के भीतर इसके महत्व की पूरी समझ प्राप्त हो सके। इस पहल के माध्यम से केंद्र सहकारी सदस्यों को उनके सहकारी उद्यमों के सतत विकास में प्रभावी रूप से योगदान देने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान के साथ सशक्त बनाने का प्रयास करता है।

इसके अंतर्गत उप-शीर्षक "उद्यम के रूप में सहकारिता" के तहत क्षेत्रीय सहकारी समितियों पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास करना मुख्य हैं। इस उप-शीर्षक के तहत केंद्र विभिन्न क्षेत्रीय सहकारी समितियों और उन्हें एक व्यावसायिक इकाई बनाने के तरीके के बारे में उनको शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित कर रहा है। केंद्र की टीम ने सदस्यों और नेताओं की शैक्षिक और प्रशिक्षण आवश्यकताओं को समझने के लिए क्षेत्रवार हितधारक परामर्श बैठकों के कई दौर आयोजित किए हैं। इसके बाद अंतिम मसौदे की विषय-वस्तु और क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा सावधानीपूर्वक समीक्षा और तकनीकी रूप से संपादन किया गया है। यह प्रक्रिया संसाधन की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है जिससे यह सभी सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। यह केंद्र अब तक चौदह क्षेत्रीय प्रशिक्षण मॉड्यूल का सेट तैयार कर चुका है जो इस प्रकार हैं:-

1) प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में व्यवसाय संवर्धन और विविधीकरण*
2) ऋण सहकारी समितियाँ
3) शहरी सहकारी बैंकिंग*
4) ग्रामीण सहकारी बैंकिंग*
5) डेयरी सहकारी समितियाँ
6) मत्स्य सहकारी समितियाँ
7) चीनी सहकारी समितियाँ
8) विपणन सहकारी समितियाँ
9) उपभोक्ता सहकारी समितियाँ
10) श्रम सहकारी समितियाँ
11) आवास सहकारी समितियाँ*
12) हथकरघा/वस्त्र सहकारी समितियाँ
13) हस्तशिल्प सहकारी समितियाँ
14) स्वास्थ्य सहकारी समितियाँ
15) बीज सहकारी समितियाँ
16) जैविक सहकारी समितियाँ
17) निर्यात सहकारी समितियाँ

*ये चार प्रशिक्षण मॉड्यूल पहले ही सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध करा दिए गए हैं और इन्हें हमारे सीईएएस-एलएमएस पोर्टल के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है।

- सहकारिता मंत्रालय के लिए किए गए अध्ययन

- सहकारी क्षेत्र के लाभ के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मौजूदा और भावी योजनाओं का संग्रह।

- केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का संग्रह सहकारी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यह सरकारी पहलों के लिए एक समेकित मार्गदर्शिका प्रदान करता है जिससे सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने, क्षेत्र-विशिष्ट योजनाओं के साथ जुड़ने और प्रभावी वकालत में संलग्न होने में मदद मिलती है। इससे प्रक्रियाओं को सरल बनाने, सहकार को बढ़ावा देने और विकास को बढ़ावा देने के माध्यम से यह संग्रह सहकारी विकास को आगे बढ़ाता हैं और व्यापक आर्थिक उन्नति में अहम योगदान देता है।

- अन्य व्यावसायिक संस्थाओं की तुलना में सहकारी क्षेत्र के लाभ और हानि को समझना।

- यह अध्ययन अन्य व्यावसायिक मॉडलों की तुलना में सहकारी समितियों की सापेक्ष शक्तियों और कमजोरियों के बारे में जानकारी प्रदान करके महत्वपूर्ण मूल्य रखता है। इसके निष्कर्ष नीति निर्माताओं, उद्यमियों और निवेशकों के लिए निर्णय लेने की जानकारी देते हैं। इसके अतिरिक्त नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं, संसाधन आवंटन का मार्गदर्शन करते हैं, जोखिमों का प्रबंधन करते हैं और सामुदायिक विकास को बढ़ावा देते हैं। यह अध्ययन एक शैक्षिक संसाधन के रूप में भी कार्य करता है, संधारणीय प्रथाओं को बढ़ावा देता है और क्रॉस-सेक्टर सहयोग को बढ़ाता है। कुल मिलाकर, निर्णय लेने, टिकाऊ व्यापार रणनीतियों और व्यापक आर्थिक चर्चाओं में योगदान देता है।

- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारी कानूनों (अधिनियमों/नियमों) की तुलना करता हैं।

- अध्ययन विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी समितियों को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। निष्कर्ष उनके बीच अंतर और समानताएं, स्पष्टता, निर्णय लेने की जानकारी, नीति संरेखण को बढ़ावा देने और अनुपालन की सुविधा प्रदान करते हैं। इसके अलावा इसने कानूनों के प्रतिबंधात्मक प्रावधानों का पता लगाने में भी मदद प्रदान करता हैं जिससे कि सहकारी समितियों को मजबूत किया जा सकता है।

- भारत में सभी बहु-राज्य सहकारी समितियों की प्रोफाइल मैपिंग करना।

- यह अध्ययन देश भर की सभी बहु-राज्य सहकारी समितियों (एमएससीएस) की प्रोफाइल बनाने के लिए किया गया था जिसका उद्देश्य उनकी कार्यक्षमता, सूचना और अन्य प्रासंगिक विवरणों का आकलन करना था। इसके अतिरिक्त भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन को भी इसके तहत उन्हें मजबूत करने की आवश्यकता है।

- **प्रकाशन**
- एनसीयूआई नीति संक्षिप्त श्रृंखला: नीति संक्षिप्त

1: सहकारी समितियों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा और कार्बन बाजारों को संस्थागत बनाना।

शोध लेख: सहकारी तालमेल: सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में डेयरी सहकारी समितियों की शक्ति को उजागर करना। सहकारी लेखा और प्रबंधन के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल (आईजेसीएएम), मई 2024

· लोकप्रिय लेख: कुल लेख 09 प्रकाशित किए गए जो इस प्रकार हैं:-

1) आर्थिक विकास के लिए सहकारी उद्यमिता को मजबूत करना (योजना, जुलाई 2023)
2) सहकारिता के माध्यम से समृद्धि का एहसास (रोजगार समाचार: 20 - 26 मई, 2023)
3) क्लस्टर स्तरीय संघों के माध्यम से ग्रामीण उद्यमियों को सशक्त बनाना (रोजगार समाचार: 01-07 जुलाई, 2023)
4) सहकारिता का व्यावसायीकरण: पेशेवरों की भूमिका ? दक्षिण एशिया में कृषि विस्तार (एईएसए) (ब्लॉग 197 – अगस्त, 2023)
5) बजट ने सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा दिया। (डेक्कन हेराल्ड न्यूज़ पेपर, (दिनांक 06 फ़रवरी, 2023)
6) डीकोरबोनाइज़ेशन मार्केट। (द पायनियर, 07 जनवरी, 2024)
7) 'प्रकृति का बगीचा': महिला-नेतृत्व वाले नवाचार के माध्यम से हर किसी की भूमिकाओं को फिर से परिभाषित करना, द कोऑपरेटर वॉल्यूम-61 (दिनांक 09 मार्च, 2024)
8) पीपीसी मॉडल के माध्यम से गांवों का सर्व-समावेशी विकास संभव, (सहकार जागरण, अंक 09 दिसंबर, 2023)
9) राष्ट्रीय सहकारी क्षेत्र में एक नया क्षितिज विकसित करना। (ऑर्गेनिक इनसाइट्स, वॉल्यूम-11, अंक नंबर-3)

· गनोट: सौर सहकारी समितियों के माध्यम से हरित विकास को बढ़ावा देना। गुड अभ्यास नोट 2. एपीआईआरएएस-एपीएएआरआई। दी टीएपी-एआईएस परियोजना, एफएओ 1 से 13

· पुस्तकें: सहकारी समितियों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू): सहकारी कानून को समझना। इसका विमोचन 70वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह समारोह के दौरान श्री पुरुषोत्तम रुपाला, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, भारत सरकार द्वारा किया गया। यह सहकारी संगठनों के कामकाज और सिद्धांतों से संबंधित सामान्य प्रश्नों और चिंताओं को संबोधित करने के लिए संसाधन के रूप में कार्य करेगा। इसके अलावा यह युवा पीढ़ी को सहकारी व्यापार मॉडल की ओर आकर्षित करने में भी मदद करेगा क्योंकि इससे जटिल सहकारी कानून को अधिक सुलभ प्रारूप में सरल बनाया है।

· एनसीसीई और अन्य संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में संसाधन व्यक्ति (रिसोर्स पर्सन) के रूप में भागीदारी

· विशेष प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे केंद्र, एलबीएसएनएए, मसूरी, उत्तराखंड में और नई दिल्ली में सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) द्वारा आयोजित प्रशिक्षण और कार्यशालाओं में अतिथि वक्ता के रूप में कार्य करते हैं।

· एनसीजीसी द्वारा आयोजित जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक अधिकारियों के लिए "सहकारिता आंदोलन 2.0" (दिसंबर 2023 और जनवरी 2024)

· सहकारिता:- अतीत, वर्तमान और भविष्य, भारत सरकार के अवर सचिवों के लिए (सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम), नई दिल्ली द्वारा आयोजित)

· लाओ पीडीआर - सुपरवीकॉफी परियोजना: केयर इंटरनेशनल, 4फॉर्म, हेलियस और आईसीए-एपी

· एनसीआरसी/सीईएएस के अनुसंधान अधिकारी नियमित रूप से विभिन्न एनसीसीई कार्यक्रमों में प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर रहे हैं।

भारत में सहकारिता की स्थिति पर सम्मेलन एवं विचार मंथन

भारत में सहकारिता की स्थिति पर आईसीए-एपी और राष्ट्रीय आर्थिक मंचों (एनईएफ) पर विस्तृत चर्चा दिनांक 20 मार्च, 2024 को एनसीयूआई में आयोजित की गई। यह सम्मेलन भारत में सहकारिता की प्रगति, चुनौतियों और आगे के मार्ग पर केंद्रित रहा जिसमें सहकारी क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों के बीच खुली बातचीत की गई। इसमें सहकारी संगठनों, सरकारी एजेंसियों, शिक्षाविदों और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि भी शामिल थे। इस चर्चा में अनुसंधान के अवसरों की खोज और भारत में सहकारी समितियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

I. सहकारी विस्तार और सलाहकार सेवाएँ (सीईएएस)

इस विभाग की स्थापना दिसंबर 2022 में हुई जिसका मकसद कार्यान्वयन प्रभाग के रूप में मौजूदा सहकारी विस्तार संस्थानों (जैसे एससीयू और जेसीटीसी) को मजबूत करना और सहकारी विस्तार तंत्र का निर्माण करना है। इसके बहुआयामी दृष्टिकोण में विस्तार कार्यकर्ताओं (सहकारी विभाग के कार्मिकों सहित) की क्षमता निर्माण, सलाहकार सेवाएँ, अनुसंधान, सहकारी जागरूकता, मौजूदा सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करना और नई सहकारी समितियों को बढ़ावा देना शामिल है।

· सहकारी विस्तार एवं परामर्शदात्री सेवा प्रभाग द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ निम्नानुसार हैं:-

सीईएएस - एलएमएस पोर्टल: यह सहकारी सदस्यों, नेताओं, कर्मचारियों, युवाओं और महिलाओं को सहकारी प्रबंधन के सभी तत्वों के बारे में जागरूक और शिक्षित करने के लिए एक एकीकृत मंच है। इस पोर्टल को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 1 जुलाई, 2023 को लॉन्च किया गया था। इस पहल का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र में लगे या इच्छुक व्यक्तियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसके तहत पंजीकृत उपयोगकर्ता पाठ्यक्रम, अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सकते हैं और 'ज्ञान परीक्षण' पास करने के बाद 'प्रमाणपत्र' प्राप्त करने के लिए सरल प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। वर्तमान में 754 पंजीकृत प्रतिभागी हैं जिनमें से 5238 सक्रिय रूप से पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं। उल्लेखनीय रूप से अब तक 63 प्रतिभागियों ने सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और इस पोर्टल पर लगभग 38,000 आगंतुक (अप्रैल 2024 तक) हो चुके हैं।

सीईएएस-एलएमएस पोर्टल का प्रचार:

सीईएएस टीम समय-समय पर एनसीसीई कार्यक्रमों के प्रतिभागियों और कृषि व्यवसाय प्रबंधन में एमबीए के साथ-साथ कृषि अध्ययन में बीएससी, एमएससी और पीएचडी कार्यक्रमों की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए 'ओरिएंटेशन सह जागरूकता सृजन' सत्र आयोजित करती है। ये सत्र सहकारिता के मूल सिद्धांतों के बारे में ज्ञान प्रदान करने और सीईएएस-एलएमएस पोर्टल को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं। इस तरह का पहला सत्र 26 फरवरी, 2024 को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू), रांची के लिए आयोजित किया गया था।

प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) कार्यक्रम:

सीईएएस प्रभाग ने कृषि और कृषि व्यवसाय प्रबंधन के छात्रों के लिए "कॉप्स4 एसआरडी: सतत ग्रामीण विकास" पर एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शुरु किया। इसका पहला बैच दिनांक 12 से 16 मार्च, 2024 तक रामचंद्रन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, पुणे, महाराष्ट्र के लिए आयोजित किया गया था।

कूप्स 4जेन नेक्स्ट ज्ञान श्रृंखला:

- यह ज्ञान श्रृंखला सहकारी विस्तार और सलाहकार सेवा प्रभाग के तहत एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसे सहकारी समितियों और युवा पीढ़ी के बीच की खाई को पाटने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके तहत दिनांक 15 जुलाई, 2023 के "विश्व युवा कौशल दिवस" के शुभ अवसर पर विभिन्न आयु समूहों के बीच सहकार को बढ़ावा देने और युवाओं को सहकारी समितियों द्वारा पेश किए जाने वाले अवसरों का लाभ उठाने के लिए सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता के रूप में लॉन्च किया गया। सहकारी विशेषज्ञों द्वारा अब तक निम्नलिखित व्याख्यान दिए गए हैं:-

व्याख्यान 1: "सहकारिता: समावेशी और सतत विकास के लिए सामाजिक व्यवसाय मॉडल" (डॉ. के. के. त्रिपाठी, सहकारिता विशेषज्ञ द्वारा)

व्याख्यान 2: "सहकारी नवाचार के साथ स्मार्ट खेती" - केस स्टडीज - वेंकटेश्वर पावर एंड एग्रो मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी और मालेगांव, महाराष्ट्र और मिथिला वेज कोप, बिहार

व्याख्यान 3: "सहकारी समितियों का पंजीकरण" श्री. जे. जे. शाह, सेवानिवृत्त संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, गुजरात

व्याख्यान 4: "सहकारी ऋण समितियां और बैंक: पंजीकरण और अनुपालन" सीए गोपाल ढाकन और श्री. सुभाष गुप्ता, सलाहकार, एनसीयूआई द्वारा

व्याख्यान 5: "बहु-राज्य सहकारी समितियां (एमएससीएस): पंजीकरण और अनुपालन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया सहित हालिया संशोधन और उनके प्रभाव" डॉ. वी.के. दुबे, सलाहकार और श्री यशांक कुलकर्णी, अनुसंधान अधिकारी, एनसीयूआई, नई दिल्ली द्वारा।

क्षेत्रवार वेबिनार श्रृंखला:

- सहकारी क्षेत्र के भीतर ज्ञान-साझाकरण और सहयोग के लिए इन क्षेत्रवार वेबिनारों को एक अमूल्य पहल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये वेबिनार सहकारी सदस्यों और हितधारकों को क्षेत्र-विशिष्ट विषयों पर गहन विचार-विमर्श करने, उभरते रुझानों, क्षेत्र से संबंधित पहलुओं और समस्याओं पर चर्चा करने और सतत विकास के लिए नवीन रणनीतियों का पता लगाने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। अब तक निम्नलिखित वेबिनार आयोजित किए जा चुके हैं:

पैक्स:- प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में व्यवसाय संवर्धन और विविधीकरण [3 जनवरी से 12 जनवरी 2024]

इस वेबिनार में 150 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस श्रृंखला में कृषि विकास में पैक्स की भूमिका को बढ़ाने, व्यवसाय संवर्धन और विविधीकरण के लिए रास्ते तलाशने के लिए महत्वपूर्ण रणनीतियों के अवसरों की खोज की गई। इसमे व्यावहारिक चर्चाओं और विशेषज्ञों के नेतृत्व वाले सत्रों के माध्यम से प्रतिभागियों ने ग्रामीण आर्थिक विकास के लिए पैक्स को इंजन के रूप में उपयोग करने के बारे में भी जानकारी प्राप्त की।

मिलेट :-

सहकारी मिलेट पुनर्जागरण [दिनांक 9 - 10 जनवरी, 2024]

इस वेबिनार में विभिन्न राज्य सहकारी संघों (एससीयू), जेसीटीसी, सहकारी शिक्षा क्षेत्र परियोजनाओं और छात्रों सहित 100 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस वेबिनार ने प्रतिभागियों को मिलेट की व्यापक समझ प्रदान की जिसमें उनके पोषण संबंधी लाभों, दैनिक आहार में महत्व और स्वस्थ जीवन शैली में उनके संभावित योगदान पर जोर दिया गया ।

आवास:

सहकारी आवास समितियों का प्रबंधन [25 जनवरी से 3 फरवरी 2024]

इस वेबिनार में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। आवास सहकारी विशेषज्ञों के नेतृत्व में व्यावहारिक सत्रों के माध्यम से, प्रतिभागियों ने सहकारी आवास क्षेत्र के भीतर शासन, वित्तीय प्रबंधन, कानूनी अनुपालन और सामुदायिक सहभागिता की जटिलता का पता लगाया। टिकाऊ और सामंजस्यपूर्ण रहने वाले वातावरण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रतिभागियों को संचालन को सुव्यवस्थित करने, संघर्षों को हल करने और संसाधन उपयोग को अनुकूलित करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ सशक्त बनाया।

क्षेत्रवार प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटीएस) कार्यक्रम:

पुणे, महाराष्ट्र में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के परिवर्तन के लिए पांच दिवसीय (13-17 फरवरी, 2024) प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन.

पैक्स को बहुउद्देश्यीय पैक्स में बदलने की पहल के समर्थन में सीईएएस ने "प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में व्यवसाय संवर्धन और विविधीकरण" विषय पर अपनी तरह का पहला टीओटी कार्यक्रम आयोजित किया। इसके तहत कुल 68 संकाय/प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया जो अगले छह महीनों में महाराष्ट्र भर में 21,000 से अधिक पैक्स के सदस्यों और निदेशक मंडल को विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों में प्रशिक्षित करेंगे।

रांची, झारखंड में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के परिवर्तन के लिए पांच दिवसीय (26 फरवरी से 1 मार्च, 2024) प्रशिक्षण

कार्यक्रम का आयोजन:-

पुणे में टीओटी के सफल समापन के साथ,रांची में व्यापक टीओटी कार्यक्रम का दूसरा बैच आयोजित किया गया । छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के राज्य और जिला सहकारी संघों और जूनियर सहकारी प्रशिक्षण केंद्रों (जेसीटीसी) के 36 से अधिक संकाय और प्रशिक्षकों को विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों में प्रशिक्षित किया गया। वे बाद में अपने-अपने राज्यों में पैक्स और लैंएंप्स के सदस्यों और बोर्ड निदेशकों को प्रशिक्षित करेंगे जिससे उन्हें पैक्स के मूल सिद्धांतों के बारे में जानने और बहुउद्देशीय पैक्स में उनके परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी।

वर्ष 2023-24 में आयोजित कार्यक्रम और प्रतिभागियों का समेकित विवरण नीचे दिया गया हैं:

क्रमांक	कार्यक्रम का नाम	कुल	अवधि	सैक्टर	राज्य
1	प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में व्यवसाय संवर्धन एवं विविधीकरण	150	3-12 जनवरी, 2024	पैक्स	भारत
2	सहकारी मिलेट पुनर्जागरण	96	9-10 जनवरी, 2024	मिलेट	भारत
3	सहकारी आवास समितियों का प्रबंधन	267	25 जन से 3 फरवरी, 24	आवास	भारत

क्रमांक	कार्यक्रम का नाम	कुल	अवधि	सैक्टर	राज्य
4	Coop4GenNext ज्ञान श्रृंखला- एमएससीएस के हालिया संशोधन और उनके प्रभाव	198	29-31 जनवरी, 2024	एम.एस.सी.एस	भारत
5	प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के परिवर्तन के लिए प्रशिक्षक कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षण	68	13-17 फरवरी, 2024	पैक्स	भारत
6	प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के परिवर्तन के लिए प्रशिक्षक कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षण	36	26 फरवरी से 01 मार्च, 2024	पैक्स	भारत
	कुल	815			

NATIONAL COOPERATIVE RESEARCH CENTRE
National Cooperative Union of India, New Delhi
Annual Progress Report for the year of 2023-24

									Date		
Sl. No.	Name of the Programme	Total	SC	ST	OBC	WOMEN	OTHER	NE	FROM	SECTOR	STATE
1	Business Promotion & Diversification in Primary Agriculture Credit Societies	150							3-12 January, 2024	PACS	India
2	Coop. Millets Renaissance	96							9-10 January, 2024	Millets	India
3	Management of Cooperative Housing Societies	267							25 Jan.-3 Feb., 24	Housing	India
4	Coop4GenNext Knowledge Series- MSCS Recent Amendments and their Impact	198							29-31 January, 2024	Multi State Coop. Societies	India
5	Training Programme for the Transformation of Primary Agriculture Credit Societies	68							13-17 February, 2024	PACS	India
6	Training Programme for the Transformation of Primary Agriculture Credit Societies	36							26 Feb.-1st March, 2024	PACS	Ranchi/Jharkhand
	Total	**815**									

अध्याय 10
एनसीयूआई हाट

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) द्वारा "एनसीयूआई हाट" कम प्रसिद्ध एवं ज्ञात सहकारी समितियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई एक अग्रणी पहल है। भारत के लोगों और ग्रामीण क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करते हुए "एनसीयूआई हाट" इन समूहों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। कोविड-19 महामारी ने छोटे उद्यमों और सहकारी समितियों को बुरी तरह प्रभावित किया जिससे कई लोगों को अपना व्यवसाय बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इनमें से कई समितियां वित्तीय बाधाओं, अपर्याप्त प्रशिक्षण और सीमित अनुभव के कारण बड़े बाजारों तक पहुंच से वंचित हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने और ऐसे उद्यमों का समर्थन करने के लिए "एनसीयूआई हाट" की कल्पना दिल्ली में एक प्रमुख स्थान पर स्थित एक प्रदर्शनी-सह-बिक्री केंद्र के रूप में की गई जो इन सहकारी समितियों को व्यापक दर्शकों तक पहुंचने के लिए स्टॉल स्थान प्रदान कर आर्थिक मदद करता है।

शुरू में एनसीयूआई शिक्षा क्षेत्र परियोजनाओं से जुड़े एसएचजी को समर्थन देने के लिए डिज़ाइन की गई इस पहल ने देश भर में अन्य एसएचजी विशेष रूप से महिलाओं के नेतृत्व वाले समूहों को शामिल करने के लिए अपना दायरा बढ़ाया है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य भारतीय सहकारी आंदोलन के परिदृश्य को व्यापक बनाना है जिससे इन समूहों को "एनसीयूआई हाट" द्वारा प्रदान किए गए मंच से लाभ उठाने का अवसर मिल सके। सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए अपने दरवाजे खोलकर एनसीयूआई हाट सहकारी आंदोलन की समावेशिता और पहुंच को बढ़ाता है। दिनांक 16 अगस्त, 2021 को उद्घाटन के बाद से "एनसीयूआई हाट" को दिल्ली के निवासियों और आस-पास के संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों सहित आगंतुकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। इस पहल ने न केवल कम ज्ञात सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों को दृश्यता प्रदान की है बल्कि ग्रामीण कारीगरों और शहरी उपभोक्ताओं के बीच सीधे जुड़ाव को बढ़ावा देकर सहकारी भावना को भी मजबूत किया है।

एनसीयूआई हाट: जरूरतमंदों को सशक्त बनाने का एक विचार

"सहकार से समृद्धि" के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना।

"एनसीयूआई हाट" भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कई प्रमुख कार्यक्रमों और पहलों जैसे "राष्ट्रीय आजीविका मिशन", "वोकल फॉर लोकल" और "स्किल इंडिया मिशन" का समर्थन करता है।

उद्देश्य

इसके तहत वंचित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और सहकारी समितियों को दिल्ली में प्रमुख बिक्री स्थानों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना, उनकी दृश्यता और बाजार पहुंच को बढ़ाना हैं।

दिल्ली के निवासियों और पर्यटकों को ग्रामीण भारत के कारीगरों द्वारा तैयार उच्च गुणवत्ता वाले, उचित मूल्य वाले उत्पाद उपलब्ध कराना।

शहरी उपभोक्ताओं के बीच स्वस्थ और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहित करके अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना।

राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में अपने उत्पादों का प्रदर्शन करके पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों का समर्थन करना जिससे उनकी पहचान और मांग बढ़े।

भौगोलिक संकेत (जीआई) टैगिंग के लिए योग्य सहकारी उत्पादों की पहचान करना, उनकी विशिष्टता और बाजार मूल्य को बढ़ाना।

कम प्रसिद्ध सहकारी समितियों और एसएचजी के सदस्यों को विशेष प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए मान्यता देना जिसका उद्देश्य उनके उत्पादों की गुणवत्ता और मानकों में सुधार करना है।

मुख्य विशेषताएं :-

आगंतुक विभिन्न क्षेत्रों से स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करके हस्तनिर्मित उत्पादों की एक विस्तृत विविधता का पता लगा सकते हैं।

एनसीयूआई इसमे भाग लेने वाले समूहों के लिए यात्रा, आवास और भोजन से संबंधित सभी खर्चों को वहन करता है।

भाग लेने वाले समूहों को प्रदर्शनी-सह-स्टॉल स्थान निःशुल्क प्रदान किया जाता है।

जरूरतमंद एसएचजी और सहकारी समितियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए एक कैलेंडर प्रणाली का पालन किया जाता है जिसमें 5-6 राज्यों के उत्पादों को 15 दिनों के लिए प्रदर्शित किया जाता है जिसके बाद नए समूहों को भाग लेने का अवसर दिया जाता है।

"एनसीयूआई हाट" की गतिविधियाँ:-

उत्पाद प्रदर्शन चक्र: हर 15-20 दिन में एनसीयूआई शिक्षा क्षेत्र परियोजनाओं और 5-6 राज्यों की सहकारी समितियों और एसएचजी के उत्पादों को प्रदर्शन और बिक्री के लिए आमंत्रित किया जाता है। नए उत्पादों के बारे में विज्ञापन और जानकारी फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और पोस्टर और बैनर के माध्यम से साझा की जाती है।

युवा कार्यक्रम:

सहकारी सप्ताह के दौरान एनसीयूआई ने युवाओं को जोड़ने और उन्हें सहकारी उद्यमिता मॉडल से परिचित कराने के लिए अपने परिसर में दो मजेदार प्रतियोगिताएँ- स्ट्रीट प्ले और वेस्टर्न डांस आदि आयोजित कीं।

एनआईएफटी द्वारा आयोजित क्राफ्ट बाज़ार में एनसीयूआई हाट की भागीदारी:

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ फ़ैशन टेक्नोलॉजी (एनआईएफटी) ने एक क्राफ्ट बाज़ार का आयोजन किया जिसमें एनसीयूआई हाट ने भाग लिया। एनआईएफटी दिल्ली द्वारा आयोजित रुज फ़ैशन शो में एनसीयूआई ने अपने वेस्ट फ़ैब्रिक लॉन्ग जैकेट और आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में खाद्य स्टॉल, फ़ैब्रिक, हर्बल रंग और घर के बने खाने के सामान भी शामिल थे जिससे ग्रामीण कारीगरों और शहरी उपभोक्ताओं के बीच की खाई को पाटने में मदद मिली।

एनसीयूआई हाट के ई-पोर्टल का शुभारंभ:

1 जुलाई, 2023 को 17वें राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन (एनसीसी) के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री ने एनसीयूआई हाट ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किया। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म विशेष रूप से सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों के लिए बनाया गया है। वेबसाइट और एप्लिकेशन 10 भाषाओं में उपलब्ध हैं जो कि अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, तमिल और तेलुगु हैं। पोर्टल सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है और ऑनबोर्डिंग, ब्रांडिंग और प्रचार के लिए मुफ्त प्रशिक्षण सहायता प्रदान करता है।

वार्षिक आम बैठकों (एजीएम) में स्टॉल: एनसीयूआई, नेफेड, एनसीसीएफ और अन्य सहकारी संघों ने 21 से 24 सितंबर तक एनसीयूआई परिसर में अपनी एजीएम आयोजित की। एनसीयूआई हाट ने सहकारी उत्पादों का प्रदर्शन किया और भारतीय सहकारी कांग्रेस के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए एनसीयूआई हाट ई-कॉमर्स पोर्टल को बढ़ावा दिया। पोर्टल सहकारी समितियों और संबद्ध एसएचजी को उनकी आय बढ़ाने के लिए एक विशेष डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। एनसीयूआई हाट टीम ने सदस्यों और कर्मचारियों को पोर्टल के लाभों के बारे में बताया और प्रतिनिधियों ने हस्तशिल्प और खाद्य पदार्थ खरीदे, कम प्रसिद्ध सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के एनसीयूआई के प्रयासों की सराहना की।

सहकारी मेला 2023: एनसीयूआई ने लगातार तीसरे वर्ष दिल्ली के हौज खास परिसर में अपने लोकप्रिय सहकारी मेले (सहकार मेला) 2023 की मेजबानी की। अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के दौरान आयोजित पिछले मेलों के विपरीत इस वर्ष का आयोजन त्योहारी सीजन के दौरान उच्च सार्वजनिक रुचि को बेहतर ढंग से समायोजित करने के लिए 3-8 नवंबर, 2023 तक आयोजित किया गया था। इस मेले में कम प्रसिद्ध सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और खाद्य विक्रेताओं के लगभग 51 स्टॉल थे।

इस कार्यक्रम का उद्घाटन एनसीयूआई अध्यक्ष दिलीप संघाणी, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (एशिया-प्रशांत) अध्यक्ष डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव और एनसीयूआई मुख्य कार्यकारी डॉ. सुधीर महाजन ने किया। इस दौरान उचित मूल्य पर पेश किए गए गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की विविधता के लिए मेले की काफी प्रशंसा की गई। इसमे प्रतिभागियों को निःशुल्क स्टॉल स्पेस, बोर्डिंग और लॉजिंग का लाभ मिला। यह मेला सफल रहा जिसमें 1,200 से अधिक आगंतुक आए और 20 लाख रुपये से अधिक की इस दौरान बिक्री हुई।

पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स में स्टॉल:- दिनांक 24 जनवरी, 2024 को पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तत्वावधान में सहकारिता पर टास्क फोर्स ने पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स में 'सहकारिता मंत्रालय की 54 नई पहलों के माध्यम से विकसित भारत की नींव का निर्माण: प्रगति को सशक्त बनाना-समृद्धि को सक्षम बनाना' शीर्षक से एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। एनसीयूआई हाट ने सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों के प्रामाणिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम में एक स्टॉल लगाया जिसे वहाँ पर पधारें सभी आगंतुकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया और सराहना मिली।

अध्याय 11

उद्यमिता विकास एवं सहयोग केंद्र

ए) अनुसंधान एवं विकास

- देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए सीईडीसी सहकारी-सामाजिक-कॉर्पोरेट साझेदारी को बढ़ावा देकर क्रॉस-सेक्टरल सहयोग को बढ़ावा दे रहा है।
- सीईडीसी ने जून, 2023 में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य शहरी आजीविका मिशनों के सहयोग से पूरे भारत में सहकारी समितियों के रूप में स्वयं सहायता समूह के संघों को पंजीकृत करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का परामर्श आयोजित किया।
- विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था के अन्य उभरते क्षेत्रों में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए सीईडीसी तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है।
- खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड-चेन प्रबंधन आदि में टिकाऊ प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए एलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी और अन्य विशेषज्ञ संस्थानों जैसे संगठनों के साथ परामर्श कार्यशालाओं का भी आयोजन सीईडीसी द्वारा किया गया।
- 17वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन के दौरान माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एनसीयूआई पर एक लघु-फिल्म जारी की गई।

ए) एनसीयूआई हाट

- भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ ने ग्रामीण भारत की कम-ज्ञात सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए अगस्त 2021 में एक नई पहल के तहत "एनसीयूआई हाट" की स्थापना की। उल्लेखनीय हैं कि दो साल के अंदर ही "एनसीयूआई हाट" में बिक्री तीन करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गई हैं।

- सहकारी सप्ताह के दौरान प्रतिवर्ष आयोजित "एनसीयूआई हाट" सहकारी मेले में भाग लेने वाले कारीगरों को बाजार की
- आवश्यकताओं और नए उत्पाद विकल्पों का आकलन करने में सक्षम बनाया है।
- नवंबर 2023 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, एचसीएल फाउंडेशन और एनसीयूआई के चयनित सदस्य संस्थानों के सहयोग से'सहकारी मेला' आयोजित किया गया था।

एनसीयूआई हाट ई-कॉमर्स पोर्टल

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ ने "एनसीयूआई हाट ई-कॉमर्स पोर्टल" को विकसित एवं प्रबंधित करने हेतु निटकॉन लिमिटेड को नियुक्त किया जो सहकारी समितियों द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन के लिए विशेष रूप से अपनी तरह का पहला पोर्टल है।

- इस पोर्टल का लॉन्च माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2023 को भारतीय सहकारी महासम्मेलन के कार्यक्रम के दौरान किया गया था।
- "एनसीयूआई हाट ई-कॉमर्स पोर्टल" का यह विशेष प्रोजेक्ट पाँच महीने तक चला जिसमें एनसीयूआई हाट पोर्टल के प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी दी गई। इसमे पाँच सौ से अधिक सहकारी उत्पादों को शामिल किया गया।

- एनसीयूआई को ई-कॉमर्स पोर्टल के प्रबंधन के लिए एथिक्स ग्रुप से एक प्रस्ताव मिला था। एथिक्स ग्रुप लॉजिस्टिक्स सेवाओं और ग्राहको तक डिलीवरी सेवा मुहैया कराने का एक प्रमुख समाधान प्रदाता है और जिसकी उपस्थिति पूरे भारत में हैं।
- एनसीयूआई ने दिनांक 28 फरवरी, 2024 को एथिक्स ग्रुप के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। एथिक्स ग्रुप ई-कॉमर्स पोर्टल के लिए आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन समाधान प्रदान करेगा।

एनसीयूआई इनक्यूबेशन सेंटर

- एनसीयूआई ने अप्रैल 2022 में इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जिसका उद्देश्य उद्यमिता विकास के माध्यम से वंचित समुदायों को सशक्त बनाना और सहकारी समितियों के लिए आजीविका के अवसरों का विस्तार करना है।
- इनक्यूबेशन सेंटर की परिकल्पना दिल्ली में एनयूएलएम से जुड़ी महिलाओं के बीच सहकारी पहचान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इसके साथ ही देश भर की सहकारी समितियों के सफल सहकारी उद्यमिता मॉडल विकसित करना भी इसका उद्देश्य है।
- इनक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से तीन अलग-अलग प्रशिक्षण मॉड्यूल पेश किए जाते हैं जैसे कि क्षमता विकास कार्यक्रम (25 दिन), उद्यमिता विकास कार्यक्रम (5 दिन) और उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम (5 दिन) इत्यादि हैं।
- प्रथम वर्ष में ही इस केंद्र ने दिल्ली में 5,000 से अधिक महिलाओं को संगठित किया और बीस से अधिक स्वयं सहायता समूह और आठ सौ से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया।
- राज्य शहरी आजीविका मिशन, दिल्ली (एसयूएलएम) के साथ मिलकर सीईडीसी ने स्वयं सहायता समूहों के क्षेत्र स्तरीय संघों को सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत किया और दिल्ली के स्वयं सहायता समूहों को 'उद्यम विकास' पर प्रशिक्षण प्रदान किया।
- इनक्यूबेशन सेंटर की अधिकांश प्रशिक्षुओं ने अपने पहचान दस्तावेजों को अपडेट किया और आभा, एमएसएमई, एफएसएसएआई, श्रमयोगी मानधन योजना और अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं में नामांकन कराया। इससे प्रत्येक प्रशिक्षु को पंद्रह हजार से अधिक रुपए की बचत हुई। इसके तहत सभी प्रशिक्षुओं ने दो लाख रुपये के कवर के साथ सुरक्षा बीमा योजना में अपना बीमा करवाया है।

- इनक्यूबेशन सेंटर की अधिकांश प्रशिक्षुओं ने अपने पहचान दस्तावेजों को अपडेट किया और आभा, एमएसएमई, एफएसएसएआई, श्रमयोगी मानधन योजना और अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं में नामांकन कराया। इससे प्रत्येक प्रशिक्षु को पंद्रह हजार से अधिक रुपए की बचत हुई। इसके तहत सभी प्रशिक्षुओं ने दो लाख रुपये के कवर के साथ सुरक्षा बीमा योजना में अपना बीमा करवाया है।
- एनसीयूआई ने नवंबर, 2023 में इनक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से "कॉप किचन"" नामक एक नई पहल शुरु की हैं जो अपने प्रशिक्षुओं को खाद्य और खानपान क्षेत्र में आजीविका के अवसर प्रदान करती हैं।
- स्वयं सहायता समूह "साथिन" जिसको "कॉप किचन" के प्रबंधन का कार्य सौंपा गया था उसने छह महीने अंदर ही भोजन तैयार करने, ग्राहक सेवा और वित्तीय प्रबंधन सहित व्यवसाय के सभी पहलुओं को सफलतापूर्वक संभाला हैं।

एनसीयूआई कौशल विकास केंद्र

- भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ ने नोएडा में एक अत्याधुनिक कौशल विकास केंद्र (एसडीसी) विकसित किया है।
- आर्ट ऑफ लिविंग संस्था ने श्नाइडर इलेक्ट्रिक, जगुआर, गोदरेज और नैसकॉम जैसी कॉर्पोरेट एजेंसियों के साथ मिलकर प्रशिक्षण बुनियादी ढांचा स्थापित किया है।
- एचसीएल फाउंडेशन ने सिलाई, बेकरी और कन्फेक्शनरी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग आदि विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपने एनजीओ भागीदारों के साथ प्रशिक्षण बुनियादी ढांचा स्थापित किया है।
- हैवेल्स इंडिया जैसी कई अन्य कंपनियों ने केंद्र में कौशल विकास बुनियादी ढांचा स्थापित करने के प्रस्ताव के साथ एनसीयूआई से संपर्क किया है।

समझौता ज्ञापन और सहयोग पत्र पर हस्ताक्षर

- वित्त वर्ष 2023-24 में एनसीयूआई ने "उन्नत भारत अभियान" और "एचसीएल फाउंडेशन" के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- जर्मनी सरकार और भारत सरकार के बीच विकास सहयोग पर द्विपक्षीय समझौते को औपचारिक रूप देने के एनसीयूआई के प्रस्ताव को दिनांक 01 नवंबर, 2023 को मंजूरी दी गई।

- जीआईजेड इंडिया ने 18 महीने के लिए एनसीयूआई में एक परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) स्थापित करने के लिए वित्तीय मदद प्रदान करने की पुष्टि की है। पीएमयू, सीईडीसी के माध्यम से, एनसीयूआई ने सहकारी विकास के मॉडल विकसित करने के लिए जीआईजेड इंडिया और साझेदार संस्थानों के समर्थन से भारत भर में बीस विभिन्न स्थानों पर पायलट परियोजनाओं को निष्पादित करने की योजना बनाई है।

- एओएल पांच राज्यों कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड में पाँच सौ से अधिक बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों को पंजीकृत करने के लिए एनसीयूआई के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। कर्नाटक में पंजीकरण के लिए एक सौ बीस से अधिक बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों ने आवेदन किया है।

- एनसीयूआई ने उत्तराखंड और लद्दाख क्षेत्र के चयनित सीमावर्ती गांवों में सहकारी विकास के लिए परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए अपने "हिमालयी उन्नति मिशन" कार्यक्रम के तहत एओएल के साथ सहयोग किया है।

- एचसीएल फाउंडेशन पूरे देश में सहकारी समितियों के पंजीकरण के लिए अपने स्वयं सहायता समूहों और समुदायों को संगठित करने के लिए एनसीयूआई के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।

- "उन्नत भारत अभियान" मौजूदा सहकारी समितियों के नेटवर्क निर्माण क्षमताओं में शैक्षणिक संस्थानों के संसाधनों का उपयोग करने और नए पंजीकरण करने के लिए एनसीयूआई के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।

सलाहकार परिषद

1 एनसीयूआई ने अप्रैल 2022 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, महिला उद्यमियों और "पद्म श्री" पुरस्कार विजेताओं जैसे प्रमुख संस्थानों से आने वाले विशेषज्ञों की एक सलाहकार परिषद का गठन किया।

2 इस सलाहकार परिषद के गठन का उद्देश्य पूरे भारत में सहकारी समितियों के लिए आजीविका और उद्यम विकल्पों को बढ़ाने के लिए टिकाऊ प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना था।

3 यह सलाहकार परिषद व्यवसाय विकास और बाजार संबंधों में सहकारी समितियों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों का समाधान इत्यादि तैलासने के लिए सीईडीसी के साथ मिलकर कार्य कर रही है।

अध्याय 12

राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संस्थानों की संक्षिप्त रिपोर्ट

1. कृषक भारती सहकारी लिमिटेड (कृभको)

कृषक भारती सहकारी लिमिटेड (कृभको) की स्थापना दिनांक 17 अप्रैल, 1980 को हुई थी । यह एक राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी समिति है। वर्तमान में यह बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2023 के तहत पंजीकृत है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य देश भर में सहकारी समितियों और संस्थागत एजेंसियों के माध्यम से मुख्य रूप से रासायनिक उर्वरक, बीज, जैव उर्वरक जैसे गुणवत्तापूर्ण कृषि इनपुट का उत्पादन और वितरण करना है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सूरत के हजीरा में समिति के संयंत्रों ने अपने वाणिज्यिक उत्पादन के 38वें वर्ष में 13.88 लाख मीट्रिक टन अमोनिया और 23.35 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन किया जो अमोनिया के लिए 111.32% और यूरिया के लिए 106.40% क्षमता उपयोग के अनुरूप है। इसके अलावा समिति ने 8.95 लाख लीटर तरल जैव-उर्वरक, 5551 हजार एनएम3 तरल आर्गन और 1.45 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का उत्पादन भी किया।

कृभको के तहत सहकारी समितियों की कुल सदस्य संख्या 9650 हैं और दिनांक 31 मार्च, 2024 तक समिति की चुकता शेयर पूंजी 390.78 करोड़ रुपये थी। समिति के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए चुकता शेयर पूंजी पर 20 प्रतिशत का लाभांश देने की सिफारिश की है। कृभको ने कर से पहले 334.12 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है। कृभको की नेटवर्थ वित्त वर्ष 2022-23 में 5128.61 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च, 2024 तक 5311.08 करोड़ रुपये हो गई है।

कृभको ने इस वर्ष के दौरान 39.74 लाख मीट्रिक टन यूरिया की बिक्री की है। इस वर्ष के दौरान 22.88 लाख मीट्रिक टन कृभको यूरिया, 10.58 लाख मीट्रिक टन केएफएल यूरिया और 6.28 लाख मीट्रिक टन सरकारी खाते की यूरिया की बिक्री हुई। इसमे संतुलित उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए समिति ने इस वर्ष भी आयातित डीएपी, एनपीके, एनपीएस, एसएसपी आदि का विपणन जारी रखा हैं। समिति ने 5.83 लाख मीट्रिक टन डीएपी, 1.16 एलएमटी एनपीके 10-26-26, 0.44 एलएमटी एनपीके 12-32-16, 0.34 एलएमटी एनपीके 15:15:15, 0.64 एलएमटी एमओपी और 0.44 लाख मीट्रिक टन एनपीएस20-20-0-13 का आयात किया हैं। इस वर्ष के दौरान कुल 8.85 लाख मीट्रिक टन 'पी' और 'के' उर्वरकों का प्रबंधन किया गया हैं। उपरोक्त के अलावा समिति ने 2023-24 के दौरान 53295 मीट्रिक टन अधिशेष अमोनिया और 5551 हजार एनएम3 तरल आर्गन बेचने में कामयाबी हासिल की हैं। वित्त वर्ष 1990-91 में सोसायटी ने किसानों को प्रमुख फसलों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने के लिए बीज गुणन कार्यक्रम शुरू किया। इस पहल के कारण विभिन्न राज्यों में 11 आधुनिक बीज प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना हुई और इसके साथ ही उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक कस्टम प्रसंस्करण इकाई भी स्थापित की गई हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में सोसायटी ने विभिन्न फसलों के लिए 1.45 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का उत्पादन किया और उसको सफलतापूर्वक बेचा भी हैं।

कृषि उत्पादकता को और बढ़ावा देने के लिए सोसायटी ने व्यापक विपणन नेटवर्क का उपयोग करते हुए कृभको के ब्रांड के तहत अपने उत्पादों का विपणन करने के लिए एक प्रमुख हाइब्रिड बीज कंपनी के साथ भागीदारी की। वित्त वर्ष 2023-24 में सोसायटी ने बीटी कपास के 38,539 पैकेट, हाइब्रिड धान के 343 क्विंटल, अनुसंधान धान के 2,173 क्विंटल, हाइब्रिड मक्का के 2,722 क्विंटल और हाइब्रिड बाजरा के 80 क्विंटल बीज बेचे।
सोसायटी वर्तमान में तरल जैव-उर्वरकों के 10 प्रकार के जीवाणु उपभेदों का उत्पादन कर रही है और वर्ष 2023-24 के दौरान कृभको ने 8.95 लाख लीटर तरल जैव-उर्वरकों की बिक्री की जो इसके लंबे शेल्फ जीवन, उच्च तापमान पर जीवित रहने, आसान आवेदन और कम कीमतों के कारण इसकी सराहनीय प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए किया गया।

कृभको लगातार किसानों को खाद के उपयोग के लाभों के बारे में शिक्षित कर रहा है जो मिट्टी में कार्बनिक कार्बन में सुधार करता है और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 44903 मीट्रिक टन सिटी कम्पोस्ट बेच चुका है।

कृभको उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में कृषक भारती सेवा केंद्र (केबीएसके) के रूप में जाने जाने वाले 67 आउटलेट संचालित कर रही है। ये केबीएसके सोसायटी के स्वामित्व वाले खुदरा आउटलेट के रूप में काम करते हैं जो किसानों की उच्च गुणवत्ता वाले कृषि इनपुट की आवश्यकताओं को उनके दरवाजे पर सुविधाजनक और किफायती तरीके से पूरा करने के लिए समर्पित हैं। इसके अतिरिक्त, केबीएसके समय-समय पर शैक्षिक और सलाहकार कार्यक्रमों के माध्यम से अत्याधुनिक कृषि ज्ञान का प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार बिक्री और सेवा उद्देश्यों को एक ही छत के नीचे प्रभावी ढंग से जोड़ते हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सोसायटी ने किसान बैठकें, फील्ड प्रदर्शन, फसल शो, सहकारी सम्मेलन और समूह चर्चा आदि जैसे 4626 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए। इसके अतिरिक्त सोसायटी ने विभिन्न फसलों और सेवाओं पर क्षेत्रीय भाषाओं में 7.36 लाख तकनीकी फ़ोल्डर भी वितरित किए।

सहकारिता और ग्रामीण विकास को मजबूत करने के लिए सोसायटी ने 215 सहकारी समितियों को अपनाया और 153 सहकारी सम्मेलनों में 16588 सहकारी प्रबंधकों को प्रशिक्षित किया। सोसायटी ने मानव और पशुधन के लिए 71 स्वास्थ्य अभियान भी आयोजित किए, 35 पेयजल सुविधाएँ, 33 ग्रामीण खेल कार्यक्रम, 35 स्वच्छता अभियान और 35 आय सृजन कार्यक्रम प्रदान किए।
नोएडा में कृभको कृषि परामर्श केंद्र ने कृषि संबंधी मुद्दों पर मुफ्त परामर्श जारी रखा। वर्ष 2023-24 के दौरान 16 राज्यों से 5943 मिट्टी के नमूनों का परीक्षण किया और परिणामों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से साझा किया। केंद्र ने किसान हेल्पलाइन के माध्यम से कृषि योजना में सहायता के लिए मौसम की जानकारी भी दी।

निवेश, संयुक्त उद्यम, सहायक कंपनियां और अन्य

- ओमान इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी, एसएओसी (ओएमआईएफसीओ)
- कृभको फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (केएफएल)
- कृभको एग्री बिजनेस लिमिटेड
- कृभको ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
- भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल)
- नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एनसीईएल)
- कृभको इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (केआरआईएल)
- गुजरात स्टेट एनर्जी जेनरेशन लिमिटेड (जीएसईजी)
- इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज (आईसीईएक्स)
- नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (एनएफसीएल)

एफ ए आई वार्षिक सेमिनार, 2023 में सोसायटी को निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं-

- कृभको वीडियो फिल्म जिसका शीर्षक "समृद्धि की नई राह" है, "कृषि अपशिष्ट प्रबंधन" पर इस फिल्म को वीडियो फिल्म श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला।
- कृभको को जैव उर्वरकों/जैविक उर्वरकों/शहरी खाद के उत्पादन, संवर्धन और विपणन पर पुरस्कार मिला।
- कृभको उर्वरक संयंत्र, हजीरा ने नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र श्रेणी में "पर्यावरण संरक्षण" के लिए उपविजेता पुरस्कार मिला।

1. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ लिमिटेड (एनसीडीएफआई)

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ लिमिटेड, सहकारी डेयरी क्षेत्र का शीर्षस्थ संगठन है। यह आनंद (गुजरात) में स्थित हैं। इसके सदस्यों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संघीय डेयरी सहकारी समितियाँ शामिल हैं। एनसीडीएफआई में 19 नियमित सदस्य, 13 सहयोगी सदस्य और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) इसके संस्थागत सदस्य हैं। एनसीडीएफआई का प्राथमिक उद्देश्य समन्वय, नेटवर्किंग और वकालत के माध्यम से डेयरी सहकारी समितियों के कामकाज को सुविधाजनक बनाना है।
वित्त वर्ष 2023-24 में एनसीडीएफआई की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

ए) असम लिंग्ज़ी के एसआईसीयूएन में एनसीडीएफआई अधिकारियों का तीन दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) आयोजित किया गया।
भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ लिमिटेड (एनसीडीएफआई) ने सिक्किम राज्य सहकारी संघ (एसआईसीयूएन) में 4 से 6 दिसंबर, 2023 तक तीन दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) का सफलतापूर्वक आयोजन किया। पूर्वी सिक्किम के असम लिंग्ज़ी में स्थित, एसआईसीयूएन एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान के रूप में कार्य करता है जो पूरे राज्य में सहकारी समितियों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। सिक्किम सरकार के तहत सहकारिता विभाग के शीर्ष निकाय के रूप में एसआईसीयूएन ने 19 कर्मचारियों की अपनी टीम के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ लिमिटेड के साथ सहयोग किया।

बी) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ लिमिटेड का 53वां स्थापना दिवस मनाया गया। यह 07 दिसंबर, 2023 को चिंतन भवन, गंगटोक, सिक्किम में आयोजित एक भव्य समारोह में मनाया गया। इस कार्यक्रम में सिक्किम सरकार के माननीय पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा मंत्री श्री लोक नाथ शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही जो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। माननीय मंत्री ने डेयरी विकास में एनसीडीएफआई द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की और इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि डॉ. मंगल जीत राय पूर्वोत्तर क्षेत्र से एनसीडीएफआई के पहले अध्यक्ष हैं। इस 53वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान एनसीडीएफआई ने क्षेत्र की सदस्य डेयरी सहकारी समितियों को सम्मानित करते हुए संस्थागत बिक्री पुरस्कार समारोह के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में उत्कृष्टता की सराहना की। इस कार्यक्रम के दौरान प्रतिष्ठित पुरस्कार श्री लोकनाथ शर्मा, माननीय पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा मंत्री, कर्नल जय सनन, कमांडिंग ऑफिसर, 517 एएससी बटालियन द्वारा प्रदान किए गए।

एनसीडीएफआई पश्चिम असम मिल्क यूनियन (पूरबी डेयरी) को 2022-23 के दौरान भारतीय सेना को दूध के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में प्रथम स्थान हासिल करने के लिए बधाई देता है! सिक्किम मिल्क यूनियन को दूसरा स्थान हासिल करने के लिए भी बधाई देता हैं और इसी अवधि के दौरान आपूर्ति की गई दूध की मात्रा के आधार पर तीसरा स्थान प्राप्त करने के लिए दीमापुर मिल्क यूनियन की भी सराहना करता है। एनसीडीएफआई ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) को निरंतर संरक्षण और मार्गदर्शन पुरस्कार प्रदान किया जिससे उत्तर-पूर्व क्षेत्र में डेयरी उत्कृष्टता प्राप्त करने की दिशा में सहयोगी प्रयासों को पुनर्जीवित किया गया।
एनसीडीएफआई हमारे सम्मानित सशस्त्र बलों को दूध और दूध उत्पादों की निरंतर और विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने में उनके अमूल्य प्रयासों के लिए उत्तर-पूर्व में सभी डेयरी सहकारी समितियों की सराहना करता हैं।

1. राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (नैफसकोब)

राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की स्थापना 19 मई, 1964 को राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों के संचालन को सुविधाजनक बनाने और सामान्य रूप से अल्पकालिक सहकारी ऋण और बैंकिंग के विकास के व्यापक उद्देश्य से की गई थी। यह बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (संशोधित) के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत है।

इसने ग्रामीण सहकारी ऋण वितरण प्रणाली में अपनी उपयोगी सेवाओं के लगभग 61 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मार्च, 2022 के अंत तक 34 राज्य सहकारी बैंक (एससीबी) हैं, जिनमें से 33 नैफसकोब के सदस्य हैं जिनकी 2143 शाखाओं का नेटवर्क है। इसमे 351 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी जिनकी 14058 शाखाएँ हैं और 104266 प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (पैक्स) हैं।

1. नैफ्सकॉब के विभाग :

नैफ्सकॉब में तीन महत्वपूर्ण विभाग हैं जो कि (1) योजना, अनुसंधान और विकास (पीआरडी) और (2) कंप्यूटर सेवा प्रभाग (सीएसडी) हैं।

2. नैफ्सकॉब का प्रदर्शन:

नैफ्सकॉब ने अपने सीमित संसाधनों, वित्तीय और जनशक्ति दोनों के साथ अपने निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में अपने कार्यों को बहुत अच्छी तरह से पूरा किया हैं। पिछले छह दशकों के दौरान नैफ्सकॉब के प्रदर्शन को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता हैं:

पहला दशक (1964 - 1974)	उचित दिशा की खोज
दूसरा दशक (1975 - 1984)	छवि निर्माण के लिए खोजें
तीसरा दशक (1985 - 1994) ए) प्रथम अवधि (1985 - 1989) बी) दूसरी अवधि (1989 - 1994)	दो अवधियों में विभाजित समेकन 'परिवर्तन' की अवधि
चौथा दशक (1995 - 2004)	'आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं और अपेक्षाओं' का दौर
पांचवां दशक (2005 - 2014)	पुनर्पूंजीकरण के लिए सफल लॉबी / अस्थिरता के खिलाफ लॉबी
अगला दशक (2014 - 2023)	*डिजिटलीकरण सहित तकनीकी विकास से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए एसटीसीसीएस की तैयारी सुनिश्चित करना। *कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करना और नियामक ढांचे का अनुपालन करना।
2023-2033	1. सहकारिता मंत्रालय के बनने से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करना। 2. एम सी सी अधिनियम 2002 की धारा 24 का अनुपालन करने के लिए विज़न पेपर तैयार करना। 3. नैफ्सकॉब द्वारा विज़न और मिशन स्टेटमेंट को स्पष्ट करना। 4. अमृत काल (2022-2047) के लिए तैयार होना। 5. नैफ्सकॉब की सदस्यता का दायरा केंद्रीय सहकारी बैंकों/डीसीसीबी तक बढ़ाना। 6. एमसीसी (संशोधन) अधिनियम 2023 की धारा 24 का अनुपालन करना।

1. सेमिनार,परामर्श और बैठकों का आयोजन : पिछले तीस महीनों (06-07-2021) के दौरान समय-समय पर सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के साथ चर्चा के बाद राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक महासंघ (नैफ्सकॉब) ने ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) अर्थात राज्य सहकारी बैंकों (एससीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस) में मजबूत करने के उद्देश्य से उक्त उपाय शुरु किए गए जो कि इस प्रकार हैं:-

(i) एससीबी और डीसीसीबी के लिए ड्राफ्ट मॉडल उपनियम (ii) डीसीसीबी को नेफस्कोब की नाममात्र या सहयोगी या नियमित सदस्यता की अनुमति देने के लिए नेफस्कोब के उपनियमों में संशोधन (iii) सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने अमृत काल (2022-2047) के दौरान व्यापार वृद्धि का विस्तार करने और एमएससीएस अधिनियम, 2022 की धारा 24 के अनुपालन के उपाय सुझाने के लिए नेफस्कोब को एक अध्ययन रिपोर्ट सौंपा। इस पर नेफस्कोब ने व्यापार वृद्धि क्षमता का विस्तार करने के उपायों पर सुझावों का पता लगाने के लिए विस्तार से विचार किया। नेफस्कोब ने वर्ष 2023-24 के दौरान निम्नलिखित सम्मेलन,कार्यशालाएं,सेमिनार और बैठकें आयोजित कीं।

2. अमृत काल (2022-47) के दौरान व्यापार वृद्धि का विस्तार करने के उपायों पर ग्रामीण सहकारी बैंकों के साथ राष्ट्रीय परामर्श दिनांक 29 दिसंबर, 2023 को मुंबई में आयोजित की गई।

- अमृत काल (2022-2047) के दौरान ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना (आरसीसीएस) की व्यावसायिक योजनाओं के विस्तार पर भारत का अध्ययन 10-11 जनवरी 2024 को शिलांग, मेघालय में आयोजित किया गया था।
- अमृत काल (2022-47) के दौरान व्यापार वृद्धि को बढ़ाने के उपायों पर एससीबी/डीसीसीबी के साथ क्षेत्रीय परामर्श दिनांक 23 जनवरी, 2024 को चंडीगढ़ में आयोजित किया गया। इस परामर्श में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के एससीबी और डीसीसीबी के प्रतिनिधि शामिल हुए।
-

3. अमृत काल (2022-47) के दौरान व्यापार वृद्धि को बढ़ाने के उपायों पर एससीबी/डीसीसीबी के साथ क्षेत्रीय परामर्श 30 जनवरी, 2024 को लखनऊ में आयोजित किया गया। इसमे उत्तर प्रदेश के एससीबी और डीसीसीबी के प्रतिनिधि शामिल हुए।

4. अमृत काल (2022-47) के दौरान व्यापार वृद्धि को बढ़ाने के उपायों पर एससीबी/डीसीसीबी के साथ दक्षिणी क्षेत्रीय परामर्श 22 फरवरी, 2024 को बेंगलुरु में आयोजित किया गया। अमृत काल (2022-2047) के दौरान एसटीसीसीएस की व्यावसायिक योजनाओं के विस्तार और नैफ्सकॉब द्वारा बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 की धारा 24 के तहत परिभाषित कार्यों के अनुपालन से संबंधित अध्ययन दल की निम्नलिखित बैठकें आयोजित की गईं जो कि इस प्रकार हैं:-

i. 27-10-2023 - हैदराबाद में अध्ययन दल की पहली बैठक

ii. 21-12-2023 - अध्ययन दल की दूसरी बैठक (ऑनलाइन)

iii. 28-12-2023 मुंबई में अध्ययन दल की तीसरी बैठक

iv. 17-01-2024 - हैदराबाद में अध्ययन दल की चौथी बैठक

v. 15-03-2024 - हैदराबाद, तेलंगाना में अध्ययन दल की पांचवीं बैठक - "अमृत काल (2022-2047) के दौरान एसटीसीसीएस की व्यावसायिक योजनाओं के विस्तार का अध्ययन करना और बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 की धारा 24 के तहत परिभाषित कार्यों का नेफस्कोब द्वारा अनुपालन करना"

1. जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) की नेफस्कोब में सदस्यता:

नेफस्कोब ने 18 अक्तूबर , 2023 को सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) को प्रस्ताव प्रस्तुत किया ताकि डीसीसीबी को नेफस्कोब के सहयोगी सदस्य बनने के योग्य बनाने और ऐसे संशोधन को पंजीकृत करने के लिए उनके उपनियमों में संशोधन किया जा सके।

तदनुसार भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के सीआरसीएस कार्यालय ने बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 39) की धारा 11 के तहत इन उप-नियमों को पंजीकृत किया और 11 दिसंबर, 2023 को नेफस्कोब के उप-नियमों में संशोधन के पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया। दिनांक 31 मार्च, 2024 तक 61 डीसीसीबी ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया और नेफस्कोब में एसोसिएट सदस्य के रूप में नामांकन के लिए 2000/- रुपये (केवल दो हजार रुपये) का प्रवेश शुल्क भी जमा किया।

कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थानों (एसीएसटीआई) को वार्षिक प्रदर्शन पुरस्कार: राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक महासंघ (एनएएफएससीओबी) ने 1982-83 से राज्य सहकारी बैंकों (एससीबी), 2008-09 से जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) और 1998-99 से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार की एक योजना शुरु की। 16 मार्च, 2021 को आयोजित वर्चुअल बैठक में नेफस्कोब निदेशक मंडल ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) में पैक्स के लिए एक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार मेघालय राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक डॉ जे.बी. दत्ता के प्रस्ताव को मंजूरी दी। उक्त पुरस्कार को वर्ष 2021-22 से "पूर्वोत्तर क्षेत्र में पैक्स के लिए किया गया। यह डॉ जे बी दत्ता सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार" शीर्षक से पुरस्कार साल में एक बार दिया जाता है।
नेफस्कोब ने वर्ष 2012-13 से कृषि सहकारी कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थानों (एसीएसटीआई) को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार' की स्थापना की जिसका उद्देश्य प्रेरक प्रशिक्षण प्रदान करने, क्षमता निर्माण प्रयासों के लिए प्रशिक्षण, सहकारी क्षेत्र में कर्मियों के कौशल विकास, नेतृत्व विकसित करने और मानव संसाधन प्रबंधन और विकास की दिशा में उनके प्रयासों के लिए उनके द्वारा किए गए योगदान को मान्यता देना है। वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए एससीबी, डीसीसीबी, पैक्स और एसीएसटीआई को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार एनईआर क्षेत्र में पैक्स के विजेताओं को दिये गए। ये पुरस्कार श्रेया गुहा, आई ए एस , प्रमुख सचिव (सहकारिता), राजस्थान सरकार, और राजस्थान एससीबी की प्रशासक, कोंडुरु रविंदर राव, अध्यक्ष, नेफस्कोब , भीमा सुब्रह्मण्यम, एमडी, नेफस्कोब , उल्हास बी फाल देसाई, अध्यक्ष, गोवा एससीबी, द्वारा मेघराज सिंह रत्नू, आईएएस, आरसीएस, राजस्थान, तथा मांगी लाल डागा, पूर्व विधायक, वयोवृद्ध सहकारी नेता द्वारा दिनांक 26 सितंबर, 2023 को जयपुर में आयोजित पुरस्कार समारोह के दौरान प्रदान किए गए। ।

फोटो संख्या . 1

के. एन. राजन्ना, विधायक, माननीय सहकारिता मंत्री, कर्नाटक सरकार और नेफस्कोब निदेशक ने दिनांक **29** दिसंबर, **2023** को मुंबई में नेफस्कोब द्वारा आयोजित अमृत काल (**2022-2047**) के दौरान व्यापार वृद्धि का विस्तार करने के उपायों पर ग्रामीण सहकारी बैंकों के साथ राष्ट्रीय परामर्श के उद्घाटन के दौरान दीप प्रज्वलित करते हुए। (बाएं से दाएं) भीमा सुब्रह्मण्यम, प्रबंध निदेशक, नेफस्कोब और अध्यक्ष, आईसीबीए, कोंडुरु रविंदर राव, अध्यक्ष, नेफस्कोब, डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव, पूर्व सांसद, अध्यक्ष आईसीए-एपी और अध्यक्ष कृभको, दिलीप संघाणी, पूर्व सांसद एवं मंत्री, गुजरात और पूर्व अध्यक्ष नेफस्कोब, एनसीयूआई और इफको इस अवसर पर मौजूद थे।

फोटो संख्या . 2

एनसीयूआई द्वारा "ग्रामीण सहकारी बैंकिंग" पर प्रशिक्षण मॉड्यूल पर एक पुस्तिका तैयार की गई है जिसका उद्देश्य व्यवसाय विविधीकरण के माध्यम से समावेशी वित्त को बढ़ावा देना है। इसका विमोचन मुंबई में 29 दिसंबर, 2023 को नैफ्सकॉब द्वारा आयोजित अमृत काल (2022-2047) के दौरान व्यापार वृद्धि को बढ़ाने के उपायों पर ग्रामीण सहकारी बैंकों के साथ राष्ट्रीय परामर्श के दौरान किया गया। (फोटो में बाएं से दाएं) भीमा सुब्रह्मण्यम, प्रबंध निदेशक, नैफ्सकॉब और अध्यक्ष, आईसीबीए, डॉ. बिजेन्द्र सिंह, पूर्व विधायक, पूर्व अध्यक्ष, नैफ्सकॉब और अध्यक्ष, नैफेड, दिलीप संघाणी, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, गुजरात और पूर्व अध्यक्ष, नैफ्सकॉब, अध्यक्ष एनसीयूआई, इफको, डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव, पूर्व सांसद, अध्यक्ष, आईसीए-एपी एवं अन्य गणमान्य विभूति इस अवसर पर उपस्थित हैं।

1. राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक संघ लिमिटेड (नेफकार्ड)

इस संघ की स्थापना वर्ष 1960 में दीर्घकालीन सहकारी ऋण संरचना (एलटीसीसीएस) के लिए राष्ट्रीय शीर्ष संगठन के रूप में की गई थी। एलटीसीसीएस मुख्य रूप से कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के पूंजी निर्माण के लिए ऋण देता है। वर्तमान में संरचना में 16 एससीएआरडीबी शामिल हैं जिनमें से केवल तेरह ही पूरी तरह कार्यात्मक हैं। इसके अतिरिक्त जमीनी स्तर पर 1,851 परिचालन इकाइयों का नेटवर्क है और जिसकी कुल सदस्य 1.08 लाख हैं। इसमे तेरह पूरी तरह कार्यात्मक एससीएआरडीबी में से पाँच में अपनी शाखाओं के माध्यम से संचालित एकात्मक संरचना है और छह में जमीनी स्तर पर संबद्ध प्राथमिक एआरडीबी के माध्यम से संचालित संघीय संरचना है। शेष दो एससीएआरडीबी में मिश्रित संरचना है जो राज्य के कुछ क्षेत्रों में अपनी शाखाओं के माध्यम से और अन्य क्षेत्रों में संबद्ध पीसीएआरडीबी के माध्यम से संचालित होती है।

प्रमुख पहलें- 2023-24

इस संघ की प्रमुख गतिविधियों और एलटीसीसीएस में विकास के मुख्य अंश नीचे दिए गए हैं।

एससीएआरडीबी की व्यवसाय विकास योजनाएँ:-

- संघ ने वर्ष के दौरान एससीएआरडीबी की व्यवसाय विकास योजनाओं को अंतिम रूप दिया जिसका उद्देश्य कम से कम कृषि ऋण की समग्र वृद्धि दर पर व्यवसाय वृद्धि हासिल करना है जो कि प्रति वर्ष लगभग 20 प्रतिशत है।
- सदस्य बैंकों ने फेडरेशन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर व्यवसाय विकास योजना में अनुमानों को प्राप्त करने के लिए कार्य योजनाएँ तैयार कीं हैं जिन्हें फेडरेशन द्वारा सरकार और नाबार्ड को व्यवसाय विकास योजना में अनुमानों को प्राप्त करने के लिए एससीएआरडीबी को वित्त पोषण और नीति समर्थन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए भेजा गया था।

आईटी हस्तक्षेप के माध्यम से सहकारी समितियों को मजबूत बनाने की केंद्र प्रायोजित परियोजना के तहत एआरडीबी का कम्प्यूटरीकरण:-

एआरडीबी के राष्ट्रीय सम्मेलन वर्ष 2022 ने भारत सरकार को एआरडीबी के कम्प्यूटरीकरण के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने की सिफारिश की। उपर्युक्त सिफारिश के आधार पर महासंघ ने वर्तमान में कार्यान्वियन के तहत पैक्स के कम्प्यूटरीकरण की केंद्र प्रायोजित परियोजना के अनुरुप एआरडीबी के कम्प्यूटरीकरण के लिए सहकारिता मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सहकारिता मंत्रालय ने प्रस्ताव के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और योजना को अंतिम रूप देने के लिए नाबार्ड और महासंघ के साथ तीन संयुक्त बैठकें बुलाई हैं। सहकारिता मंत्रालय ने 6 अक्टूबर 2023 को 'आईटी हस्तक्षेप के माध्यम से सहकारी समितियों को मजबूत बनाने' की केंद्र प्रायोजित परियोजना के तहत एआरडीबी के कम्प्यूटरीकरण की योजना को मंजूरी दी और 16 नवंबर 2023 को योजना के कार्यान्वियन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश भी जारी किए। इस योजना में जीएसटी सहित 119.40 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत पर 13 पूरी तरह कार्यात्मक एससीएआरडीबी की 1851 परिचालन इकाइयों के कम्प्यूटरीकरण की परिकल्पना की गई है।

एआरडीबी में सुधार, पुनर्गठन और नवाचार पर अध्ययन:-

एआरडीबी के राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 की सिफारिशों के आधार पर सहकारिता मंत्रालय ने नाबार्ड के नैबकॉन्स के माध्यम से 'एआरडीबी में सुधार, पुनर्गठन और नवाचार' पर एक अध्ययन शुरु किया है। यह अध्ययन श्री ए.के. श्रीवास्तव के नेतृत्व में नैबकॉन्स द्वारा गठित एक टीम द्वारा किया गया था। अध्ययन दल ने एआरडीबी के कामकाज का अध्ययन करने के लिए फेडरेशन और सभी एससीएआरडीबी और विभिन्न राज्यों के कुछ पीसीएआरडीबी का दौरा किया और हाल ही में सरकार को मसौदा रिपोर्ट सौंपी है।

सहकारिता मंत्रालय ने अध्ययन दल की कार्यान्वियन योग्य सिफारिशों और कार्यान्वियन की समय-सीमा पर चर्चा करने के लिए नाबार्ड और फेडरेशन की तीन संयुक्त बैठकें बुलाई हैं। फेडरेशन ने मंत्रालय को सिफारिशों पर विस्तृत टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं। उम्मीद है कि अध्ययन दल की सिफारिशों को लागू करने के लिए समय-सीमा के साथ एक कार्य योजना को मंत्रालय द्वारा जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा।

अमृत काल (2022-2047) में व्यवसाय वृद्धि का विस्तार करने तथा आईआरएमए द्वारा एमएससीएस अधिनियम 2002 की धारा 24 के अनुपालन के लिए अध्ययन:-

संघ ने अमृत काल (2022-2047) के दौरान व्यवसाय विस्तार के लिए सदस्य बैंकों को अपनी सेवाएं बढ़ाने सहित संघ के कामकाज पर एक अध्ययन ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद (आईआरएमए) को सौंपा है। इस अध्ययन को सहकारिता मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित किया जाएगा। यह अध्ययन रिपोर्ट अगस्त 2024 तक प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है।

वर्ष 2023-24 के दौरान गतिविधियों का कार्यक्रम

(ए) सम्मेलन, प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएँ, सेमिनार, अध्ययन

(1) एआरडीबी की व्यवसाय विकास योजनाओं पर कार्यशाला

फेडरेशन ने व्यवसाय विकास और कार्य योजनाओं के लिए राज्यवार अनुमानों को अंतिम रूप देने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया। दिनांक 11 सितंबर, 2023 को जयपुर में नौ सदस्य बैंकों के अध्यक्षों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों सहित 28 प्रतिभागियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया।

(2) एलटीआरसीसीएस में आंतरिक सुधारों पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम: -

फेडरेशन ने एलटीआरसीसीएस में आंतरिक सुधारों पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया है जिसका उद्देश्य सुझाए गए सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए शीर्ष और जमीनी स्तर पर प्रमुख कर्मियों को तैयार करना है। वर्ष के दौरान फेडरेशन ने नाबार्ड की वित्तीय सहायता से कर्नाटक और पंजाब में ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इस वर्ष दूसरा कार्यक्रम धारवाड़ में 8 से 10 जनवरी, 2024 के दौरान आयोजित किया गया था। कर्नाटक के सभी पीसीएआरडीबी के सचिवों ने अब यह प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। इसी प्रकार पंजाब के सभी पीसीएआरडीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को भी इस वर्ष दो कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया जो क्रमशः चंडीगढ़ और अमृतसर में 10 से 12 अक्टूबर, 2023 और 11 से 13 अक्टूबर, 2023 के दौरान आयोजित किए गए थे।

संघ ने 2024-25 के दौरान उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है।

(बी) सुधार पहल के लिए कोर ग्रुप (सीजीआरआई)

एससीएआरडीबी द्वारा गठित सुधार पहल के लिए कोर ग्रुप (सीजीआरआई) की अधिकांश बैंकों में नियमित बैठकें जारी हैं। सीजीआरआई जमीनी स्तर पर स्व-संचालित सुधारों को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। सीजीआरआई ने संसाधन जुटाने के नए रास्ते, नए उत्पादों की शुरुआत, महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान और एससीएआरडीबी की रेटिंग में सुधार के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने, विभिन्न स्तरों पर प्राधिकरण और जवाबदेही के साथ-साथ वसूली और एनपीए प्रबंधन को निर्दिष्ट करने वाली सुसंगत नीतियों और अच्छी तरह से प्रलेखित प्रक्रिया को विकसित करने के उद्देश्य से कार्यात्मक क्षेत्रों पर मैनुअल तैयार करने के मुख्य क्षेत्रों में पहले से शुरु किए गए सुधारों के प्रभाव की भी समीक्षा की।

(सी) प्रकाशन

भूमि बैंक जर्नल मासिक समाचार पत्र:-
भूमि बैंक जर्नल मासिक समाचार पत्र का इस वर्ष के अंत तक कुल प्रसार अब 4000 ग्राहकों तक पहुँच गया है। समाचार पत्र में क्षेत्र की महत्वपूर्ण घटनाओं को शामिल किया गया है और सदस्य बैंकों की गतिविधियों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटनाओं की खबरें भी शामिल हैं जिसमें सहकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यक्रमों और पहलों को भी शामिल किया गया है।

वार्षिक सांख्यिकी बुलेटिन

वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक सांख्यिकी बुलेटिन प्रकाशित और प्रसारित किया गया। वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक सांख्यिकी बुलेटिन जल्द ही जारी किया जा रहा है।

एआरडीबी की मासिक प्रगति रिपोर्ट:-
फेडरेशन मासिक आधार पर सदस्य बैंकों के प्रमुख परिचालनों पर डेटा एकत्र और संकलित करता है। फरवरी 2023 से जनवरी 2024 तक के महीनों के लिए मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रसारित की गई हैं।

5. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ (एनसीएचएफ)

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ (एनसीएचएफ) सहकारी आवास क्षेत्र का एक राष्ट्रव्यापी संगठन है। वर्ष 2023-24 के दौरान एनसीएचएफ की मुख्य गतिविधियाँ और उपलब्धियाँ नीचे दी गई हैं:

प्रचार गतिविधियाँ:-

1. सदस्य एसीएचएफ को विभिन्न मुद्दों पर सभी आवश्यक सहायता और सहयोग प्रदान किया गया। उन्हें नियमित अंतराल पर महत्वपूर्ण प्रकाशन/दस्तावेज भी वितरित किए गए।

2. सदस्य एसीएचएफ के वरिष्ठ अधिकारियों और आवास सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों ने एनसीएचएफ सचिवालय का दौरा किया और मुख्य कार्यकारी के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। एनसीएचएफ ने आवास सहकारी समितियों को मजबूत करने और धन जुटाने आदि के बारे में बताया। उन्हें सरकार और अन्य संबंधित संगठनों की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने की सुविधा के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश और दस्तावेज भी प्रदान किए गए।

3. वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान एसीएचएफ द्वारा उधार, ऋण संचालन, वितरित आवास ऋण और निर्मित/वित्तपोषित इकाइयों पर जानकारी और डेटा राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को उनके वार्षिक प्रकाशन में शामिल करने के लिए भेजा गया। भारत में आवास की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट-2023 प्रस्तुत की ।

4. भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) से अनुरोध किया गया कि वह नए ऋण स्वीकृत करे तथा एलआईसी द्वारा संबंधित एसीएचएफ को दिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान पुनर्निर्धारण/एकमुश्त निपटान (ओटीएस) को मंजूरी दे। संबंधित एसीएचएफ को एलआईसी ऋणों के व्यावहारिक ओटीएस/पुनर्भुगतान पुनर्निर्धारण प्रस्ताव तैयार करने में आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया तथा एलआईसी से अनुरोध किया गया कि वह ऐसे प्रस्तावों पर उनके समक्ष आने वाली वास्तविक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार करे।

5. संबंधित राज्यों के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) से अनुरोध किया गया कि वे आवास सहकारी समितियों को भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) के साथ पंजीकृत चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा अपना ऑडिट करवाने की अनुमति दें।

6. राजस्थान राज्य सहकारी आवास संघ (राजस्थान हाउसफेड) ने विभिन्न प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, कोटा-स्टोन, करौली-स्टोन आदि में निर्माण सामग्री का व्यवसाय शुरू किया है तथा अन्य राज्यों के एसीएचएफ और आवास सहकारी समितियों के साथ निर्माण सामग्री का व्यवसाय करने का इरादा रखता है। अन्य सदस्य एसीएचएफ से अनुरोध किया गया कि वे राजस्थान हाउसफेड के प्रस्ताव पर विचार करें तथा अपनी नियमित आय के पूरक के रूप में निर्माण सामग्री का व्यवसाय शुरू करने की संभावनाएं भी आवश्यकतानुसार तलाशें।

7. नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2023 के प्रारूप पर टिप्पणियां और सुझाव सहकारिता मंत्रालय को भेजे गए।

8. एनसीएचएफ आदि के संबंध में अमृत काल (2022-2047) के लिए विकास कार्यक्रम और लक्ष्य तथा आवास सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक सहायता के संबंध में एमएससीएस अधिनियम, 2002 की धारा 24 के अनुपालन पर एक पीपीटी प्रस्तुति हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सहकारिता मंत्रालय को भेजी गई।

9. संबंधित राज्यों के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों से अनुरोध किया गया कि वे आवास सहकारी समितियों आदि के सदस्यों द्वारा उठाई गई सार्वजनिक शिकायतों पर गौर करें। भारत सरकार के लोक शिकायत पोर्टल पर आवास सहकारी समितियों से संबंधित उठाए गए प्रश्नों के उत्तर सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर अपलोड किए गए। एनसीएचएफ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन.एस. मेहरा ने 23.05.2023 और 18.09.2023 को नई दिल्ली में सार्वजनिक शिकायतों और अपीलों की समीक्षा के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार (एच एंड कोऑर्ड) की अध्यक्षता में समीक्षा बैठकों में भाग लिया।

10. 'सहकारिता पर राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार करने हेतु इनपुट' पर एक विस्तृत नोट एनसीएचएफ के निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और एसीएचएफ के सभी प्रबंध निदेशकों को सूचना के लिए प्रसारित किया गया। मुख्य कार्यकारी, एनसीएचएफ ने 21.11.2023 को नई राष्ट्रीय सहयोग नीति 2023 के प्रारूपण में शामिल प्रक्रिया और दृष्टिकोण के बारे में जानकारी देने के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति सचिवालय, वैमनिकॉम द्वारा हाइब्रिड मोड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'उत्तरी और मध्य क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय कार्यशाला' में भाग लिया। कार्यशाला को नई राष्ट्रीय सहयोग नीति का मसौदा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तरीय समिति के अध्यक्ष श्री सुरेश प्रभु ने संबोधित किया था।

11.. आवास सहकारी समितियों की संपत्तियों का एनसीएचएफ के माध्यम से बीमा कराया गया। सदस्य एसीएचएफ और प्राथमिक आवास सहकारी समितियों से अनुरोध किया गया कि वे अपनी आवास परियोजनाओं को एनसीएचएफ के माध्यम से कम प्रीमियम पर 'भारत गृह रक्षा नीति' के तहत कवर करें। संपत्तियों के सामान्य बीमा के संबंध में आवास सहकारी समितियों और अन्य संबंधितों को आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया।

12. बिजय कुमार सिंह, एमएलसी, अध्यक्ष, एनसीएचएफ, एनसीएचएफ निदेशक, श्री एन.एस. एनसीएचएफ मुख्य कार्यकारीअधिकारी, श्री मेहरा और एसीएचएफ के अधिकारियों ने 13.10.2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहकारितामंत्रालय द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लिया जिसमें सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने और 'सहकार से समृद्धि' के विजन को साकारकरने के लिए मंत्रालय द्वारा की गई 54 प्रमुख पहलों और इन पहलों के कार्यान्वयन में अब तक हुई प्रगति पर प्रस्तुति दी गई।

.13.. सहकारिता मंत्रालय द्वारा 06.07.2021 को अपने गठन के बाद से 'सहकारिता के माध्यम से समृद्धि' के विजन को साकार करने के लिए की गई प्रमुख पहलों (54 नई पहलों) वाली पुस्तिका एनसीएचएफ के निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और सदस्य एसीएचएफ के सभी प्रबंध निदेशकों को वितरित की गई।

14.. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की सरकार की पहल के एक हिस्से के रूप में एनसीएचएफ के संचालन में डिजिटल लेनदेन को बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रयास किए गए। एनसीएचएफ के कार्यालय में डिजिटल लेनदेन का मासिक/त्रैमासिक विवरण नियमित रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को भेजा जाता था।

शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना प्रसार

- राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केंद्र (एनसीसीई) द्वारा एनसीएचएफ के सहयोग से 11-13 सितंबर, 2023 तक नई दिल्ली में आवास सहकारी समितियों के अध्यक्षों और निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसे एनसीएचएफ के एमडी ने संबोधित किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से कुल 58 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- संबंधित राज्यों के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) से अनुरोध किया गया कि वे अपने-अपने राज्यों में आवास सहकारी समितियों के संचालन के बारे में जानकारी और डेटा भेजें। एनसीएचएफ और इसके सदस्य एसीएचएफ से संबंधित डेटा को सहकारिता मंत्रालय के राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पोर्टल में भी दर्ज किया गया।

- सम्मेलन एवं वेबिनार का आयोजन एनसीएचएफ एसीएचएफ और आवास सहकारी समितियों के कर्मियों के लिए सम्मेलन/कार्यशाला/अध्ययन दौरे/वेबिनार आदि आयोजित करता रहा हैं और ऐसे आयोजनों में सहकारी आवास क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी करता रहा हैं।

- 70वां अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह 14-20 नवंबर, 2023 तक "भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में सहकारी समितियों की भूमिका और एसजीडी" विषय पर मनाया गया। श्री पुरुषोत्तम रुपाला, माननीय केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने 16.11.2023 को नई दिल्ली में एनसीयूआई सभागार में सहकारी सप्ताह समारोह-2023 का उद्घाटन किया। श्री दिलीप संघाणी , पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री, गुजरात सरकार तथा अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) ने इस समारोह की अध्यक्षता की।

- सहकारी सप्ताह समारोह-2023 के उपलक्ष्य में एनसीएचएफ ने 'एनसीएचएफ बुलेटिन' का एक विशेष अंक निकाला जिसका विमोचन श्री पुरुषोत्तम रुपाला, माननीय केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने 16 नवंबर, 2023 को एनसीयूआई द्वारा आयोजित सहकारी सप्ताह समारोह के उद्घाटन समारोह में किया। उपरोक्त प्रकाशन उद्घाटन समारोह के प्रतिभागियों के बीच वितरित किया गया। श्री एन.एस. मेहरा, मुख्य कार्यकारी, एनसीएचएफ भी उद्घाटन समारोह में शामिल हुए।

- एनसीएचएफ के मुख्य कार्यकारी, एन.एस. मेहरा ने 25 जनवरी, 2024 को 'सहकारी आवास समितियों के प्रबंधन' पर एक वेबिनार में उद्घाटन भाषण दिया। एनसीयूआई द्वारा आयोजित वेबिनार में 25 जनवरी, 2024 से 3 फरवरी, 2024 तक प्रतिष्ठित संसाधन व्यक्तियों द्वारा व्याख्यानों की एक श्रृंखला शामिल थी जिसका उद्देश्य एनसीयूआई द्वारा लाए गए 'आवास सहकारी समितियों पर प्रशिक्षण मॉड्यूल' के बारे में संवेदनशील बनाना और जागरूकता पैदा करना था।

प्रकाशन

एनसीएचएफ समय-समय पर विभिन्न प्रकाशन निकालता रहा है। वर्ष 2023-24 के दौरान इसने विभिन्न प्रकाशन निकाले जैसे कि मासिक पत्रिका 'एनसीएचएफ बुलेटिन' (विश्व पर्यावास दिवस और सहकारी सप्ताह समारोह पर विशेष अंक सहित), एक मासिक ई न्यूज़लेटर 'सहकारी और आवास आवाज़', अंग्रेजी-हिंदी शब्दकोश, वर्ष 2022-23 के लिए एनसीएचएफ की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षा रिपोर्ट हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बनाई गई। सहकारी आवास पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हैंडआउट्स बनाए गए।

एनसीएचएफ कार्यालय में राजभाषा (हिंदी) का कार्यान्वयन

सहकारी आवास और संबंधित क्षेत्रों पर हिंदी में लिखे गए लेख और हिंदी में अन्य प्रासंगिक समाचार नियमित रूप से 'एनसीएचएफ बुलेटिन' में प्रकाशित किए गए। 14-29 सितंबर, 2023 को मनाए गए हिंदी पखवाड़े और 14.09.2023 को मनाए गए हिंदी दिवस के दौरान एनसीएचएफ के कार्यालय परिसर में प्रमुख स्थानों पर बैनर और पोस्टर/तख्तियाँ प्रदर्शित की गईं। वर्ष 2022-23 के लिए एनसीएचएफ की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षा रिपोर्ट हिंदी में तैयार की गई।

(i) विश्व पर्यावास दिवस समारोह

विश्व पर्यावास दिवस समारोह-2023 के उपलक्ष्य में एनसीएचएफ ने 'एनसीएचएफ बुलेटिन' का एक विशेष अंक निकाला जिसका विमोचन श्री हरदीप पुरी, माननीय केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने श्री मनोज जोशी, आईएएस, सचिव, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा यूएन-हैबिटेट के प्रतिनिधियों और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया।

(ii) एनसीएचएफ वेबसाइट का अद्यतन

एनसीएचएफ वेबसाइट (www.nchfindia.net) को रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान नियमित रूप से अद्यतन किया गया। आवास सहकारी समितियों के सदस्यों तथा अन्य संबंधित लोगों के लाभ के लिए आवास सहकारी समितियों/विकास प्राधिकरणों/आवास बोर्डों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को एनसीएचएफ बुलेटिन में शामिल किया गया। जिसके सभी अंक (अप्रैल, 2023 से मार्च, 2024) वेबसाइट पर अपलोड किए गए।

(iii) एनसीएचएफ सचिवालय का अध्ययन दौरा

वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न प्रशिक्षुओं, छात्रों, सहकारिताओं ने एनसीएचएफ सचिवालय का अध्ययन दौरा किया जिसका विवरण इस प्रकार हैं:

(iv) (i) नेपाल के राष्ट्रीय सहकारी संघ के पूर्व अध्यक्ष श्री शांता राज शर्मा नेउपाने ने 03.05.2023 को एनसीएचएफ सचिवालय का दौरा किया और एनसीएचएफ के मुख्य कार्यकारी श्री एन.एस. मेहरा से मुलाकात कर नेपाल में आवास सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की ताकि सहकारी आवास आंदोलन को मजबूत करने के लिए दोनों देशों की सहकारी समितियों के बीच सहयोग का निर्माण किया जा सके।

(ii) राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केंद्र (एनसीसीई) की ओर से 'भारतीय सहकारी समितियों के अध्यक्षों/महिला निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम' में भाग लेने वाली 38 महिला सहकारिताओं के एक समूह ने अपने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में 09.05.2023 को नई दिल्ली में एनसीएचएफ सचिवालय का अध्ययन दौरा किया।

(iii) राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केंद्र (एनसीसीई) के 'नेपाली सहकारी नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम' के प्रतिभागियों के रूप में नेपाल के 27 सहकारी नेताओं के एक समूह ने अपने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में 15.06.2023 को नई दिल्ली में एनसीएचएफ सचिवालय का अध्ययन दौरा किया।

(iv) महाराष्ट्र राज्य सहकारी आवास संघ और पुणे जिला सहकारी आवास संघ के पदाधिकारियों सहित तीन सहकारी नेताओं के एक समूह ने 03.07.2023 को एनसीएचएफ सचिवालय का दौरा किया और एनसीएचएफ के मुख्य कार्यकारी से मुलाकात की।

(V) देश भर से राज्य स्तरीय एसीएचएफ, जिला सहकारी आवास संघों और प्राथमिक आवास सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 45 सहकारी नेताओं के एक समूह ने 11-13 सितंबर, 2023 तक दिल्ली में एनसीएचएफ के सहयोग से राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केंद्र (एनसीसीई) द्वारा आयोजित आवास सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम के लिए अपने पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में 12.09.2023 को एनसीएचएफ सचिवालय का अध्ययन दौरा किया।

(vi) राष्ट्रीय संयुक्त प्रमुख, आवास प्रकोष्ठ, सहकार भारती के नेतृत्व में सहकार भारती के तीन प्रतिनिधियों के एक समूह ने 12.09.2023 को एनसीएचएफ का दौरा किया।

(vii) पुणे, महाराष्ट्र में प्राथमिक और जिला स्तर पर कार्यरत आवास सहकारी समितियों के पदाधिकारियों और सदस्यों सहित 10 सहकारी नेताओं के एक समूह ने 13.09.2023 को नई दिल्ली में एनसीएचएफ सचिवालय का दौरा किया और आवास सहकारी समितियों को मजबूत करने और महाराष्ट्र में उनके द्वारा की गई पहलों के बारे में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एनसीएचएफ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से मुलाकात की।

(viii) राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केंद्र (एनसीसीई), नई दिल्ली से 'सहकारी शिक्षा और विकास में डिप्लोमा' प्राप्त करने वाले 36 प्रशिक्षुओं के एक समूह ने 05.10.2023 को एनसीएचएफ सचिवालय का अवलोकन अध्ययन दौरा किया।

(ix) राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केंद्र (एनसीसीई) के 'भारतीय सहकारी समितियों के अध्यक्षों/महिला निदेशकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम' के 32 प्रतिभागियों के एक समूह ने अपने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में 06.12.2023 को नई दिल्ली में एनसीएचएफ सचिवालय का अध्ययन दौरा किया।

(x) एनसीयूआई की सहकारी कनेक्ट पहल के तहत सहकारिता पर प्रशिक्षण जागरूकता कार्यक्रम से गुजर रहे संस्कृति स्कूल, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली के 26 छात्रों के एक समूह ने 02.01.2024 को एनसीएचएफ का अध्ययन दौरा किया।

आजादी का अमृत महोत्सव मनाना

एसीएचएफ के सदस्यों से आजादी का अमृत महोत्सव मनाने तथा अपने-अपने राज्यों में जागरुकता अभियान चलाने का अनुरोध किया गया जिसमें सहकारी सिद्धांतों, सहकारी समितियों के लाभों, सदस्यों के अधिकारों और कर्तव्यों तथा उनके संचालन क्षेत्र में आवास सहकारी समितियों के उत्कृष्ट उदाहरण के बारे में जानकारी दी गई।

एनसीएचएफ के कर्मचारियों को आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान के दौरान 13-15 अगस्त, 2023 तक अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के संबंध में परामर्श जारी किया गया।

एनसीएचएफ के सोशल मीडिया खाते

भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने देश भर में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए विभिन्न पहल की हैं। मंत्रालय का इरादा राष्ट्रीय सहकारी संघों द्वारा लाए गए सोशल मीडिया और आवधिक प्रकाशनों की सीमा और पहुंच को बढ़ाकर सहकारी आंदोलन की पहुंच को जमीनी स्तर तक पहुंचाना है। इस बात पर जोर दिया गया है कि राष्ट्रीय संघों को देश भर में सभी स्तरों यानी राज्य, जिला और प्राथमिक स्तर पर सदस्यों से जुड़ने की जरूरत है। उपरोक्त के मद्देनजर, एनसीएचएफ ने सहकारी क्षेत्र, विशेष रुप से सहकारी आवास क्षेत्र और सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों को प्रचारित करने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है:-
फेसबुक यूज़रनेम: NchfNchf (https://www.facebook.com/nchf.nchf.14),
इंस्टाग्राम यूज़रनेम: nchf1969 (https://www.instagram.com/nchf1969/),
ट्विटर (X) यूज़रनेम: @nchf1969 (https://www.twitter.com/nchf1969)।

सहकारिता मंत्रालय, माननीय प्रधान मंत्री, माननीय गृह और सहकारिता मंत्री और एनसीयूआई के सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करने के बारे में एनसीएचएफ से संबंधित अपेक्षित जानकारी निर्धारित प्रोफार्मा में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) को भेजी गई।

विविध

1. एनसीएचएफ ने 21.06.2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) मनाया और इस अवसर पर कर्मचारियों को योग शपथ दिलाई गई। एनसीएचएफ सचिवालय में प्रमुख स्थानों पर योग और ध्यान पर एक बैनर, योग चार्ट और प्रेरक उद्धरण प्रदर्शित किए गए। एनसीएचएफ के कर्मचारियों के बीच कॉमन योग प्रोटोकॉल पर पुस्तिका भी वितरित की गई।

2. 1-15 जून, 2023, 1-15 अक्टूबर, 2023 और 1-15 फरवरी, 2024 के दौरान एनसीएचएफ के कार्यालय परिसर में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया और सफाई/सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया। उपरोक्त पखवाड़े के दौरान एनसीएचएफ के कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता शपथ भी ली गई और कार्यालय परिसर में एक बैनर प्रदर्शित किया गया। कार्यालय भवन में प्रमुख स्थानों पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में स्वच्छता शपथ प्रदर्शित की गई।

3. बहुराज्यीय सहकारी समितियां (संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 120 (डी)(ई)(एफ) के अंतर्गत रिटर्न दाखिल करने के संबंध में निर्धारित प्रपत्र के अनुसार 31.03.2023 तक वर्ष 2022-23 के लिए एनसीएचएफ से संबंधित जानकारी, वर्ष 2022-23 के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की रिपोर्ट और एनसीएचएफ की आम सभा द्वारा अनुमोदित वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अधिशेष वितरण की योजना को सहकारिता मंत्रालय के केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के नए पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया।

4. एनसीएचएफ सचिवालय में 30 अक्टूबर से 5 नवंबर, 2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

5. एनसीएचएफ सचिवालय ने भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में 26.11.2023 को संविधान दिवस मनाया।

6) श्री एन.एस. एनसीएचएफ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मेहरा द्वारा लिखित 'अमृत काल में आवास सहकारी समितियों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक समस्याएं, संभावनाएं और समर्थन' शीर्षक वाला यह आलेख 1-2 जुलाई, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित 17वें भारतीय सहकारी सम्मेलन के अवसर पर एनसीयूआई द्वारा प्रकाशित स्मारिका में प्रकाशित किया गया।

1.भारतीय राष्ट्रीय श्रम सहकारी संघ लिमिटेड (एनसीएलएफ)

सदस्यता

दिनांक 31 मार्च, 2024 तक भारतीय राष्ट्रीय श्रम सहकारी संघ लिमिटेड (एनएलसीएफ) की सदस्यता 414 थी जिसका प्रतिनिधित्व भारत सरकार के साथ-साथ राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सहित देश के विभिन्न हिस्सों से श्रम अनुबंध/निर्माण और वन श्रम सहकारी समितियों द्वारा किया गया था।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

ए) नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम:

1. श्रम सहकारी समितियों के पदाधिकारियों के लिए नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

भारतीय राष्ट्रीय श्रम सहकारी संघ लिमिटेड (एनएलसीएफ) ने 25 से 27 सितंबर 2023 तक एनसीसीई में भारतीय श्रम सहकारी समितियों के पदाधिकारियों के लिए तीन दिवसीय नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना और पंजाब राज्यों के पैंतीस प्रतिभागियों ने भाग लिया।

2. श्रम सहकारी समितियों के पदाधिकारियों के लिए नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

भारतीय राष्ट्रीय श्रम सहकारी संघ लिमिटेड (एनएलसीएफ) ने 30 नवंबर 2023 से 2 दिसंबर 2023 तक शिमला में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्यों के श्रम सहकारी समितियों के पदाधिकारियों के लिए तीन दिवसीय नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में हरियाणा और पंजाब राज्यों के 26 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

3. श्रम सहकारी समितियों के पदाधिकारियों के लिए नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

भारतीय राष्ट्रीय श्रम सहकारी संघ लिमिटेड (एनएलसीएफ) ने 26 से 28 फरवरी 2024 तक एनसीसीई में भारतीय श्रम सहकारी समितियों के पदाधिकारियों के लिए तीन दिवसीय नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 31 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

बी) स्व-वित्तपोषित प्रशिक्षण कार्यक्रम

हरियाणा राज्य के राज्य, जिला और प्राथमिक श्रम सहकारी समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों और प्रबंधकों के लिए अध्ययन दौरा सह प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय राष्ट्रीय श्रम सहकारी संघ लिमिटेड (एनएलसीएफ) ने 23 से 27 फरवरी, 2024 तक गोवा में हरियाणा राज्य के राज्य, जिला और प्राथमिक श्रम सहकारी संघों/समितियों के अध्यक्षों/निदेशकों और प्रबंधकों के लिए पांच दिवसीय और चार रात्रि का अध्ययन दौरा सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में हरियाणा राज्य के विभिन्न जिलों से 15 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया।

3. अनुसंधान परामर्श सेवाएँ और प्रकाशन

ए. परामर्श सेवाएँ

एनएलसीएफ ने आवश्यकतानुसार वर्ष के दौरान समय-समय पर विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न जिला श्रम सहकारी संघों को परामर्श प्रदान किया।

बी. प्रकाशन

संदर्भित वर्ष के दौरान श्रम सहकारी समितियों के सदस्यों और अन्य लोगों द्वारा उपयोग के लिए एनएलसीएफ द्वारा निम्नलिखित प्रकाशन प्रकाशित किए गए।:-

1. एनएलसीएफ की पत्रिका "लेबर कॉप्स"।
2. एन.एल.सी.एफ. का मासिक ई-न्यूज़ बुलेटिन
3. एन.एल.सी.एफ. का अद्यतन विवरणिका
4. एन.एल.सी.एफ. के अद्यतन उपनियम

7. राष्ट्रीय मत्स्य सहकारी संघ लिमिटेड (फिशकोफेड)

फिशकोफेड ने विभिन्न राज्यों में मछुआरों के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। इस कार्यक्रम के तहत मछुआरों को सरकारी योजनाओं (पी.एम.एम.एस.वाई.) और सहकारी सिद्धांतों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण सत्रों और अध्ययन दौरों के माध्यम से मछुआरों को न केवल सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के बारे में जागरूक किया गया बल्कि सहकारी संगठनों और उनके कामकाज के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। इस पहल ने मछुआरों को सशक्त बनाया और उन्हें उनके विकास के लिए आवश्यक संसाधनों के बारे में जानकारी प्रदान की।

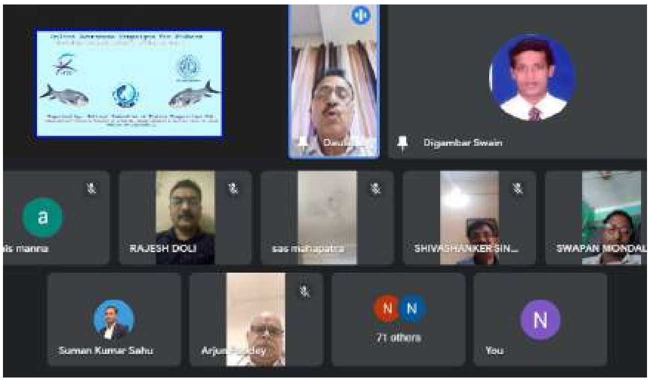

3.कार्यक्रमों की झलकियाँ:

1 अक्टूबर 2023 को 'स्वच्छता के लिए एक घंटे का श्रमदान' कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी देखी गई।

8. नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड (नैफकब)

नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड (नैफकब) देश में शहरी सहकारी बैंकों और क्रेडिट सोसाइटियों का शीर्ष स्तरीय निकाय है। 31 मार्च 2024 तक 10117 शाखाओं के साथ 1502 शहरी सहकारी बैंक थे जिनमें से 52 अनुसूचित बैंक थे जिनमें 35 बहुराज्यीय शहरी बैंक, 23 बहुराज्यीय गैर अनुसूचित बैंक और 1412 गैर अनुसूचित बैंक शामिल थे।

यह पूरे भारत में कार्यरत लगभग 1502 शहरी सहकारी बैंकों और 50,000 सहकारी ऋण समितियों का प्रतिनिधित्व करता है। 31 मार्च 2024 तक नैफकब की कुल सदस्यता 1776 है जिसमें से 963 शहरी सहकारी बैंक और 791 सहकारी ऋण समितियां नैफकब के सदस्य हैं। शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र में 22 राज्य संघ/एसोसिएशन हैं अन्य स्रोत सदस्य-संस्थाओं से वार्षिक सदस्यता शुल्क, प्रवेश शुल्क, प्रकाशनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों से आय, अध्ययन दौरे, सम्मेलन और सेमिनार हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान नेफकब की गतिविधियाँ

वर्ष 2023-24 के दौरान नेफकब की प्रमुख गतिविधियाँ:-

न ेफकब ने वर्ष के दौरान कई गतिविधियाँ कीं जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

1. क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए सहकारिता मंत्रालय के साथ सक्रिय जुड़ाव।

नेफकब के अनुरोध पर सहकारिता मंत्रालय और आरबीआई के अधिकारियों के साथ यूसीबी के मुद्दों पर चर्चा करने और क्षेत्र के तेजी से विकास को सुनिश्चित करने के तरीकों का पता लगाने के लिए मंत्रालय में एक कार्य समूह बनाया गया है। इनमें से कुछ मुद्दे हैं- शाखा विस्तार, कुल ऋण पोर्टफोलियो के 40% से 70% तक प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के प्रतिशत में भारी वृद्धि, सभी यूसीबी के लिए समान अवसर प्रदान करना इत्यादि ।

सहकारी ऋण समितियों पर संगोष्ठी

21 जून 2023 को लिनैक, एनसीडीसी, गुड़गांव में सहकारी ऋण समितियों के समक्ष चुनौतियों पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई। इसमे श्री लक्ष्मी दास, अध्यक्ष नेफकब मुख्य अतिथि थे।

संगोष्ठी में निम्नलिखित विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया:-

- सहकारी समितियों को प्रभावित करने वाले आयकर मुद्दे और जीएसटी से संबंधित मुद्दे
- एमएसएमई के माध्यम से सहकारी क्षेत्र का विकास
- सहकारी समितियों में डिजिटल परिवर्तन- प्रतिस्पर्धी माहौल में अस्तित्व और विकास के लिए आवश्यक
- सहकारी समितियों के लिए कुशल रिकॉर्ड प्रबंधन-सी-केवाईसी आदि।

3. नेफकब ने यूसीबी क्षेत्र को लगातार सहयोग देने के लिए माननीय केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमितभाई शाह को धन्यवाद दिया। नेफकब अध्यक्ष श्री ज्योतिंद्र मेहता ने पूर्व मुख्य कार्यकारी और नेफकब सलाहकार श्री डी. कृष्णा और मुख्य कार्यकारी श्री योगेश शर्मा के साथ 21 जुलाई, 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह से मुलाकात की और शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को हल करने में उनके सहयोग और योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। अन्य मुद्दों के अलावा पैक्स को मजबूत करने और उन्हें सीएससी के रूप में कार्य करने के लिए एक मंच प्रदान करने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई।

4. **नैफकब ने शहरी सहकारी बैंकों में हाल के घटनाक्रमों पर एक बैठक आयोजित की**

   नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड (नैफकब) ने 31 जुलाई, 2023 को दिल्ली में शहरी सहकारी बैंकों के राज्य संघों और जिला संघों तथा चुनिंदा बड़े अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की बैठक बुलाई जिसका उद्देश्य नैफकब द्वारा किए गए सभी प्रयासों, विनियामक मोर्चे पर सकारात्मक विकास और अम्ब्रेला संगठन की स्थापना में हुई प्रगति से उन्हें अवगत कराना था।

सहकारिता मंत्रालय द्वारा यूसीबी और क्रेडिट सोसाइटियों के परिवर्तन पर टास्क फोर्स का गठन।

सहकारिता मंत्रालय ने यूसीबी और क्रेडिट सोसाइटियों से संबंधित मुद्दों पर मंत्रालय को सलाह देने और बहुराज्य शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र के परिवर्तन के लिए आवश्यक इनपुट प्रदान करने के लिए नेफकब के शहरी सहकारी बैंकों और क्रेडिट सोसाइटियों के परिवर्तन पर एक टास्क फोर्स का गठन किया है।

मानव संसाधन पहल - वेबिनार/प्रशिक्षण कार्यक्रम/गोलमेज/सम्मेलन

इस वर्ष के दौरान संघ ने भारतीय रिजर्व बैंक, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे, राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केंद्र और शहरी सहकारी बैंकों के सदस्य राज्य संघों के सहयोग से शहरी सहकारी बैंकों, खासकर छोटे शहरी बैंकों, महिला बैंकों और सहकारी ऋण समितियों के लाभ के लिए साइबर धोखाधड़ी, डिजिटल बैंकिंग और साइबर सुरक्षा, साइबर बीमा, ऋण प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, कॉर्पोरेट प्रशासन आदि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 25 वेबिनार/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

इसमे अनुसूचित और बहु-राज्य सहकारी शहरी सहकारी बैंकों और ऋण समितियों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन 12 अक्टूबर, 2023 को आयोजित किया गया था जिसका उद्घाटन माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने किया था।

पत्रिकाओं और पुस्तिकाओं का प्रकाशन:-

इसमे दो प्रमुख प्रकाशनों (i) त्रैमासिक पत्रिका "अर्बन क्रेडिट" और (ii) पाक्षिक समाचार पत्र "कॉप बैंकिंग" के नियमित प्रकाशन के अलावा इस वर्ष के दौरान कई पुस्तिकाएँ भी प्रकाशित की गईं।

9. राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना संघ लिमिटेड (एनएफसीएसएफ)

राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना संघ लिमिटेड (एनएफसीएसएफ) की स्थापना 1960 में संबद्ध सहकारी चीनी कारखानों और सहकारी चीनी कारखानों के राज्य संघों के कामकाज को समन्वित और सुविधाजनक बनाने तथा नए सहकारी चीनी कारखानों को बढ़ावा देने और स्थापित करने में सहायता करने के लिए की गई थी। हालांकि एनएफसीएसएफ की स्थापना ने परिदृश्य को बदल दिया है। चीनी उत्पादन और कुल उत्पादन में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 1982, 1988 से 1993, 1995, 1996, 2000, 2018 और 2022 के दौरान भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक बनने का गौरव हासिल किया है। 31 मार्च, 2024 तक 762 चीनी मिलें स्थापित थीं जिनमें से 284 सहकारी क्षेत्र में हैं। चीनी उत्पादन ब्राजील के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक है। भारत का चीनी उत्पादन विश्व के चीनी उत्पादन का 18.10% है जिसमें सहकारी समितियों की हिस्सेदारी लगभग 5.40% है। यह उद्योग भारत में कपड़ा उद्योग के बाद दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है जो मुख्य रूप से गन्ने की खेती पर केंद्रित है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं। सहकारी चीनी क्षेत्र ने भारत को घाटे वाले चीनी उत्पादक देश से अधिशेष चीनी उत्पादक देश में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सहकारी चीनी क्षेत्र ने चीनी उत्पादन, इथेनॉल उत्पादन और सह-उत्पादन के मोर्चे पर उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। देश के ग्रामीण इलाकों में इसके सामाजिक-आर्थिक विकास ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने में मदद की है।

एनएफसीएसएफ के रिकॉर्ड के अनुसार 31 मार्च 2024 तक कुल 762 चीनी मिलें स्थापित हैं। इन स्थापित 762 चीनी मिलों में से 284 चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र की हैं जिनमें से 31 मार्च 2024 तक 203 सहकारी चीनी मिलें चालू थीं जबकि 2023-24 के दौरान 228 चीनी मिलें चालू नहीं थीं। इसमें से 147 मिलें सार्वजनिक और निंजी क्षेत्र की हैं और 81 मिलें सहकारी क्षेत्र की हैं। 31 मार्च 2024 तक सीजन के दौरान कुल चीनी उत्पादन 299.45 लाख टन था जिसमें से सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित चीनी 87.20 लाख टन थी।

एनएफसीएसएफ द्वारा तकनीकी-वाणिज्यिक सेवाएँ

वर्ष के दौरान एनएफसीएसएफ ने भारत के गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में पुनर्वास, आधुनिकीकरण, विस्तार, सह-उत्पादन और मूल्यांकन परियोजना रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और डिस्टिलरी परियोजनाओं के लिए परियोजना रिपोर्ट के लिए 71 परियोजनाएँ शुरू कीं। इन परियोजना रिपोर्टों में गन्ना विकास कार्यक्रम, मौजूदा संयंत्र का मूल्यांकन और प्रौद्योगिकी के उन्नयन और आधुनिकीकरण, सह-उत्पादन, मशीनरी विनिर्देशों, वित्तीय पुनर्गठन और वित्तपोषण पैटर्न आदि के लिए सिफारिशें शामिल थीं।

2023-24 में गन्ना सलाह और गन्ना विकास गतिविधियाँ

एनएफसीएसएफ गन्ना उत्पादकों और सहकारी चीनी उद्योग के लाभ के लिए वैज्ञानिक प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दे रहा है। एनएफसीएसएफ किसानों की गन्ना उपज और मिलों की चीनी रिकवरी में सुधार के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए पूरे भारत में सभी सहकारी चीनी मिलों का मार्गदर्शन कर रहा है। राष्ट्रीय महासंघ ने सभी चीनी मिलों, गन्ना विभाग और विभिन्न राज्यों के संबंधित राज्य कृषि विभाग को सलाह दी है कि बड़े पैमाने पर गन्ना खेती के लिए गन्ना किसानों को नई किस्मों के आवश्यक बीज उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है जिससे मिलों के प्रति इकाई क्षेत्र में चीनी और गन्ना उपज बढ़ाने में मदद मिलेगी।

देश में विभिन्न सहकारी चीनी मिलों की दैनिक पेराई क्षमता में वृद्धि की गई है, जिसके लिए मिलों के संचालन के आर्थिक पैमाने को प्राप्त करने के लिए कच्चे माल की सुचारु और निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होगी।

हालांकि प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण, मिलों की आवश्यक 180 दिनों की पेराई अवधि को प्राप्त करने के लिए गन्ने की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है। इससे चीनी मिलों के परिचालन और वित्तीय स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

तकनीकी दक्षता पुरस्कार 2022-23

देश में सहकारी चीनी मिलों के प्रदर्शन का नियमित रूप से एनएफसीएसएफ के गन्ना सलाह विभाग द्वारा एनएफसीएसएफ के एमडी और भारत सरकार के निदेशक (चीनी नीति) की अध्यक्षता में और एनएफसीएसएफ के तकनीकी विशेषज्ञों की अध्यक्षता में मूल्यांकन किया जाता है। वर्ष 2022-23 के दौरान, प्रदर्शन और दक्षता पुरस्कारों के मूल्यांकन के लिए पूरे भारत में कुल 92 चीनी मिलों ने भाग लिया।

एनएफसीएसएफ के प्रकाशन

इस वर्ष के दौरान एनएफसीएसएफ ने अपने नियमित प्रकाशन भी जारी रखे जैसे कि 'सहकारी चीनी प्रेस समाचार' साप्ताहिक पत्रिका जिसमें चीनी और उससे संबंधित विषयों पर वर्तमान रिपोर्टें होती हैं और 'सहकारी चीनी' मासिक पत्रिका जिसमें गन्ना, चीनी और उसके उप-उत्पादों तथा सरकारी आदेशों, अधिसूचनाओं और सांख्यिकीय सूचनाओं पर उपयोगी तकनीकी लेख होते हैं। इसने वर्ष के दौरान चीनी उद्योग की समस्याओं के बारे में जनता और पत्रकारों को जागरुक करने और चीनी उद्योग की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए मीडिया के साथ घनिष्ठ संपर्क भी बनाए रखा।

सोशल मीडिया

इसके अलावा सहकारी चीनी कारखाना संघ लिमिटेड का राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय है और इसे सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं द्वारा खूब सराहा जा रहा है जिसमें मुख्य रूप से किसान, सदस्य, सरकारी संगठन, शैक्षणिक संस्थान, अन्य सहकारी संगठन, व्यापारी, पत्रकार आदि शामिल हैं। एनएफसीएसएफ के सोशल मीडिया अकाउंट पर देश भर से अच्छी संख्या में फॉलोअर्स हैं। फेडरेशन के सोशल मीडिया हैंडल इस प्रकार हैं:-

फेसबुक : @CoopsugarIndia www.facebook.com/CoopSugarIndia

ट्विटर : @CoopsugarIndia www.twitter.com/CoopSugarIndia,

इंस्टाग्राम : @CoopsugarIndia www.instagram.com/CoopSugarIndia

एनएफसीएसएफ की 64वीं वार्षिक आम सभा

राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना संघ लिमिटेड की आम सभा की चौंसठवीं वार्षिक बैठक 19 अगस्त, 2023 को दिल्ली में आयोजित की गई। इसमे विभिन्न विषयों पर चर्चा के दौरान सदस्यों द्वारा चर्चा की गई जिन्होंने भारतीय सहकारी चीनी उद्योग को बढ़ावा देने में गहरी रुचि दिखाई। इसमे सदस्यों ने सरकार के स्तर पर नीतिगत मुद्दों से निपटने और सदस्य कारखानों को सहायता प्रदान करने में एनएफसीएसएफ द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।

अध्याय 13

राज्य स्तरीय सहकारी संगठनों की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

परिवार विकास सहकारी बचत और ऋण सोसायटी लिमिटेड (फैमको)

1. परिचय:

इस संस्था को 23 जुलाई, 2009 को केंद्रीय सहकारी रजिस्ट्रार, नई दिल्ली द्वारा एक बहु-राज्य सहकारी समिति के रुप में पंजीकृत किया गया था। इसका संचालन क्षेत्र पुडुचेरी, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों को कवर करता है जिसका पंजीकरण नंबर एमएससीएस /सीआर /307/2009 है। यह संस्था निम्नलिखित विजन और मिशन के साथ काम करता है।

यह संस्था प्राथमिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। इसके मुख्य उद्देश्य सहकारी सिद्धांतों के अनुरुप, स्व-सहायता और पारस्परिक सहायता के माध्यम से अपने सभी सदस्यों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण में सुधार करके उनके हितों को बढ़ावा देना हैं।

2. सदस्यता:

दिनांक 31.03.2024 तक संस्था के कुल 460 सदस्य हैं जिनमें 117 व्यक्तिगत सदस्य और 343 समूह सदस्य शामिल हैं । दिनांक 31.03.2023 तक इसके 453 सदस्य (116 व्यक्तिगत सदस्य और 337 समूह सदस्य) थे जिनकी कुल चुकता शेयर पूंज़ी 13,02,600 रुपये थी।

3. जमा:

दिनांक 31 मार्च 2024 तक संस्था के पास कुल 1.79 करोड़ रुपये की जमा राशि है।

4. ऋण:

वर्ष के दौरान 29 सदस्य स्वयं सहायता समूह को छोटी आय सृजन गतिविधियों के लिए 100% पुनर्भुगतान के साथ कुल 1,00,50,000 रुपये का ऋण दिया गया। अपनी स्थापना के बाद से संस्था ने 528 स्वयं सहायता समूह को कुल 14.34 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया है जिससे 7,168 परिवार लाभान्वित हुए हैं।

5. फैमको की 14वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित की गई:

14वीं वार्षिक आम बैठक 12 अगस्त 2023 को पुडुचेरी-1 में आयोजित की गई जिसमें 71 सदस्य उपस्थित थे।

6. निदेशक मंडल की बैठकें:

वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक तिमाही में एक-एक बोर्ड की चार बैठकें आयोजित की गईं।

7. कर्नाटक के चित्रदुर्ग में 70वां सहकारी सप्ताह मनाया गया:

दिनांक 10 नवंबर, 2023 को फैमको और चित्रा डॉन बॉस्को, चित्रदुर्ग ने आगामी अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह मनाने के लिए स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए एक सामुदायिक बैठक की सह-मेजबानी की। स्टीवन लॉरेंस एसडीबी, निदेशक, चित्रा डॉन बॉस्को और फैमको, चित्रदुर्ग के उपाध्यक्ष ने कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इस बैठक में सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों से निपटने में सहकारी समितियों के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने, सहयोग के माध्यम से आय-उत्पादक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और महिलाओं के सामूहिक प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डालने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस कार्यक्रम में 25 स्वयं सहायता समूहों की 62 महिलाओं ने भाग लिया।

चित्रदुर्ग में 70वां राष्ट्रीय सहकारी सप्ताह

10.11.2023 को सहकारी सप्ताह के प्रतिभागी

1. रिपैट्रिएट्स कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड (रेपको बैंक)

उत्पत्ति:-

रिपैट्रिएट्स कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड (रेपको बैंक) को शुरू में 19 नवंबर 1969 को मद्रास कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 1961 के तहत एक सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत किया गया था। इसके बाद इसे मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 2002 के तहत फिर से पंजीकृत किया गया जिससे इसका अधिकार क्षेत्र तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी तक फैल गया।

1) उद्देश्य:-

इस बैंक का प्राथमिक उद्देश्य श्रीलंका, बर्मा, वियतनाम और अन्य देशों से आए लोगों के पुनर्वास में सहायता करना है। प्रत्यावर्तन पुनर्वास पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए बैंक ने अपने सदस्य ग्राहकों को सेवाओं की एक व्यापक श्रृंखला प्रदान करते हुए एक आत्मनिर्भर बैंक के रूप में विकसित होने के लिए अपनी भूमिका का विस्तार भी किया है।

2) बैंक की उपलब्धियाँ और प्रशंसाएँ

ए) बैंक ने अपना पहला लाभ वित्तीय वर्ष 1991-92 में हासिल किया और वित्तीय वर्ष 1992-93 से लगातार लाभांश का भुगतान किया है। 31.03.2024 तक, इसका कुल व्यापार पोर्टफोलियो 19,635.85 करोड़ रुपये का है जिसमें 10,582.48 करोड़ रुपये जमा और 9,053.37 करोड़ रुपये अग्रिम शामिल हैं। बैंक भारत के दक्षिणी राज्यों में 108 शाखाएं संचालित करता है और बैंकिंग उद्योग में एक मजबूत ब्रांड छवि और प्रतिष्ठा का निर्माण किया है।

बी) वित्तीय वर्ष 1992-93 से लगातार लाभांश वितरित करते हुए बैंक ने कई वर्षों तक अपने शेयरधारकों को 20% लाभांश प्रदान किया है। यह एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है कि बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में अर्जित लाभ से भाग लेने वाली सरकारों और पात्र शेयरधारकों को 38.06 करोड़ रुपये की राशि का 25% लाभांश वितरित करने का प्रस्ताव दिया है।

सी) रेप्को बैंक लगभग 1,518 परिवारों को आजीविका प्रदान करता है जिसमें 1,008 नियमित कर्मचारी और 510 अनुबंध आधार पर कर्मचारी शामिल हैं।

डी) रेप्को बैंक एक कुशल और प्रेरित कार्यबल बनाए रखता है जो बैंकिंग उद्योग की चुनौतियों का समाधान करने के लिए निरंतर प्रशिक्षण के महत्व पर जोर देता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बैंक ने 13 इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और राष्ट्रीय संस्थानों में 10 बाहरी कार्यक्रमों में कर्मचारियों को नामांकित किया।

इ) बैंक 1992 से कम्प्यूटरीकरण और डिजिटलीकरण में अग्रणी रहा है जो जमा, ऋण, एमआईएस और पेरोल के लिए इन-हाउस सॉफ्टवेयर विकसित करता है। यह दक्षिण भारत का पहला सहकारी बैंक था जिसने कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस (सीबीएस) सॉफ्टवेयर पेश किया। बैंक अपने स्वयं के डेटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी सेंटर भी संचालित करता है जो विभिन्न भूकंपीय क्षेत्रों में टियर-III डेटा सेंटर में स्थित हैं।

एफ) बैंक का निरीक्षण प्रभाग यह सुनिश्चित करता है कि व्यवसाय वृद्धि का समर्थन करते हुए नियंत्रण और अनुपालन मानकों को पूरा किया जाए। सतर्कता प्रकोष्ठ भारत सरकार, केंद्रीय सतर्कता आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य निकायों के निर्देशों का पालन करता है, तथा धोखाधड़ी और नुकसान को रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी करता है। धोखाधड़ी को रोकने के लिए केवाईसी मानदंडों का पालन करने पर जोर दिया जाता है।

जी) बैंक में अच्छी तरह से परिभाषित जांच और संतुलन तथा एक मानक आंतरिक प्रणाली और नियंत्रण है, ताकि किसी भी हानिकारक या अनैतिक व्यवहार और कार्यों से बचा जा सके।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बैंक की वित्तीय विशेषताएँ:

1. 31.03.2024 तक चुकता पूंजी ₹ 152.48 करोड़ थी।
2. मार्च 2024 के अंत तक निवल संपत्ति ₹ 846.34 करोड़ अधिक है।
3. जमा राशि ₹ 10,582.48 करोड़ थी जो 11.07 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज करती है।
4. अग्रिम राशि ₹ 9,053.37 करोड़ थी जो 10.15 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज करती है।
5. 31 मार्च 2024 तक व्यवसाय मिश्रण ₹ 19,635.85 करोड़ तक पहुँच गया जो 10.65 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज करता है।
6. 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कर के बाद लाभ ₹ 69.69 करोड़ रहा।
7. 31.03.2024 तक प्रति कर्मचारी व्यवसाय ₹ 19.48 करोड़ रहा।
8. बैंक पिछले 30 वर्षों से लगातार लाभ कमाने वाला संस्थान है और हर साल अपने हितधारकों को लगातार 20% का लाभांश घोषित करता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए घोषित लाभांश 25% है।

बैंक की उपलब्धियाँ -

पिछले कुछ वर्षों के दौरान बैंक द्वारा जीते गए एफसीबीए पुरस्कार

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, बैंक ने एफसीबीए सर्वश्रेष्ठ सहकारी बैंक पुरस्कार जीता।

1) प्रत्यावर्तित व्यक्तियों का पुनर्वास

इसमे प्रत्यावर्तित व्यक्तियों का पुनर्वास और कल्याण वह प्राथमिक उद्देश्य जिसके लिए बैंक की स्थापना की गई थी इसके मिशन का केंद्र बना हुआ है। अपने 54 साल के सफ़र के दौरान बैंक ने प्रत्यावर्तियों के उत्थान और कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया है। इस लक्ष्य का समर्थन करने के लिए लगातार उपायों को और बढ़ाया है। वर्ष 2007 में बैंक ने 'प्रत्यावर्तियों कल्याण ट्रस्ट' की स्थापना की जो प्रत्यावर्तित समुदाय के लिए कल्याणकारी पहलों को निधि देने के लिए हर साल बैंक के मुनाफे का एक हिस्सा प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त बैंक प्रत्यावर्तित उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, प्रत्यावर्तियों कल्याण ट्रस्ट ने विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 910.64 लाख रुपये आवंटित किए जिससे 45,061 प्रत्यावर्तियों को लाभ

2) रेप्को बैंक द्वारा प्रवर्तित संस्थाएँ रेप्को होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) - सहयोगी कंपनी:

बैंक ने वर्ष 2000 में 'रेप्को होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल)' की स्थापना की। आरएचएफएल अब भारत की अग्रणी आवास वित्त कंपनियों में से एक है जिसका व्यवसाय बकाया 13,037.08 करोड़ रुपये और शुद्ध लाभ 1.5 करोड़ रुपये है।

रेप्को माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड (आरएमएफएल) - सहायक कंपनी:

इस बैंक ने 2007 में 'रेप्को माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड (आरएमएफएल)' नामक एक माइक्रोफाइनेंस कंपनी भी स्थापित की जिसका प्राथमिक उद्देश्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को माइक्रोक्रेडिट प्रदान करना है। आरएमएफएल भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकार क्षेत्र के तहत एक लाइसेंस प्राप्त कंपनी है। दिनांक 31.03.2024 तक इसने 1,331 करोड़ रुपये का व्यवसाय बकाया, 68.31 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ और 115 शाखाओं का नेटवर्क संचालित किया है।

1. राज्य सहकारी संघ, केरल

केरल राज्य सहकारी संघ राज्य,सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बारह सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों, दस सहकारी प्रशिक्षण केंद्रों, छह जेडीसी विस्तार प्रशिक्षण केंद्रों और इक्कीस सदस्य शिक्षा इकाइयों के माध्यम से संचालित होता है। इसके अतिरिक्त यह प्रतिष्ठित केरल सहकारी प्रबंधन संस्थान (केआईसीएमए) और आरपीएम कला और विज्ञान महाविद्यालय का प्रबंधन करता है जो दोनों केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के नेयारदम में स्थित हैं।

दिनांक 05 जून, 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस के हिस्से के रूप में राज्य सहकारी संघ ने "हरितम सहकारणम" कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय उद्घाटन माननीय अध्यक्ष श्री कोलियाकोड एन. कृष्णन नायर ने तिरुवनंतपुरम सहकारी महाविद्यालय में किया जहाँ उन्होंने एक पेड़ लगाया। राज्य सहकारी संघ के निर्देशों के अनुसार सभी सर्किल सहकारी संघों, कॉलेजों/केंद्रों और केआईसीएमए में विश्व पर्यावरण दिवस की गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

केरल राज्य सहकारी संघ "केरल सहकारी जर्नल" नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित करता है। 17 जुलाई, 2023 को संघ ने श्री जोसेफ मुंडासेरी जो कि एक सम्मानित लेखक और राज्य के पहले सहकारिता मंत्री थे, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में जर्नल दिवस मनाया। श्री कोलियाकोडे कृष्णन नायर, अध्यक्ष द्वारा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई और भव्य कार्यक्रम के माध्यम से पत्रिका के प्रसार को बढ़ाने की योजना की घोषणा की।

इसके अतिरिक्त 1 जुलाई, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर माननीय श्री कोलियाकोडे कृष्णन नायर, अध्यक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष सहकारी टिकट जारी किया।

राष्ट्रीय सहकारी संघ की ओर से एसएयू ने 14 नवंबर से 20 नवंबर, 2023 तक 70वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह समारोह का आयोजन किया। 70वें सहकारी सप्ताह का राज्य स्तरीय उद्घाटन समारोह 14 नवंबर, 2023 को कन्नूर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत श्री सुभाष, आई.ए.एस. द्वारा सहकारी ध्वज फहराने के साथ हुई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केरल के माननीय मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन ने किया और इसकी अध्यक्षता सहकारिता मंत्री श्री वी.एन. वासवन ने की। राज्य सहकारी संघ अध्यक्ष श्री कोलियाकोड एन. कृष्णन नायर ने स्वागत भाषण दिया जबकि अतिरिक्त रजिस्ट्रार/सचिव श्रीमती ग्लैडी जॉन पुथुर ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इस समारोह में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सहकारी क्षेत्रों से कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भाग लिया। 70वें सहकारी सप्ताह का राज्य स्तरीय समापन समारोह 20 नवंबर, 2023 को कोल्लम में हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व वित्त मंत्री डॉ. टी.एम. थॉमस इसाक ने किया। राज्य सहकारी संघ अध्यक्ष श्री कोलियाकोड एन. कृष्णन नायर ने समारोह की अध्यक्षता की। श्री प्रकाश बाबू (पूर्व विधायक) ने मुख्य भाषण दिया जबकि राज्य सहकारी संघ प्रबंध समिति के सदस्य श्री के. राजगोपाल ने उपस्थित सभी लोगों का स्वागत किया और अतिरिक्त रजिस्ट्रार/सचिव श्रीमती ग्लैडी जॉन पुथुर ने धन्यवाद ज्ञापन किया। सहकारी सप्ताह के उद्घाटन और समापन समारोह में लगभग 4,000 सहकारी नेताओं ने भाग लिया।

दिनांक 21-22 जनवरी, 2024 को 9वां सहकारी सम्मेलन कनककुन्नू, तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत रजिस्ट्रार श्री टी.वी. सुभाष, आईएएस द्वारा सहकारी ध्वज फहराने के साथ हुई। इस समारोह का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन ने किया जबकि सहकारिता मंत्री श्री वी.एन. वासवन ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। राज्य सहकारी संघ अध्यक्ष ने स्वागत भाषण दिया। इस उद्घाटन समारोह में वित्त मंत्री श्री के.एन. बालगोपाल, पूर्व सहकारिता मंत्री श्री कडकम्पल्ली सुरेंद्रन विधायक, केरल बैंक अध्यक्ष श्री गोपीकोट्टामुरिक्कल, सहकारिता विभाग की सचिव श्रीमती मिनी एंटनी आईएएस और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार श्री टी.वी. सुभाष आईएएस ने भाषण दिए। इसके अलावा अतिरिक्त रजिस्ट्रार-सचिव श्रीमती ग्लैडी जॉन पुथुर ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। इस समारोह में विभिन्न सर्किल सहकारी संघों के मनोनीत सदस्यों ने भाग लिया। इस 9वें सहकारी सम्मेलन के दौरान सहकारी क्षेत्र से संबंधित कई सेमिनार आयोजित किए गए।

4. महाराष्ट्र शहरी सहकारी बैंक संघ लिमिटेड (एमयूसीबीएफ)

1. पृष्ठभूमि

महाराष्ट्र शहरी सहकारी बैंक महासंघ, महाराष्ट्र राज्य के सभी शहरी सहकारी बैंकों का मुख्य निकाय है और यह केंद्रीय सरकार, आरबीआई,

सीबीडीटी, नाबार्ड, एनएचबी, राज्य सरकार, सहकारिता आयुक्त, सोसायटी रजिस्ट्रार, आईबीए, नेफकब, एनसीयूआई और अन्य संबंधित सरकारी निकायों सहित उचित मंचों के समक्ष हमारे सदस्य बैंकों की शिकायतों को आवाज़ देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

2. संगठनात्मक संरचना और कार्य

महासंघ एकमात्र राज्य स्तरीय निकाय है जिसका आरबीआई की स्थायी सलाहकार समिति की बैठक, टीएएफसीयूबी की बैठक में प्रतिनिधित्व है और केंद्र सरकार द्वारा गठित यूसीबी के लिए सलाहकार समूह, मॉडल उपनियम समिति, राज्य कानून संशोधन समिति आदि में भी प्रतिनिधित्व है।

3. प्रशिक्षण कार्यक्रम

यह महासंघ,महाराष्ट्र राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान भी है और इसने अब तक आरबीआई, आईबीए, नाबार्ड, सीएबी और बैंकिंग क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों से निदेशकों, सीईओ, अधिकारियों, कर्मचारियों आदि के लिए विभिन्न बैंकिंग विषयों पर प्रशिक्षण/शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित संकायों को आमंत्रित करके विभिन्न इन-हाउस/आउटडोर प्रशिक्षण कार्यक्रम/सेमिनार/कार्यशालाएँ आयोजित की हैं। इस महासंघ ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जो कि इस प्रकार हैं:-

ए) दिनांक 29 अप्रैल, 2023 को साइबर सुरक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

1) इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य बैंकरों को साइबर हमले और डेटा चोरी से बचाना, साइबर खतरों को रोकने और उनका जवाब देने की क्षमता का निर्माण करना और नियामक नीति आदि के बारे में जागरूकता पैदा करना था। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र राज्य के 35 यूसीबी से लगभग 59 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

बी) दिनांक 26 मई, 2023 को केवाईसी और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया:

इस प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य सदस्य बैंकों को केवाईसी अपडेट, संदिग्ध लेनदेन की पहचान, लॉगिन संबंधी मुद्दों, फिननेट गेटवे तक पहुंच और उस पर रिपोर्ट अपलोड करने और सबसे महत्वपूर्ण आरबीआई और एफआईयू-आईएनडी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/निर्देशों के उल्लंघन से बैंकों को बचाने के बारे में शिक्षित करना था। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र राज्य के 23 यूसीबी से लगभग 66 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

सी) 29 जून, 2023 और 30 जून, 2023 को विशेष वसूली अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया:-

जैसा कि अवगत हैं कि वसूली प्रबंधन बैंकिंग क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण रीढ़ है। बैंकिंग व्यवसाय को बढ़ाने और बैंकों को सशक्त बनाने के लिए ऋण वसूली एक आवश्यक कारक है। इसलिए विशेष वसूली अधिकारियों को वसूली के वास्तविक कार्य/कार्यों से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करना अनिवार्य हो गया है। संघ ने महाराष्ट्र राज्य के यूसीबी के विशेष वसूली अधिकारियों के लिए 29 जून, 2023 और 30 जून, 2023 को फेडरेशन के कार्यालय में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र राज्य के 29 यूसीबी से लगभग 65 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

डी) दिनांक 01 जुलाई, 2023 को सारफाइसी अधिनियम, 2002 पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य वसूली से संबंधित कानूनों में नवीनतम परिवर्तनों के बारे में जागरूकता लाना था और उपरोक्त अधिनियम के तहत की जाने वाली कार्रवाइयों के लिए कौशल को बढ़ाना, बैंकों के बकाया की जल्द से जल्द वसूली के अंतिम उद्देश्य के साथ निडरता से कार्रवाई शुरू करने के लिए वसूली अधिकारियों को प्रेरित करना, व्यावहारिक सुझावों के साथ अधिकारियों और बैंक को लंबे समय तक सुरक्षित रखना, इसके लिए भले ही मुद्दे सुप्रीम कोर्ट तक क्यों ना जाए आदि। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र राज्य के 38 यूसीबी से लगभग 69 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

ई) दिनांक 28 जुलाई, 2023 को सामान्य बैंकिंग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया:

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य आवश्यक कार्यबल तैयार करना था जो आज के प्रतिस्पर्धी माहौल की एक सख्त जरूरत हैं और यूसीबी की दिशा और दशा बदलने में गेम चेंजर साबित होगा। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र राज्य के 22 यूसीबी से लगभग 67 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

एफ) दिनांक 24 अगस्त, 2023 और 25 अगस्त, 2023 को ऋण प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया:-

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य वित्तीय विवरण विश्लेषण और निर्णय लेने की प्रक्रिया, विभिन्न प्रकार के ऋण और विभिन्न ऋणों में शामिल ऋण जोखिम, कर्मचारियों को प्रेरित करना, अधिक जवाबदेही और सुसंगत प्रथाओं को सुनिश्चित करना, ग्राहक संबंधों में सुधार आदि के बारे में जागरूकता पैदा करना था। यह कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्य में शहरी सहकारी बैंकों के सीईओ, महाप्रबंधकों, मुख्य प्रबंधकों और ऋण विभाग के प्रमुखों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 24 अगस्त और 25 अगस्त, 2023 को महासंघ के कार्यालय में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र राज्य के 27 शहरी सहकारी बैंकों से लगभग 66 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

जी) 27 अक्टूबर, 2023 को एनपीए प्रबंधन पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम:

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे सदस्य बैंकों को आईआरएसी मानदंडों पर आरबीआई द्वारा जारी मौजूदा निर्देशों का पालन करने, ऋण मूल्यांकन प्रथाओं को मजबूत करने, खराब ऋणों का शीघ्र पता लगाने और एनपीए प्रबंधन के बारे में जागरूक करना था। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र राज्य के 34 यूसीबी से लगभग 64 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

ए) दिनांक 18 नवंबर, 2023 को निवेश और ट्रेजरी प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया:-

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य यूसीबी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो, ट्रेजरी बिलों की प्रकृति और अवधारणा, निवेश नीति - विषय-वस्तु, आरबीआई के दिशा-निर्देश आदि के बारे में विभिन्न तथ्यों के बारे में जानकारी देना था। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र राज्य के 38 यूसीबी से लगभग 52 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

बी) दिनांक 29 दिसंबर, 2023 को जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया:-

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य एक वित्तीय इकाई में स्वतंत्र और प्रभावी आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य के बारे में जागरूकता लाना था, जो बोर्ड और उसके वरिष्ठ प्रबंधन को इकाई के आंतरिक नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन और शासन ढांचे की गुणवत्ता और प्रभावशीलता के बारे में महत्वपूर्ण आश्वासन प्रदान करता है। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र राज्य के 32 यूसीबी से लगभग 60 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

सी) दिनांक 31 जनवरी, 2024 को जोखिम प्रबंधन और अनुपालन प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया:-

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों को विनियमित संस्थाओं में कार्यों के महत्व के बारे में संवेदनशील बनाना, अनुपालन नीति कैसे तैयार करें यह बताना, तथा इसकी सामग्री और उद्देश्य, अनुपालन जोखिम को कम करने के लिए निवारक उपाय शुरू करने के

लिए उन्हें प्रबुद्ध करना था। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र राज्य के 37 यूसीबी से लगभग 66 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

डी) दिनांक 23 फरवरी, 2024 को ग्राहक सेवा और नेतृत्व विकास कार्यक्रम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया:-
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य थे:

- बैंक मार्केटिंग में ज्ञान प्रदान करना और कौशल को बढ़ाना।
- नेतृत्व कौशल लोगों को विकसित करने और प्रबंधित करने के अभिनव तरीके खोजने, संगठन और टीम के सदस्यों को मूल्य निर्माण के लिए मार्गदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- संगठन की ताकत और कमजोरियों और सुधार के क्षेत्रों का आकलन करने के लिए स्वोट विश्लेषण।इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र राज्य के 22 यूसीबी से लगभग 60 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

2. संघ की अन्य गतिविधियाँ:

ए) बैठकें आयोजित करना :-

इस वर्ष के दौरान आरबीआई ने मुंबई और नागपुर क्षेत्रों से संबद्ध यूसीबी के लिए चार टफकैब बैठकें और बहु-राज्य अनुसूचित यूसीबी के लिए एक केंद्रीय बैठक आयोजित की।

बी) मुंबई के सथये कॉलेज के छात्रों के लिए कार्यशालाएँ आयोजित की :-

दिनांक 24 जनवरी, 2024 को मुंबई के सथये कॉलेज के छात्रों के लिए कार्यशाला का आयोजन शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के महत्व विषय पर किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य केंद्र सरकार की वित्तीय समावेशन योजना में यूसीबी की भूमिका के बारे में जागरूकता लाना था। इस कार्यशाला में मुंबई के सथये कॉलेज के 60 छात्रों और उनके शिक्षकों ने भाग लिया।

सी) आरबीआई के उप-गवर्नर के साथ स्थायी सलाहकार समिति (एसएसी) की बैठक आयोजित की।

डी) श्री समर्थ सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक के शेयरधारकों, निदेशक मंडल और कर्मचारियों के लिए 18 फरवरी, 2024 को प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बैंक के शेयरधारकों, निदेशक मंडल और कर्मचारियों सहित 132 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

ई) सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार समारोह:- दिनांक 30 सितंबर, 2023 को संघ द्वारा सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया जिसमें 25 यूसीबी को ऑडिट वर्ग, जमा और ऋण वृद्धि, सकल और शुद्ध एनपीए का प्रतिशत, जमा की लागत, कुल जमा में सीएएसए जमा का प्रतिशत, शुद्ध ब्याज मार्जिन आदि जैसे मानदंडों के आधार पर सम्मानित किया गया।

एफ) यूसीबी का विलय/एकीकरण/एकीकरण इत्यादि :- कुछ नकारात्मक नेटवर्थ वाले यूसीबी और रिज़र्व बैंक से अनुरोध पर फेडरेशन ऐसे बैंकों का राज्य और राज्य के बाहर वित्तीय रूप से मजबूत यूसीबी के साथ विलय की संभावना भी तलाश रहा है। पिछले कुछ वर्षों में फेडरेशन ने विभिन्न यूसीबी के सफल विलय को आगे बढ़ाने और उनके जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने की पहल की है।

1. कर्नाटक राज्य सहकारी शहरी बैंक संघ लिमिटेड, बैंगलोर

पृष्ठभूमि:-

कर्नाटक राज्य सहकारी शहरी बैंक संघ लिमिटेड, बैंगलोर, कर्नाटक राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1959 के तहत पंजीकृत एक शीर्ष-स्तरीय निकाय है। सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने और शहरी बैंकिंग क्षेत्र को प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इस संघ की स्थापना की गई थी।

कर्नाटक में 252 शहरी सहकारी बैंकों का प्रतिनिधित्व करते हुए संघ राज्य में शहरी सहकारी बैंकों के समग्र विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों को लागू करने और व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा गठित कई समितियों के सदस्य के रूप में, संघ कर्नाटक में शहरी सहकारी बैंकों के स्वस्थ विकास में सीधे योगदान देता है।

संगठन संरचना और कार्य:-

इस संघ का नेतृत्व अध्यक्ष करता है जिसे बोर्ड के उन्नीस सदस्यों द्वारा चुना जाता है। श्री एच.के. पाटिल और श्री बी.एस. परमशिवैया क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं। इस बोर्ड ने सदस्य बैंकों द्वारा दिए गए शिक्षा कोष के उपयोग की देखरेख करने तथा शहरी सहकारी बैंकों के निदेशकों एवं अधिकारियों को शिक्षित करने के लिए महासंघ द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को मंजूरी देने के लिए आठ सदस्यीय 'शिक्षा समिति' का गठन किया है। संघ के दैनिक कार्यों की देखरेख मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा की जाती है। महासंघ का प्राथमिक उद्देश्य राज्य में शहरी सहकारी बैंकिंग (यूसीबी) क्षेत्र की छवि को बढ़ाना तथा यह सुनिश्चित करना है कि सभी यूसीबी नियामक आवश्यकताओं का अक्षरशः अनुपालन करें। इस लक्ष्य का समर्थन करने के लिए महासंघ यूसीबी अधिकारियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

कार्यक्रम,गतिविधियां और योजनाएं:-

(i) समाचार-पत्रों (साप्ताहिक) तथा पत्रिकाओं (त्रैमासिक) के प्रकाशन के माध्यम से यूसीबी के निदेशकों एवं कर्मचारियों को क्षेत्र में हुए हालिया विकासों के बारे में बताना।

(ii) छोटे एवं आर्थिक रूप से कमजोर यूसीबी के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करना ताकि उन्हें उनकी वित्तीय कठिनाइयों पर काबू पाने की रणनीतियों के बारे में शिक्षित किया जा सके।

(iii) यूसीबी क्षेत्र के निदेशकों एवं कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए विभिन्न विषयों पर सेमिनार एवं कार्यशालाएं आयोजित करना।

(iv) मामलों के समाधान में तेजी लाने और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) को कम करने के लिए मध्यस्थता न्यायालयों के कामकाज को सुगम बनाना।

(v) बड़ी संख्या में शहरी सहकारी बैंकों में ई-स्टाम्पिंग सेवाओं को बढ़ावा देना।

(vi) शहरी सहकारी बैंकों के कर्मचारियों के लिए "शहरी सहकारी बैंकिंग प्रबंधन में डिप्लोमा" पाठ्यक्रम प्रदान करना।

(vii) बेंगलुरु और हुबली में वसूली अधिकारी कक्ष स्थापित करना।

(viii) सदस्य बैंकों को विभिन्न विनियामक और वैधानिक प्रावधानों के साथ-साथ बैंकिंग कानून और व्यवहार से संबंधित मुद्दों पर कानूनी सलाह देने के लिए एक सेल का गठन करना।

उपलब्धियां और सफलता की कहानियां

(i) सदस्य बैंकों को 350 से अधिक कानूनी सलाह जारी की गईं।

(ii) 218 ई-स्टाम्पिंग केंद्र चालू हैं जो ग्राहकों की सेवा कर रहे हैं।

(iii) 15 कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए गए।

(iv) डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के दसवें बैच में, 3,800 कर्मचारियों ने सफलतापूर्वक कार्यक्रम पूरा किया।

भविष्य की योजनाएं

संघ अपने सदस्यों को कुशलतापूर्वक सेवा प्रदान करने का प्रयास करेगा तथा महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए पहल करेगा। सभी शहरी सहकारी बैंकों ने राज्य सहकारी अधिनियम के अनुसार अपने बोर्ड में महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को प्रतिनिधित्व भी दिया है।

कार्यक्रम और गतिविधियों की फोटो

दिनांक 22 जून, 2023 श्री के.एन. राजन्ना, सहकारिता मंत्री, कर्नाटक सरकार ने महासंघ का दौरा किया।

दिनांक 26 अगस्त, 2023 को विजयपुर में शहरी सहकारी बैंकों की महिला निदेशक एवं महिला सीईओ के लिए एक दिवसीय राज्य स्तरीय सेमिनार

फेडरेशन की 58वीं वार्षिक आम सभा की बैठक,
स्थान: के.एच.पाटिल ऑडिटोरियम बैंगलोर दिनांक: 20/09/2023.

23 फरवरी, 2024 को शहरी सहकारी बैंकों के निदेशक मंडल और
सीईओ के लिए हसन में एक दिवसीय सेमिनार।

दिनांक: 20.06.2024 को शहरी सहकारी बैंकों के निदेशक मंडल और व्यावसायिक निदेशकों,
बी.ओ.एम. सदस्यों के लिए बैंगलोर में एक दिवसीय राज्य स्तरीय सेमिनार।

कर्नाटक दुग्ध संघ

कर्नाटक सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड (केएमएफ), कर्नाटक राज्य में डेयरी सहकारी आंदोलन के लिए सर्वोच्च निकाय है। यह देश में डेयरी सहकारी समितियों में दूसरी सबसे बड़ी डेयरी सहकारी है। दक्षिण भारत में यह खरीद के साथ-साथ बिक्री के मामले में पहले स्थान पर है। संघ के मुख्य कार्यों में से एक दूध और दूध उत्पादों का विपणन है। ब्रांड "नंदिनी" शुद्ध और ताजा दूध और दूध उत्पादों के लिए घर-घर में जाना जाता है। केएमएफ के पास राज्य के सभी जिलों को कवर करने वाले 15 दूध संघ हैं जो प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों (डीसीएस) से दूध खरीदते हैं और कर्नाटक के विभिन्न कस्बों/शहरों/ग्रामीण बाजारों में उपभोक्ताओं को दूध वितरित करते हैं।

केएमएफ की इकाइयाँ:-

केंद्रीकृत तकनीकी इनपुट सुविधाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित केएमएफ इकाइयाँ संचालित हैं।

1. मदर डेयरी, येलहंका, बेंगलुरु
2. नंदिनी हाई-टेक उत्पाद संयंत्र: चन्नारायपट्टन
3. नंदिनी मेगा हाई-टेक पाउडर प्लांट, रामनगर
4. नंदिनी दूध उत्पाद, केएमएफ इकाई, बेंगलुरु
5. कैटल फीड प्लांट राजनुकुंटे, गुब्बी, धारवाड़, हसन, शिकारीपुरा, अरकलगुड, केआर पीट और सदाली
6. नंदिनी स्पर्म स्टेशन, हेसरघट्टा
7. नंदिनी पैकेजिंग फिल्म प्लांट, मुन्नेकोलालु

केएमएफ को वर्तमान में उपभोक्ताओं की मांगों को पूरा करने के लिए दूध के विभिन्न प्रकारों को पैक करने के लिए 950 से 1000 मीट्रिक टन पैकेजिंग फिल्म की आवश्यकता है।

प्रशिक्षण संस्थान:

बैंगलोर में केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान और मैसूर, धारवाड़ और गुलबर्गा में प्रशिक्षण केंद्र डीसीएस स्टाफ, अकाउंट्स, प्रशासन, डीसीएस बोर्ड के सदस्य और अध्यक्षों, तकनीकी इनपुट और अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मानव संसाधन विकास और अन्य विशेष क्षेत्रों के तहत आयोजित प्रशिक्षण से संबंधित विभिन्न विषयों में आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विस्तृत श्रृंखला प्रदान कर रहे हैं। डब्ल्यूडीसीएस के सदस्य और केएमएफ, यूनियनों और इकाइयों के अधिकारी/कर्मचारी भी इसमे शामिल हैं।

भौतिक उपलब्धियाँ:-

माह मार्च 2024 तक 15 दूध संघों में 17766 डेयरी सहकारी समितियों (डीसीएस) का एक नेटवर्क संगठित किया गया है। उनमें से 15779 डीसीएस कार्य कर रहे हैं जिनमें से 96 प्रतिशत लाभ में हैं और इसमे लगभग 4135 महिला डीसीएस कार्य कर रही हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर दूध खरीद में दूसरे स्थान पर और दक्षिण भारत में पहले स्थान पर है। कुल 99 लाख लीटर की प्रसंस्करण क्षमता वाली 28 डेयरियाँ हैं। प्रतिदिन 27.65 लाख लीटर की क्षमता वाले 33 दूध शीतलन केंद्र, 2201 बल्क मिल्क कूलर और 288 मीट्रिक टन प्रतिदिन सुखाने की क्षमता वाले 6 दूध पाउडर संयंत्र कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के तहत हैं। फ्लूइड मिल्क, दही, गुड लाइफ मिल्क, फ्लेक्सी मिल्क, क्षीर भाग्य और बल्क मिल्क सेल्स के रूप में प्रतिदिन औसतन 65.72 लाख किलोग्राम दूध बेचा जाता है। जिसमें से औसतन 21.85 लाख लीटर की बिक्री बेंगलुरु शहर में होती है।

मार्केटिंग:

केएमएफ राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे स्थान पर है और दक्षिण भारत में अग्रणी है। आज कर्नाटक के दूध उत्पादकों को सहकारी समितियों को आपूर्ति किए गए दूध के लिए सबसे अच्छी दूध कीमत मिलती है और उपभोक्ताओं को बहुत प्रतिस्पर्धी कीमतों पर दूध मिलता है।
कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (केएमएफ) ने स्वायत्त आर्थिक और सामाजिक संस्थाओं के रूप में डेयरी सहकारी समितियों के समग्र विकास के लिए एक सहायक और अनुकूल वातावरण बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। इसने कर्नाटक में एक आत्मनिर्भर और जीवंत ग्रामीण अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कर्नाटक राज्य सरकार भी दूध मूल्य प्रोत्साहन और डेयरी बुनियादी ढांचे और अन्य कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता के माध्यम से सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

वित्त वर्ष 2023-24 की प्रगति पर प्रकाश:-

- कर्नाटक मिल्क फेडरेशन में नंदिनी ब्रांड के तहत 175 प्रकार के दूध उत्पाद बेचे जा रहे हैं।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 में नंदिनी ने सभी जिला दुग्ध संघों और मदर डेयरी इकाई के माध्यम से खुदरा दूध (पाउच) की बिक्री में औसतन 41.79 लाख लीटर दूध प्रतिदिन बेचा है जो पिछले वर्ष की तुलना में 7 प्रतिशत अधिक है।
- दही की बिक्री में 33 प्रतिशत की प्रगति के साथ दैनिक औसत 9.57 लाख किलोग्राम दही बेचा गया।
- इसके अलावा नंदिनी खुदरा दूध और दही की बिक्री को मुंबई, पुणे, हैदराबाद, गोवा, चेन्नई, सोलापुर, विदर्भ बाजार क्षेत्रों जैसे राज्य के बाहर के शहरों में सदस्य दूध संघों के माध्यम से अलग से विस्तारित किया गया है और दही सहित कुल दूध औसतन 4.39 लाख लीटर प्रतिदिन बेचा जा रहा है जिसमे 17 प्रतिशत की प्रगति हासिल की गई है।
- सभी आयु वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस वित्तीय वर्ष में विभिन्न नए उत्पाद लॉन्च किए गए जैसे कि चॉकलेट-कुकीज, उल्लास गुल्ला, घी मोतीचूर लड्डू, घी सोन पापड़ी, खोआ मूंगफली चिक्की, बटर चिपलेट्स, चीज़ स्क्वीज़, चीज़ डिप, रसकदम, मूंगफली बर्फी, पनीर निप्पट्टू, भैंस का दूध, दही लाइट और खुदरा पैक में सेवरीज इत्यादि।
- पड़ोसी देशों को लंबे समय तक चलने वाले उत्पादों के निर्यात और बिक्री के लिए व्यापारी निर्यातकों की नियुक्ति।
- माउंटेन ट्रेल पुड्स चाय पॉइंट्स को यूएचटी दूध की बिक्री शुरू की।
- नंदिनी आइसक्रीम की बिक्री 2023-24 की तुलना में 23 प्रतिशत बढ़ी।
- जीओके के सहयोग से क्षीर भाग्य योजना शुरू की गई जिसके तहत वर्ष 2013 में आंगनवाड़ी से 10वीं कक्षा तक सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में दूध की आपूर्ति की जा रही है और यह मॉडल सफलतापूर्वक दस साल पूरे कर चुका है और अभी भी प्रभावी ढंग से चल रहा है।

- यह गर्व की बात है कि 'नंदिनी' ब्रांड लंदन स्थित मार्केट रिसर्च ग्रुप कांतार वर्ल्ड पैनल द्वारा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) ब्रांड रैंकिंग में 2022 में 7वें स्थान से बढ़कर 2023 में 6वें स्थान पर पहुंच गया है।
- प्रगति पाकशाला, दशहरा स्वीट पका के हिस्से के रूप में ग्राहक आधार का निर्माण और वफादार ग्राहकों को बनाए रखना, इस प्रकार कई खाना पकाने के आयोजनों में नंदिनी उत्पादों को प्रदर्शित और उपहार में देकर प्रायोजन किया जाता है।
- प्रो कबड्डी-2023, टी-20 विश्व कप-2024 में क्रमशः बेंगलुरु बुल्स टीम और आयरलैंड और स्कॉटलैंड टीमों की जर्सी ब्रांडिंग करवाकर नंदिनी लोगो को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए गए हैं।

"क्षीर भाग्य"

दिनांक 1 अगस्त 2013 को राज्य सरकार ने केएमएफ के साथ मिलकर क्षीर भाग्य योजना शुरु की थी, जिसका उद्देश्य प्रोटीन और वसा युक्त पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है, जो राज्य में स्कूली बच्चों और आंगनवाड़ी के स्वस्थ विकास और सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है।

केएमएफ डिपो चालू करना:-

दूध और दूध उत्पादों की बढ़ती मांग और बिक्री को पूरा करने के लिए क्षेत्रवार डिपो चालू किए गए हैं।

वित्तीय प्रगति:-

फेडरेशन ने खरीद और बिक्री मूल्य के बीच कम मूल्य अंतर बनाए रखा है जिसके परिणामस्वरुप अधिक प्राप्ति हुई है। **वर्तमान में दूध उत्पादकों को प्रतिदिन औसतन 28.82 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा रहा है।**

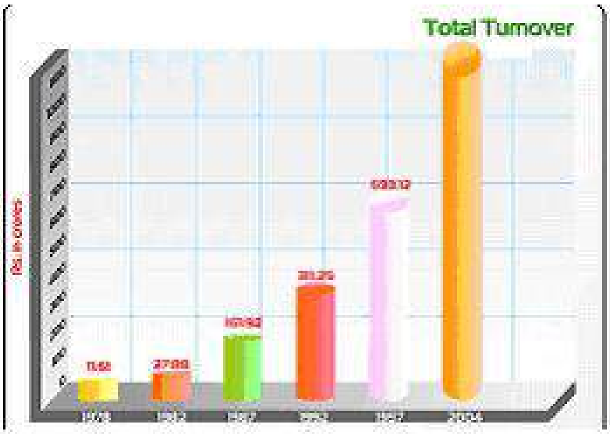

इस राज्य में डेयरी विकास गतिविधियों के लिए फेडरेशन द्वारा दिए गए समग्र इनपुट के परिणामस्वरुप दूध की अधिक खरीद हुई है जिसे बिना किसी दूध अवकाश की घोषणा के संभाला जाता है।

राज्य में पर्याप्त प्रसंस्करण सुविधाओं के साथ-साथ नई विपणन रणनीतियों के परिणामस्वरुप अधिक कारोबार हुआ है। **वर्ष 2022-23 में 20614 करोड़ की तुलना में 2023-24 में 21328 करोड़ की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।**

स्टेप परियोजना / क्षीर संजीवनी कार्यक्रम

(प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम योजना (महिला संजीवनी)

महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम योजना (स्टेप) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 में पारंपरिक रुप से अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं की भलाई सुनिश्चित करने के लिए शुरु की गई। यह महिलाओं के कौशल उन्नयन और स्थायी रोजगार के लिए प्रशिक्षण देने के उद्देश्य की वकालत करता है जो विभिन्न प्रकार की कार्योन्मुखी परियोजनाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार प्रदान करता है।

केएमएफ एवं स्टेप परियोजना:

कर्नाटक दुग्ध संघ (केएमएफ) ने अक्टूबर 1997 से कर्नाटक में "स्टेप" कार्यक्रम की शुरुआत की। तब से केएमएफ ने तीन चरणों में 800 महिला डेयरी सहकारी समितियों (डब्लूडीसीएस) का आयोजन किया है और चरण IV में स्टेप के आगमन से पहले आयोजित 250 डब्लूडीसीएस को स्टेप डब्लूडीसीएस में परिवर्तित किया है।

क्षीर संजीवनी चरण II

कर्नाटक राज्य ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति (केएसआरएलपीएस) और कर्नाटक दुग्ध महासंघ (केएमएफ) ने वर्ष 2020-21 के दौरान "क्षीरा संजीवनी चरण-II" परियोजना शुरु की। ।

इस परियोजना में कुल 6920 लाभार्थियों को कवर करने वाली 173 महिला डेयरी सहकारी समितियों को पशुओं की खरीद के लिए मार्जिन मनी प्राप्त हुई है और उन्हें प्रशिक्षण, डब्लूडीसीएस को बुनियादी ढांचा सहायता और गांव स्तर पर जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और साथ ही कुल 5846 पशुओं को नियमित और रोटेशन के आधार पर खरीदा गया है।

क्षीरा संजीवनी चरण-III

कर्नाटक राज्य ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति (केएसआरएलपीएस) और कर्नाटक दुग्ध महासंघ (केएमएफ) ने वर्ष 2021-22 के दौरान "क्षीरा संजीवनी चरण-III" परियोजना शुरु की। इस परियोजना में 150 महिला डेयरी सहकारी समितियों को शामिल किया गया है जिसमें कुल 6000 लाभार्थी हैं जिन्हें पशुओं की खरीद के लिए मार्जिन मनी दी गई है और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसके तहत डब्लूडीसीएस को बुनियादी ढांचा सहायता और गांव स्तर पर जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और नियमित और रोटेशन के आधार पर कुल 3179 पशु खरीदे गए हैं।

क्षीरा संजीवनी चरण-IV:

कर्नाटक राज्य ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसायटी (के.एस.आर.एल.पी.एस) और कर्नाटक दुग्ध महासंघ (केएमएफ) ने "क्षीरा संजीवनी चरण-IV" परियोजना शुरु की। यह परियोजना क्षेत्र कर्नाटक राज्य के 31 जिलों को कवर करता है जो 15 जिला दुग्ध संघों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं जो 250 महिला सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियों के अंतर्गत आते हैं। इसका लक्ष्य 10,000 महिला समूह सदस्यों को कवर करना है। परियोजना का कुल बजट परिव्यय 2061.10 लाख रुपये (केएसआरएलपीएस 59.61% और केएमएफ 40.4% अनुदान) है।

सरकारी सहायता प्राप्त कार्यक्रम:-

राज्य सरकार के कार्यक्रम:

क्षीरधर योजना:-

1) डेयरी किसानों को प्रोत्साहन:- सरकार ने वर्ष 2008-09 के दौरान इस योजना की घोषणा की थी जिसका उद्देश्य ग्रामीण किसानों को 2 रुपये प्रति लीटर प्रोत्साहन देकर डेयरी व्यवसाय अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना था। सरकार ने 14.5.2013 से दूध समितियों को गुणवत्तापूर्ण दूध की आपूर्ति के लिए दूध प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 4 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। इस योजना से लगभग 8.30 लाख दूध उत्पादक लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना के परिणामस्वरुप दूध खरीद में भारी वृद्धि हुई है क्योंकि 4 रुपये प्रति लीटर प्रोत्साहन के कार्यान्वियन के परिणामस्वरुप केएमएफ ने दूध खरीद में 14% की वृद्धि देखी है।

प्रदर्शन की मुख्य बातें:-

कर्नाटक मिल्क फेडरेशन का मिशन कर्नाटक राज्य में जोरदार सहकारी डेयरी विकास के माध्यम से हमारे सदस्य दूध उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इन लक्ष्यों की सफल प्राप्ति हाल के वर्षों में कई ऐतिहासिक उपलब्धियों में परिलक्षित होती है, जिनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं:-

- पूर्ण कवरेज: राज्य पूरी तरह से सहकारी डेयरी विकास द्वारा कवर किया गया है।
- किसानों द्वारा कवर किया गया: सभी जिला दुग्ध संघों और फेडरेशन में निर्वाचित बोर्ड मौजूद हैं।
- देश में सबसे कम मूल्य प्रसार: खरीद मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच सबसे कम मूल्य प्रसार।
- सहकारी उत्कृष्टता: अधिकांश डेयरी सहकारी समितियाँ (डीसीएस) लाभ कमा रही हैं।
- क्रॉस-ब्रीडिंग में अग्रणी: क्रॉस-ब्रीडिंग कार्यक्रमों के व्यापक कवरेज ने राज्य को देश में क्रॉस-ब्रीडिंग में अग्रणी राज्यों में से एक बना दिया है।
- ग्रामीण समृद्धि के लिए उत्पादकों को सशक्त बनाना: राज्य में सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रमों के लाभार्थियों का भारी बहुमत गांवों में कमजोर वर्ग से संबंधित हैं।
- उत्पादकों को लाभकारी मूल्य: उत्पादकों को दिए जाने वाले क्रय मूल्य में हाल के वर्षों में भारी वृद्धि हुई है जिससे राज्य में किसानों के लिए डेयरी व्यवसाय लाभकारी हो गया है।
- राज्य सरकार ने राज्य में डेयरी सहकारी समितियों को किसानों द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले प्रत्येक लीटर दूध के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन को 2 रुपये से बढ़ाकर 4 रुपये कर दिया है।

इसके अतिरिक्त हमारे सदस्य दूध उत्पादकों में से अधिकांश छोटे किसान, सीमांत किसान और भूमिहीन मजदूर हैं जिन्हें संकट के समय में सहायता की आवश्यकता होती है। केएमएफ सरकार के कई वित्तीय सहायता कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रहा है। कर्नाटक दुग्ध महासंघ राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी केंद्र सरकार की योजनाओं को भी सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर रहा है। अन्य में प्रशिक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना जैसे कि केएमएफ यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत प्रयास कर रहा है कि डीसीएस लाभदायक व्यावसायिक इकाइयों के रूप में काम करें और उत्पादक सदस्य अपने डीसीएस के प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभाएं।

1. गुजरात राज्य सहकारी संघ (जीएससीयू)

गुजरात राज्य सहकारी संघ (जीएससीयू) एक महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी संगठन है जो गुजरात भर में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा और समर्थन देता है। यह राज्य के भीतर विभिन्न सहकारी समितियों को सहकारी प्रशिक्षण, शिक्षा और संसाधन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा गुजरात राज्य सहकारी संघ अपने जिला सहकारी संघ और सहकारी प्रबंधन केंद्रों (सहकारी व्यवस्थापन केंद्र) के माध्यम से प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों से लेकर राज्य स्तरीय सहकारी संस्थानों के लिए विभिन्न सहकारी संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और विभिन्न अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

युवा सहकारी संगोष्ठी - 02.12.2023

गुजरात राज्य सहकारी संघ ने 02 दिसंबर 2023 को अहमदाबाद में "5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में युवा शक्ति और सहकारी संस्थाओं की भूमिका" विषय पर राज्य स्तरीय युवा सहकारी संगोष्ठी का आयोजन किया। गुजरात, सहकारिता मंत्री श्री जगदीश विश्वकर्मा ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया जिसमें प्रमुख सहकारी पदाधिकारियों सहित कई लोगों ने भाग लिया। इस संगोष्ठी की अध्यक्षता जीएससीयू, अहमदाबाद अध्यक्ष श्री जी.एच. अमीन ने की।

इस अवसर पर गुजरात विद्यापीठ के कुलपति एवं समारोह के मुख्य अतिथि डॉ. भरत जोशी द्वारा "युवा उत्कर्ष" पुस्तिका का विमोचन किया गया।

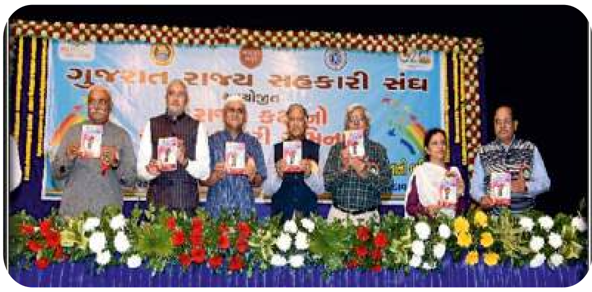

इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार एवं एसवीजी विश्वविद्यालय, गुजरात के पत्रकारिता विभाग के निदेशक तथा समारोह के मुख्य अतिथि डॉ. हरि देसाई ने कहा कि गुजरात के विकास का श्रेय सहकारी क्षेत्र को जाता है।,

युवा सहकारी संगोष्ठी में गुजरात राज्य के विभिन्न कॉलेजों से लगभग 800 युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया।

राज्य स्तरीय सहकारी महिला संगोष्ठी - 04.03.2024

गुजरात राज्य सहकारी संघ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर 04 मार्च 2024 को अहमदाबाद में "सहकारी क्षेत्र में महिलाओं के समावेश को प्रेरित करें" विषय पर राज्य स्तरीय महिला संगोष्ठी का आयोजन किया।

गुजरात राज्य सहकारी संघ अध्यक्ष श्री घनश्यामभाई अमीन की अध्यक्षता में आयोजित इस संगोष्ठी का उद्देश्य आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सहकारी गतिविधियों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करना था। गुजरात की विभिन्न महिला सहकारी समितियों से लगभग 1100 महिला प्रतिनिधियों ने राज्य स्तरीय सहकारी महिला संगोष्ठी में भाग लिया।

युवा महिला सहकारी संगोष्ठी - 21.03.2024

गुजरात राज्य सहकारी संघ, अहमदाबाद ने 21 मार्च 2024 को गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद में "नई अभिनव सहकारी समितियों का गठन" विषय पर युवा महिला सहकारी संगोष्ठी का आयोजन किया।

इस संगोष्ठी का उद्घाटन गुजरात विद्यापीठ के प्रबंधन प्रौद्योगिकी विभाग के संकाय के डीन श्री अजयभाई पारेख ने किया।

कार्यक्रम के समापन सत्र में गुजरात राज्य सहकारी संघ के अध्यक्ष घनश्यामभाई अमीन ने भाग लिया जिन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र में जाति या पंथ का कोई भेद नहीं है।

70वां अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह समारोह - 14 नवंबर 2023

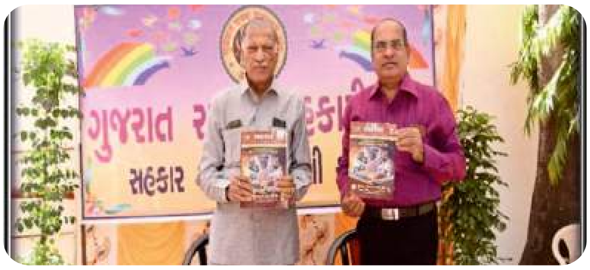

गुजरात राज्य सहकारी संघ (जीएससीयू) अध्यक्ष एवं भारतीय सहकारी बैंक (सीओबीआई), नई दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष श्री जी. एच. अमीन ने 14/11/2023 को सहकारी ध्वज फहराकर 70वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह समारोह का उद्घाटन किया।

श्री जी एच अमीन ने 70वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह समारोह के दौरान "सहकार सप्ताह विशेषांक-2023" पुस्तिका का विमोचन किया।

- **केन्द्र प्रायोजित योजना - पैक्स कम्प्यूटरीकरण परियोजना - "पैक्स अधिकारियों के लिए बुनियादी अभिविन्यास प्रशिक्षण**

- "गुजरात राज्य सहकारी संघ, अहमदाबाद के तत्वावधान में नाबार्ड के सहयोग से केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना पैक्स कम्प्यूटरीकरण के अंतर्गत गुजरात राज्य के विभिन्न जिलों जैसे अहमदाबाद, बनासकांठा, मेहसाणा, खेड़ा, अमरेली, वडोदरा, भरूच, सूरत, वलसाड, भावनगर और राजकोट में कम्प्यूटरीकरण प्रशिक्षण कक्षाएं आयोजित की गईं। इस परियोजना के अंतर्गत विभिन्न पैक्स के लगभग 3895 सचिवों को कम्प्यूटरीकरण के लिए प्रशिक्षित किया गया।

- इस समारोह का उद्घाटन करते हुए गुजरात राज्य सहकारी संघ, अहमदाबाद के अध्यक्ष श्री घनश्यामभाई एच अमीन ने पैक्स के कम्प्यूटरीकरण और डिजिटलीकरण के महत्व को समझाते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी ने "सहकारिता के माध्यम से समृद्धि" के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सहकारी संस्थाओं के विकास के लिए एक खाका तैयार किया है।
- इस उद्घाटन समारोह में नाबार्ड के सहायक महाप्रबंधक श्री राजेशभाई ध्रुव, अहमदाबाद ग्रामीण की जिला रजिस्ट्रार सुश्री उर्वशीबेन ब्रह्मभट्ट, अहमदाबाद जिले की विभिन्न पैक्स के सचिव और पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

गुजरात सरकार के सहकारिता विभाग के नवनियुक्त अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

गुजरात राज्य सहकारी संघ के प्रधान कार्यालय, अहमदाबाद में दिनांक 01.06.2023 को गुजरात सरकार के सहकारिता विभाग के नवनियुक्त अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य संघ और गुजरात सरकार के सहकारिता विभाग, गुजरात राज्य के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया।

अहमदाबाद के शहरी सहकारी बैंकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम (एलडीपी) एनसीयूआई और जीएससीयू द्वारा संयुक्त रूप से आयोजन

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई), नई दिल्ली और गुजरात राज्य सहकारी संघ, अहमदाबाद ने संयुक्त रूप से गुजरात सहकारी प्रशिक्षण केंद्र में 24.04.2023 से 26.04.2023 की अवधि के दौरान अहमदाबाद शहर के शहरी सहकारी बैंकों के बैंकरों के लिए "बैंकिंग के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम (एलडीपी)" का आयोजन किया।

गुजरात राज्य सहकारी संघ अहमदाबाद, गुजरात
शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी: वर्ष : 2023-24

क्रमांक	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का नाम	आयोजित कार्यक्रम	
		कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या
1	सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक	1,083	53,877
2	पुरुषसहकारी शिक्षा प्रशिक्षक	1,002	54,532
3	महिलासहकारी प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र	278	8666
	कुल	2,363	1,17,075

8.गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड (जीएसएआरडीबी))

परिचय:-

खेती बैंक गुजरात में सहकारी क्षेत्र में एक प्रमुख संस्था है जो कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए निवेश वित्त प्रदान करता है। यह बैंक एकात्मक संरचना के तहत कार्य करता है और 177 शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से अपने व्यवसाय का प्रबंधन करता है। इसके 17 जिला कार्यालय हैं। इसका पंजीकृत कार्यालय अहमदाबाद में स्थित है। बैंक की एकात्मक संरचना में राज्य स्तर पर एक प्रधान कार्यालय और प्रत्येक तालुका स्तर पर शाखाएँ शामिल हैं जिसमें प्रधान कार्यालय सत्रह जिला कार्यालयों के माध्यम से समन्वय करता है।

वर्ष 2023-24 के दौरान गतिविधियाँ और कार्यक्रम:

ए) सदस्यता और शेयर पूंजी:-

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सदस्यों की कुल संख्या बढ़कर 292,759 हो गई हैं। 31 मार्च, 2021 तक शेयर पूंजी ₹47,07,29,095 थी। ऋण खातों के बंद होने पर शेयर पूंजी की वापसी और नए सदस्यों (उधारकर्ताओं) के नामांकन के कारण वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, 31 मार्च, 2024 तक शेयर पूंजी ₹52,91,40,830 थी।

बी) फंड (सांविधिक आरक्षित निधि और अन्य निधि):-

पिछले वर्ष सांविधिक और अन्य आरक्षित निधि का शेष ₹612.75 करोड़ था। 31 मार्च, 2024 तक यह शेष बढ़कर ₹649.48 करोड़ हो गया है।

सी) सावधि जमा:-

बैंक ने 1991-92 वित्तीय वर्ष में अपनी सावधि जमा योजना शुरु की। 31 मार्च, 2023 तक सावधि जमा का बकाया शेष ₹232.86 करोड़ था। 31 मार्च, 2024 तक यह शेष घटकर ₹224.55 करोड़ हो गया। बैंक अपने कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों को सावधि जमा पर 0.50% की अतिरिक्त ब्याज दर प्रदान करता है।

डी) अग्रिम:-

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक द्वारा वितरित कुल ऋण 374.91 करोड़ रुपये था।

ई) सीबीएस - "कोर बैंकिंग समाधान":-

बैंक के निदेशक मंडल द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन के अनुसार आधुनिक तकनीक के माध्यम से लेखांकन के लिए बैंक के संचालन को आधुनिक बनाने के लिए कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) परियोजना शुरु की गई थी। इस परियोजना में सभी 177 शाखाएँ, 17 जिला कार्यालय और प्रधान कार्यालय शामिल थे। यह परियोजना पूरी हो चुकी है और 31 मार्च, 2024 तक बैंक के सभी समापन संचालन सीबीएस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किए गए थे।

एफ) निवेश:-

नाबार्ड, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को पुनर्भुगतान किसान सदस्यों को उनके ऋण की किस्तों का भुगतान करने के लिए ऋण प्रदान करने की व्यवस्था का हिस्सा है। वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों में निवेश किया। 31 मार्च, 2024 तक कुल किस्तों की राशि ₹292.06 करोड़ थी। बैंक ने इन किस्तों के प्रबंधन और समीक्षा के लिए एक किस्त समिति की स्थापना की है। वर्ष के दौरान इन किस्तों पर ₹26.74 करोड़ की ब्याज आय अर्जित की गई।

जी) ओटीएस-निपटान योजना:-

एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना के तहत जो 17 अक्टूबर, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी थी, 31 मार्च, 2024 के अंत तक 3,032 लाभार्थियों से कुल ₹59.35 करोड़ एकत्र किए गए। बैंक ने निपटान योजना के तहत किसानों को 38.20% का औसत लाभ प्रदान करते हुए कुल ₹36.69 करोड़ की राशि माफ की।

एच) नेट एनपीए:-

2023-24 के दौरान बैंक ने ज़ीरो प्रतिशत का नेट एनपीए हासिल किया। खेती बैंक ने ज़ीरो प्रतिशत नेट एनपीए बनाए रखने वाला देश का पहला कृषि बैंक बनकर इतिहास रच दिया है।

आई) बैंक के सदस्यों के लिए दुर्घटना लाभ:-

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान दुर्घटनाओं में मरने वाले छह उधारकर्ताओं के परिवारों को कुल ₹12,00,000 प्रदान किए गए।

जे) बैंक की ऑडिट रेटिंग:-

बैंक की वित्तीय स्थिति पिछली ऑडिट सिफारिशों के अनुपालन, समग्र प्रदर्शन, सहकारिता विभाग के स्थायी निर्देशों का पालन और नाबार्ड के मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए बैंक को "ए" श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया था। यह वर्गीकरण बैंक के समग्र प्रदर्शन और किसानों के हितों की सेवा करने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

के) टैबलेट बैंकिंग:-

बैंक ने डिजिटल संचालन को बढ़ाने के लिए टैबलेट बैंकिंग के माध्यम से डोरस्टेप सेवा शुरु करने का फैसला किया है जिससे सदस्य और जमाकर्ता अपने घरों में आराम से बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर सकें। यह सेवा इसी वित्तीय वर्ष से लागू की जाएगी।

एल) ग्राहक सेवा केंद्र:-

बैंक के साथ ग्राहक संपर्क को बेहतर बनाने के लिए चालू वित्तीय वर्ष से एक कॉल सेंटर (ग्राहक सहायता केंद्र) चालू है।

एम) कर्मचारियों के लिए प्रेरणा संगोष्ठी:-

कर्मचारियों को संगठन में सार्थक योगदान देने, लक्ष्यों को पूरा करने और सक्रिय रुप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रेरणा संगोष्ठी आयोजित की गई।

एन) 31 मार्च 2024 को अनंतिम वित्तीय डेटा घोषित किया गया:-

जीएससीएआरडी बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 31 मार्च, 2024 तक 91 करोड़ रुपए का लेखापरीक्षित अनंतिम सकल लाभ घोषित किया। 31 मार्च, 2024 को आयोजित बोर्ड की बैठक में इन लेखापरीक्षित आंकड़ों की समीक्षा की गई और उन्हें साझा किया गया।.

क्रमांक	विवरण	2022-23	2023-24
1	शेयर पूंजी	47.42	52.98
2	स्वयं का फंड	618.60	649.57
3	अग्रिम	644.16	837.89
5	कुल आयु	178.65	179.31
6	कुल लाभ	106.00	91.00
7	शुद्ध लाभ	51.19	65.00
8	शुद्ध एनपीए	0 %	0%
9	ऑडिट क्लास	“A”	-
10	लाभ अर्जित करने वाली शाखाएँ	**176**	**176**
11	घाटे में चल रही शाखाएँ	**0**	**0**

(नोट:राशि करोड़ रुपए में)

ए) बैंक की 71वीं वार्षिक आम बैठक:-

दिनांक 28 अगस्त, 2023 को बैंक ने 1वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित की। इस कार्यक्रम में गुजरात के राज्यपाल माननीय आचार्य देवव्रत, गुजरात कृषि मंत्री माननीय राघवजीभाई हंसराजभाई पटेल और सहकारिता, नमक उद्योग, मुद्रण और स्टेशनरी तथा

प्रोटोकॉल राज्य मंत्री माननीय जगदीश विश्वकर्मा सहित कई विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे। माननीय आचार्य देवव्रत ने "प्राकृतिक खेती" पर अपने विचार साझा किए।

ए) नाबार्ड अध्यक्ष का जीएससीएआरडीबी दौरा:-

नाबार्ड अध्यक्ष श्री के.वी. शाजी ने गुजरात में नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक, महाप्रबंधक और उप महाप्रबंधक के साथ खेती बैंक का दौरा किया। खेती बैंक अध्यक्ष श्री डोलर कोटेचा ने विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक स्वागत किया।

बी) मुख्यालय में जिला प्रबंधकों की समीक्षा बैठक: -

मुख्यालय में जिला प्रबंधकों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई जिसमें प्रबंध निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस

बैठक का उद्देश्य प्रबंधकों को मार्गदर्शन प्रदान करके संगठन की चल रही प्रगति की समीक्षा करना, भविष्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में उनके प्रयासों को निर्देशित करना और यह सुनिश्चित करना था कि ये उद्देश्य समय पर पूरे हों।

9. महाराष्ट्र राज्य बलुतेदार सहकारी समिति महासंघ लिमिटेड, पुणे

महाराष्ट्र राज्य बलुतेदार सहकारी समिति महासंघ, ग्रामीण कारीगर ब्लॉक स्तरीय समितियों का शीर्ष महासंघ हैं। यह कौशल विकास कार्यशालाओं के माध्यम से ग्रामीण कारीगरों को सशक्त बनाने, विपणन सहायता और तकनीकी जानकारी प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण के तहत ग्रामीण कारीगरों के उत्थान की दिशा में काम करते हैं। 'बलुतेदार' शब्द पारंपरिक रूप से उन लोगों को संदर्भित करता है जो कृषिविदों की सेवा करते हैं और बर्तन, उपकरण और सहायक उपकरण बनाकर गाँव के विकास में योगदान देते हैं।

पहले के समय में ग्रामीण कारीगर किसानों से अनाज के बदले कृषि उपकरण बनाते थे। महासंघ ने 13 जुलाई, 2023 को महाराष्ट्र के धाराशिव (उस्मानाबाद) में मरणोपरांत अंगदान और देहदान पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। इसके साथ ही बहुउद्देशीय सहकारी समितियों और शहरी सहकारी बैंकों के अध्यक्षों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम भी आयोजित किया।

इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र राज्य के सहकारी समितियों के आयुक्त और रजिस्ट्रार श्री अनिल कनाडे, मराठवाड़ा क्षेत्र के शहरी सहकारी बैंकों के अध्यक्ष श्री प्रकाश सर्वडे, उस्मानाबाद के सहकारी समितियों के जिला उप रजिस्ट्रार श्री सुनील शिरापुरकर आदि प्रमुख अतिथियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, 19 नवंबर, 2023 को महासंघ ने सहकारी सप्ताह के उपलक्ष्य में ब्लॉक स्तरीय सहकारी समितियों के सचिवों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। पुणे चैंबर्स ऑफ कॉमर्स हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में 223 प्रतिभागियों ने भाग लिया। महाराष्ट्र राज्य सहकारी समिति आयुक्त और रजिस्ट्रार श्री अनिल कनाडे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे।

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की शासी परिषद का प्रतिवेदन

प्रिय सहकार साथियों ,

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) की शासी परिषद की ओर से मुझे वर्ष 2023-24 के लिए एनसीयूआई की वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष रखते हुए प्रसन्नता हो रही है।

एनसीयूआई इस वर्ष के दौरान भारतीय सहकारी आंदोलन की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती रही हैं । इसका मुख्य उद्देश्य सहकारी क्षेत्र को मजबूत बनाने में अपने सदस्य संगठनों को शिक्षित करना, मार्गदर्शन करना और सहायता प्रदान करना है। वर्ष 2023-24 के दौरान सहकारी विकास के विभिन्न पहलुओं से संबंधित एक संक्षिप्त रिपोर्ट इस प्रकार है:

सदस्यता:-

इस वर्ष के अंत में सहकारी आंदोलन के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल तीन सौ पाँच सहकारी संगठन एनसीयूआई के सदस्य थे।

शासी परिषद की बैठकें:-

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान शासी परिषद की कुल चार बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में एनसीयूआई के प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंधन से संबंधित मामलों और सहकारी क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। शासी परिषद ने एनसीयूआई के विकास के साथ-साथ सहकारी आंदोलन के विकास के लिए एनसीयूआई के उद्देश्यों के अनुरुप गतिविधियों को अंजाम देकर कई निर्णय लिए हैं । यहाँ यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 14 जून, 2023 को एनसीयूआई के शासी परिषद के सदस्यों के साथ बातचीत करने के लिए एनसीयूआई का दौरा किया था। माननीय मंत्री की सलाह पर एनसीयूआई ने उन जिलों में अद्वितीय सहकारी मॉडल का अनुभव करने के लिए गुजरात के बनासकांठा और पंचमहल में जीसी सदस्यों की यात्रा का आयोजन किया ।

सहकारी शिक्षा:-

वर्ष 2023-24 के दौरान राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केंद्र (एनसीसीई), नई दिल्ली ने 134 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लक्ष्य के मुकाबले 215 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इस तरह से सहकारी आंदोलन के विभिन्न क्षेत्रों से 8,646 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। इन प्रशिक्षित कुल प्रतिभागियों में से 1229 अनुसूचित जाति श्रेणी से, 670 अनुसूची जनजाति श्रेणी से, 2624 महिलाएं, 2910 ओबीसी, 3,394 'अन्य और ईडब्ल्यू' श्रेणियों से और 816 पूर्वोत्तर क्षेत्र से थे। इस वर्ष के दौरान केंद्र ने महिलाओं के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुरु किया जो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के सहयोग से दो बार आयोजित किया गया। 'सहकारी समितियों के गठन' पर युवाओं के लिए एक नया पंचवर्षीय कार्यक्रम भी शुरु किया गया जिसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली और सभी ने भरपूर सराहा।

सहकारी शिक्षा क्षेत्र परियोजनाएँ:-

वर्ष 2023-24 के दौरान पूर्वोत्तर और महिला परियोजनाओं सहित एनसीयूआई सहकारी शिक्षा क्षेत्र परियोजनाओं ने व्यापक प्रभावशाली कार्यक्रमों का आयोजन करके अपनी पहुँच का विस्तार करना जारी रखा जो सदस्यों और संभावित सदस्यों के लिए फायदेमंद थे। इसमे 2,91, 991 प्रतिभागियों के लिए 14,697 कौशल विकास कार्यक्रम

आयोजित किए गए। इस वर्ष के दौरान 25241 नए सदस्यों का नामांकन किया गया। इस वर्ष के दौरान 2761 स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया जबकि 134 समितियां पंजीकृत की गईं।

सामान्य सहकारी नीतियां:-

सामान्य सहकारी नीति (जीसीपी) विभाग ने वर्ष 2023-2024 के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें 17वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन का आयोजन, क्षेत्रीय सम्मेलन, चौधरी ब्रह्मप्रकाश स्मारक अनुसंधान छात्रवृत्ति बैठक और नई राष्ट्रीय सहयोग नीति के मसौदे पर चर्चा के लिए आयोजित बैठकें शामिल हैं। 17वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया जो कि 1-2 जुलाई 2023 को आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने की जबकि समापन समारोह में लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला और तत्कालीन माननीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में 3,500 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सहकारी कानून, नवाचार और लैंगिक समानता जैसे अन्य विषयों पर चर्चा की गई। दक्षिण क्षेत्र का क्षेत्रीय सम्मेलन अक्टूबर 2023 में हैदराबाद में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय सहकार नीति का मसौदा तैयार करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में दो बैठकें आयोजित की गईं।

अंतरराष्ट्रीय संबंध:-

अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग द्वारा नियमित आधार पर आयोजित कई प्रमुख गतिविधियों और कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया गया। 17वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया जिसमे 28 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। भारत की जी-20 की अध्यक्षता के दौरान सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के एनसीयूआई के प्रयासों को बढ़ावा मिला जहाँ इसने वैश्विक सहकारी संगठनों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग किया। एनसीयूआई ने सार्क देशों में सहकारी समितियों के बीच शासन और विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मेजबानी करने के लिए भी सहयोग किया। इस दौरान प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में कोलकाता (नवंबर 2023) में सीईओ और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए सहकारी शासन पर और नई दिल्ली (मार्च 2024) में महिला निदेशक मंडल के लिए कार्यक्रम इत्यादि शामिल थे । इसके अतिरिक्त एनसीयूआई ने सीआईसीटीएबी के सहयोग से दिनांक 18 से 21 मार्च, 2024 तक अमरेली, गुजरात में सहकारी विकास के लिए परियोजना-आधारित दृष्टिकोण पर एक सफल कार्यक्रम आयोजित किया। एनसीयूआई अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय सहकारी प्रतिनिधिमंडल ने 16वीं आईसीए-एपी क्षेत्रीय सभा और संबंधित कार्यक्रमों के साथ-साथ मनीला, फिलीपींस में एनईडीएसी आम सभा में भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया।

जनसंपर्क और प्रकाशन:-

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एनसीयूआई के जनसंपर्क विभाग ने संगठन की छवि को बढ़ाने और सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मीडिया को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विभाग द्वारा प्रमुख पहलों में नवंबर 2023 में "भारत को पाँच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और एसडीजी बनाने में सहकारी समितियों की भूमिका" नामक विषय के तहत 70वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह मनाया गया। इस सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री श्री परषोत्तम रुपाला द्वारा किया गया। सहकारिता सप्ताह के प्रमुख विषयों पर महत्वपूर्ण वेबिनार आयोजित किए गए जिसमें अमूल के प्रबंध निदेशक जयन मेहता और नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज के प्रबंध निदेशक प्रकाश नाइकनवरे जैसे प्रमुख वक्ता शामिल हुए। इसके अतिरिक्त विभाग ने जुलाई 2023 में आयोजित 17वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन जैसे प्रमुख आयोजनों के लिए प्रेस विज्ञप्तियाँ भेजीं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि थे। रेडियो प्रसारण के साथ-साथ सोशल मीडिया प्रयासों ने इन आयोजनों की पहुँच को बढ़ाया। विभाग द्वारा 'द कोऑपरेटर' पत्रिका और सहकारी सप्ताह विशेष अंक और सहकारी विषयों से जुड़े और विशेष अंक भी प्रकाशित किए गए। अन्य विशेष

प्रकाशन में भारतीय सहकारी महासम्मेलन के लिए दो सौ पृष्ठ की महत्वपूर्ण स्मारिका भी निकाली गई।

कॉप कनेक्ट विभागः-

यह विभाग विशेष रुप से स्कूल और कॉलेज के छात्रों को सहकारी दर्शन और रोजगार सृजन की इसकी क्षमता से परिचित कराने के लिए समर्पित है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान इस विभाग ने 59 कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें देश भर में 5,282 प्रतिभागी शामिल हुए। इसका प्रमुख कार्यक्रम, "सफल सहकारी व्यवसाय मॉडल", ऑनलाइन, ऑफ़लाइन और हाइब्रिड प्रारूपों में पेश किया जाता है। इसके साथ ही ड्राइंग प्रतियोगिता, वाद-विवाद और सहकारी प्रश्नोत्तरी जैसी विभिन्न प्रतिस्पर्धी गतिविधियाँ भी आयोजित की जाती हैं। इस विभाग ने 3 से 8 नवंबर, 2023 तक सहकारी मेला भी आयोजित किया जिसमें 750 से अधिक छात्र और छात्राएँ शामिल हुई। एनसीयूआई इनक्यूबेशन सेंटर और इफको जैसी सफल सहकारी समितियों के शैक्षिक दौरे उन छात्रों के काफी कारगर सिद्ध होते हैं।

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेसः-

एनसीडीबी विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सहकारिता मंत्रालय के साथ मिलकर राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) पोर्टल के विकास और रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विभाग की प्रमुख गतिविधियों में दिनांक 8 मार्च, 2024 को एनसीडी पोर्टल और रिपोर्ट को सफलतापूर्वक जारी करना था। इस कार्यक्रम में लगभग 1,200 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। विभाग ने 7.05 लाख से अधिक सहकारी समितियों के लिए डेटा संग्रह किया, लेन-देन डेटा संकलित किया और सहकारी क्षेत्र के बारे में संसद में पुछे गए प्रश्नो के जवाब भी भेजे। इसके अतिरिक्त इसने 17 वें आईसीसी में विभिन्न सहकारी संस्थानों की भागीदारी का समन्वय किया और एनसीयूआई वेबसाइट पर भारतीय सहकारी आंदोलन के सांख्यिकीय प्रोफाइल अपलोड किए जिससे सहकारी डेटा की पारदर्शिता और पहुंच सुनिश्चित हुई हैं।

सहकारी उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ एवं इनक्यूबेशन केंद्रः-

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सहकारी और उद्यम विकास केंद्र (सीईडीसी) ने स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) संघों को सहकारी समितियों के रुप में पंजीकृत करने के लिए राष्ट्रीय परामर्श की सुविधा प्रदान की और उभरते क्षेत्रों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की। विभाग की उल्लेखनीय घटनाओं में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एनसीयूआई हाट ई-कॉमर्स पोर्टल का शुभारंभ करना था जिसका उद्देश्य सहकारी उत्पादों का विपणन करना और लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को बढ़ाने के लिए एथिक्स ग्रुप जैसे संगठनों के साथ साझेदारी करना था। इसके अतिरिक्त एनसीयूआई इनक्यूबेशन सेंटर ने उद्यमिता प्रशिक्षण के माध्यम से दिल्ली में पाँच हजार से अधिक महिलाओं को सशक्त बनाया। नोएडा में कौशल विकास केंद्र ने प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए कॉर्पोरेट भागीदारों के साथ सहयोग किया। जीआईजेड इंडिया और एचसीएल फाउंडेशन जैसे संस्थानों के साथ कई समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

राष्ट्रीय सहकारी संसाधन केंद्र और सहकारी विस्तार एवं सलाहकार सेवा विभागः-

वित्तीय वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय सहकारी संसाधन केंद्र (एनसीआरसी) ने सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ाने पर केंद्रित महत्वपूर्ण पहल की। इस दौरान प्रमुख गतिविधियों में सहकारी समितियों के मूल सिद्धांतों और क्षेत्रीय पहलुओं पर व्यापक प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास, सार्वजनिक डोमेन में दस मॉड्यूल जारी करना शामिल है जिनमें से कई पहले से ही सहकारी विस्तार और सलाहकार सेवा शिक्षण प्रबंधन प्रणाली (सीईएएस-एलएमएस) पोर्टल के माध्यम से सभी हेतु उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र ने सहकारिता मंत्रालय के लिए अध्ययन किए जैसे कि सहकारी समितियों के लिए सरकारी योजनाओं का एक संग्रह और सदस्यों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए

जूनियर सहकारी प्रशिक्षण केंद्रों (जेसीटीसी) का गहन मूल्यांकन इत्यादि। इस केंद्र ने नीति संक्षिप्त विवरण, शोध लेख भी प्रकाशित किए और भारत में सहकारी समितियों की स्थिति पर एक विशेष चर्चा की मेजबानी की जिससे प्रमुख रूप से हितधारकों के बीच संवाद को बढ़ावा मिला।

सहकारी विस्तार और परामर्श सेवाएं (सीईएएस) विभाग ने सहकारी विस्तार संस्थानों को मजबूत करने और सहकारी जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। दिनांक 01 जुलाई, 2023 को 17वें आईसीसी के दौरान माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए सीईएएस-एलएमएस पोर्टल ने काफी लोगों को आकर्षित किया है। इस कार्यक्रम में हजारों लोगों, सहकारी सदस्यों और नेताओं ने शिक्षण हेतु पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया है। इस विभाग ने युवाओं को जोड़ने के लिए "कॉप्स4जेनेक्स्ट नॉलेज सीरीज़" और कृषि ऋण समितियों और सहकारी आवास प्रबंधन जैसे विषयों को कवर करने वाले क्षेत्र-विशिष्ट वेबिनार सहित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक और झारखंड में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के परिवर्तन के लिए प्रशिक्षकों (टीओटी) हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिससे संकाय और प्रशिक्षकों को अपने क्षेत्रों में शैक्षिक पहल का नेतृत्व करने के लिए सशक्त बनाया गया।

स्वीकृतियाँ:-

हम माननीय केंद्रीय सहकारिता मंत्री, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री, सहकारिता मंत्रालय के अधिकारियों को उनके सहयोग और समर्थन के लिए हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। हम एनसीडीसी प्रतिनिधियों, आईसीए, आईआरयू, आईएलओ, एनईडीएसी और एफएओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों, विभिन्न मंत्रालयों, संसद सदस्यों, राज्य विधानसभाओं और ऐसे सभी प्रमुख व्यक्तियों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने एनसीयूआई के कामकाज में गहरी रुचि ली। एनसीयूआई के सदस्य संस्थानों, विभिन्न राज्यों के आरसीएस, राज्य सहकारी संघों और एनसीयूआई के अन्य घटक सदस्यों को भी संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनके बहुमूल्य समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। वित्त वर्ष 2023- 2024 में एनसीयूआई के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए एनसीयूआई के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं।

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ

3, सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-40793299,41811154, 46062727
ई-मेल : mailncui@india.coop वेबसाइट : www.ncui.coop